R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• दागी नहीं मप्र के ब्यूरोक्रेट्स • बीहड़ में डकैतों की आहट

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

चंद दिनों के सत्र में गढ़े नए प्रतिमान

वर्ष 19, अंक-13 1 से 15 अप्रैल 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

अग्निपथ पर देश...

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

लापरवाही

9 | सोम की शराब अमानक

मप्र में अवैध और अमानक शराब ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। अवैध और अमानक शराब को लेकर प्रदेश की राजनीति का पारा भी गर्म है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती शराबबंदी...

राजपथ

10-11 | चंद दिनों के सत्र में गढ़े नए प्रतिमान

वैसे तो कोरोनावायरस के आगमन के साथ ही संसद एवं देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के सुचारू संचालन पर एक तरह का ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन मप्र की 15वीं विधानसभा ने चंद दिनों के सत्र में कई नए प्रतिमान...

भर्राशाही

12 | अधर में प्रोजेक्ट

मप्र की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों के साये में रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी साइट पर हजारों पेड़ों को गुपचुप तरीके से काटने का मामला हो या फिर प्रोजेक्ट दस्तावेजों में ग्रीन बेल्ट का दायरा कम करने का, इसको...

इंदौर

20 | 7 हजार करोड़ की जमीनें सरेंडर

मप्र में इन दिनों भूमाफिया के खिलाफ दनादन कार्रवाई हो रही है। सबसे अधिक कार्रवाई इंदौर में हो रही है। प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ 18 फरवरी को सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। इंदौर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3,250 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई थी।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में सत्ता किसके हाथ लगेगी यह 2 मई को ही स्पष्ट होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बीच हो रहे चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ ही जनता के लिए भी अग्निपथ से कम नहीं हैं। एक तरफ जहां देशभर में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में कोरोना गाइडलाइन पूरी तरह दरकिनार है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या कोरोना चुनावी नारों से डर रहा है?

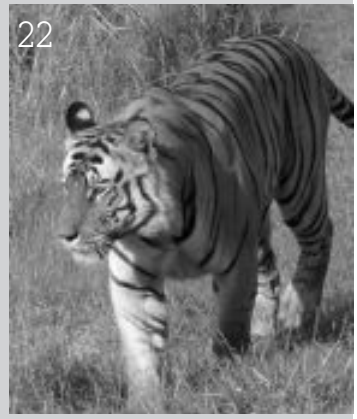

राजनीति

30-31 | अपनी जमीन छोड़ती कांग्रेस

राहुल गांधी पर लगता है लॉकडॉउन का असर अब हो रहा है। हाल फिलहाल राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वे बातें लंबे आत्ममंथन का नतीजा लगती हैं। हालांकि, ऐसा ठीक-ठाक समझने के लिए अगले साल होने जा रहे पंजाब चुनाव तक इंतजार करना पड़ सकता है।

राजस्थान

35 | 5 करोड़ की विधायक निधि

राजस्थान में विधायकों के कद के साथ अपने क्षेत्र में विकास के लिए खर्च करने की उनकी क्षमता अब और बढ़ गई है। अपने क्षेत्र में विधायक के विवेक से विकास कार्य कराने के लिए विधायकों का बजट दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब तक सवा दो करोड़ रुपए सालाना...

बिहार

38 | एक साथ आए दुश्मन नंबर वन

कई दशकों से बिहार की राजनीति अनवरत रूप से जातिगत समीकरणों पर ही चलती चली आ रही है। जो इन समीकरणों को जितना अधिक साध सका है, सत्ता की कुर्सी पर उसका अधिकार उतना ही प्रबल होता है। बिहार की राजनीति में जनता दल...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

ऐ सियासत, तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया...

किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि...

ऐ सियासत, तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया।
गरीबों को गरीब अमीरों को मालामाल कर दिया।।

दरअसल, देश में आजादी के बाद से ही समानता की बात हो रही है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज भी बहुसंख्यक आबादी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हालाकान हो रही है और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मालामाल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक वर्ग है राजनेताओं का। आज जहां देश में बड़ी जनसंख्या रोजी-रोटी के लिए मुहाल है, वहीं माननीयों के लिए आए दिन सुविधाओं की भरमार होती रहती है। वर्तमान सांसद-विधायकों की कौन कहे, पूर्व सांसद-विधायकों के लिए भी लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हाल ही में मप्र सरकार ने पूर्व विधायकों के लिए ट्रेन के एसी फर्स्ट कोच में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद और विधायकों के लिए पहले से ही पेंशन सहित अन्य सुविधाओं की भरमार है। उसके बाद भी सरकारें समय-समय पर उनकी सुख-सुविधाओं का ख्याल रखती रहती हैं। आखिर हर कोई विधायक बनने के लिए इतना उतावला क्यों है। बेशक विधायक स्वयं को जनसेवक कहलाते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि आप नेता को एक बार वोट देते हैं, विधायक बनने के बाद वे जीवनभर नोट लेते हैं। वेतन के रूप में, यात्रा भत्ते के रूप में, चिकित्सा भत्ते के रूप में, जब विधायक नहीं भी रहें तो पेंशन के रूप में और यदि मृत्यु हो जाए तो उनके पति या पत्नी को जीवनभर पेंशन की पात्रता रहती है। प्रजातंत्र में विधायक चुनने की परंपरा इसलिए शुरू की गई थी कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अब ये मायने बदल गए हैं। विधायक बनना स्टेटस सिंबल बन गया है। विधायक बनने के बाद वैधानिक और अवैधानिक कई शक्तियां इनके हाथों में आ जाती हैं। यह व्यवसाय दिन दूनी, रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अब विधायक बनने के पीछे जनसेवा की भावना तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। वहीं विधायकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से एक राय होकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा लिए जाते हैं। विधायक बनने के साथ ही नेताजी को जो भी वैधानिक सुविधाएं मिलती हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अपवादों को छोड़कर वे अवैधानिक रूप से इतनी काली कमाई करते हैं कि वह रातोंरात करोड़पति बन जाते हैं। आज जहां विधायकों में अपने रिश्तेदारों के नाम से रेत के ठेके, सड़क निर्माण के ठेके, शराब के ठेके आदि लेने का रिवाज चल रहा है जो विधायक ऐसा नहीं करता है, उसकी गिनती भूखे में या पिछड़ेपन में होती है। देश में कर्मचारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है। लेकिन यह नियम सांसद और विधायक पर नहीं लागू होता है। ऐसे में अगर कोई एक बार विधायक बन जाए और उसके बाद सांसद बन जाए तो उसे विधायक की पेंशन के साथ-साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता मिलता है। मप्र के कई दिग्गज नेताओं जैसे- पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और विक्रम वर्मा को भी इसी तरह सांसद का वेतन और विधायक की पेंशन मिल रही है। ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि जनता की कमाई पर टैक्स लगाकर माननीय किस तरह अपनी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। जब माननीय सांसद-विधायक रहते हैं तब तो उन्हें सुविधाएं मिलती ही है, लेकिन उनके नाम के आगे पूर्व लगने पर भी कई तरह की ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो सेना के जवानों तक को नहीं मिलती हैं। आखिर यह विसंगति क्यों?

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 13, पृष्ठ-48, 1 से 15 अप्रैल, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

कैसे आत्मनिर्भर होगा प्रदेश

मप्र पर कर्ज का भार है। जब हम गले-गले कर्ज में डूबे हों, तो विकास योजनाएं कैसे चलेंगी, कैसे मप्र आत्मनिर्भर बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है। सरकार की माली हालत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, कि वह किसानों की फसल बीमा का भुगतान नहीं कर सकी है।

● **निदा खान,** भोपाल (म.प्र.)

कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मप्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षक नहीं हैं तो कहीं शौचालय व बिजली कनेक्शन का अभाव है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मुश्किल है।

● **किशन श्रीवास्तव,** इंदौर (म.प्र.)

समाज के कारण बची संस्कृति

यह सच है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के अनेक शहरों के नाम बदलकर इतिहास के साथ छेड़खानी की। इसके साथ उन्होंने यहां की संस्कृति और परंपराओं को भी प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की। भारतीय समाज की जीवटता के कारण संस्कृति का अस्तित्व बचा रहा।

● **संतोष कुमार,** सीहोर (म.प्र.)

ममता की कुर्सी मुश्किल में

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के सभी शीर्ष नेता इन दिनों सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर ही दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जिस तरह राज्य की कुल 42 में 18 सीटें जीतकर भाजपा ने न सिर्फ सबको चौंकाया बल्कि ममता बनर्जी के किले को भी हिला दिया, उससे राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है। उसके बाद से ही एक-एक करके कई तृणमूल नेता पाला बदलकर भाजपा की छतरी के नीचे जा रहे हैं। अगर भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो ममता का कुर्सी पर टिके रहना मुश्किल है।

● **विनोद मेवाड़ा,** गुना (म.प्र.)

अमीर और अमीर...गरीब और गरीब

दुनिया अभी भी महामारी की चपेट में है, अभी तक किसी देश की ग्रोथ में बढ़त दर्ज नहीं हुई है और विश्व अर्थव्यवस्था में इतनी विषमता की आशंका जताई जा रही है, जितनी पहले कभी नहीं की गई। इसके साथ ही 2019 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट के संकेत हैं। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक, महामारी के चलते दुनियाभर में इस साल के अंत तक लगभग 15 करोड़ लोग महागरीब की श्रेणी में जुड़ जाएंगे, यह पूरी तरह तय है। महामारी के दौरान भी बिना किसी अपवाद के अरबपतियों का उभरना जारी है।

● **सुभाष पटेल,** शिवपुरी (म.प्र.)

घर-घर पहुंचेगा जल

देश के 7 बड़े राज्यों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मप्र अग्रणी 3 राज्यों में शामिल है। मप्र के 51 हजार से अधिक गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम मिशन स्तर पर चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि 3 साल में प्रदेश के सभी गांवों के सभी घरों में नल से जल पहुंच जाए। प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन का लक्ष्य योजनाबद्ध और सामयिक अनुपात में निर्धारित किया गया है।

● **सीमा सूर्यवंशी,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

नीतीश का मौन

बिहार में राजनीतिक कटुता ज्यादा ही बढ़ गई है। राजद के विधायकों और समर्थकों पर विधानसभा के भीतर और बाहर हुए बल प्रयोग से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। नीतीश कुमार को चचा कहने वाले तेजस्वी चिढ़कर कुर्सी कुमार कहने लगे थे। चुभने वाला भले हो पर यह संबोधन असंसदीय कतई नहीं था। अब तो उन्होंने नीतीश को निर्लज्ज कुमार कह डाला है। भीष्म प्रतिज्ञा भी कर डाली है कि जब तक राजद के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होगी और नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे, राजद के सभी विधायक विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। घटना को लेकर राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार की खासी आलोचना कर डाली। पर तेजस्वी ने तो उन्हें पहले निर्लज्ज कुमार कहा, फिर सी ग्रेड की पार्टी का सी ग्रेड नेता बताया। सी ग्रेड यहां द्विअर्थी ठहरा। सी आता है ए और बी के बाद। यानी तीसरे नंबर पर। जनता दल (एकी) संख्या बल के हिसाब से बिहार में इस समय तीसरे नंबर की ही पार्टी ठहरी। पर सी ग्रेड के नेता कहना अटपटा जरूर है। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी ने यह कहा कि जद (एकी) के गुंडे जब राजद की महिलाओं का चीरहरण कर रहे थे तो नीतीश इंद्रिय रस प्राप्त कर रहे थे। इतना होने के बाद भी नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं।

मझधार में भाजपा

पंजाब विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। किसान आंदोलन के बाद लगता है कि भाजपा ने पंजाब की अहमियत घटा दी है। अपना खुद का तो वैसे भी इस सूबे में कभी ज्यादा वजूद रहा नहीं भाजपा का। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से तो भाजपा गठबंधन करेगी नहीं। आम आदमी पार्टी ने तो पिछले चुनाव में अकाली दल और भाजपा दोनों के गठबंधन को ही तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। सियासी सर्वेक्षण अब भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं आंक रहे पर केजरीवाल तो अपनी गोटियां फिट करने में लगे ही हैं। कांग्रेस में अभी तय नहीं है कि चुनाव कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा या कोई और नेता होगा। कैप्टन अब 79 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से अभी तक कैप्टन की अदावत दूर नहीं हो पाई है। भाजपा दूसरे दलों की टोह ले रही है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और सूबे में मंत्री रह चुकी लक्ष्मीकांता चावला की अमृतसर में अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। चावला हालांकि काफी समय से अपनी पार्टी और केंद्र की सरकार दोनों की ही मुखर आलोचक बनी हैं।

राजनीति के अभिमन्यु

त्रिवेंद्र सिंह रावत तो बगावत पर आमादा लगते हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। उनसे अनुशासन की अपेक्षा अनुचित नहीं। मुख्यमंत्री पद से खुद को हटाया जाना उन्हें ज्यादा ही अखर रहा है। चार साल बाद अचानक किसी को हटाया जाए तो अखरना यूं तो स्वाभाविक है, लेकिन इस कदर बागी तेवर तो न नित्यानंद स्वामी ने दिखाए थे और न भुवनचंद्र खंडूरी ने। जब इस्तीफा हुआ था, बागी तेवर तभी दिखने लगे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के। पत्रकारों ने हटाए जाने का कारण पूछा था तो तपाक से नाराजगी जुबान पर आ गई थी। कहा था कि हटाने की वजह दिल्ली वाले बताएंगे। दिल्ली वाले यानी आलाकमान। अब एक पखवाड़े बाद अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला गए तो होली मिलन के एक कार्यक्रम में खुद को पद से हटाने की तुलना महाभारत के अभिमन्यु वध से कर डाली। फरमाया कि बेटे की मौत के बाद द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे। उसने पांडवों से अभिमन्यु के छल से हुए वध का बदला लेने की बात कही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रसंग के बहाने अपने समर्थकों को पार्टी आलाकमान से बदला लेने के लिए ही तो उकसाया। आवेश में अभिमन्यु को द्रौपदी का पुत्र भी बता दिया। जबकि अभिमन्यु थे सुभद्रा के बेटे।

हेमंत की बढ़ी हैसियत

असम में भाजपा अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है। भाजपा की इस लड़ाई से कांग्रेस खुश है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बगावत का फायदा भाजपा को मिला था। कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा सरमा सहित सैकड़ों समर्थक भाजपा में शामिल हो गए थे। सरमा लंबे अर्से से गोगोई के स्थान पर खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। जब कांग्रेस नेतृत्व तैयार होता नजर नहीं आया तो उन्होंने दल ही बदल डाला। अब खबर है कि हेमंत बिस्वा सरमा ने भाजपा आलाकमान पर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए दबाव की राजनीति शुरू कर डाली है। यही कारण है कि भाजपा इन चुनावों में सोनोवाल को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए बगैर मैदान में हैं। खबर है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री सोनोवाल के समर्थकों में पार्टी आलाकमान के इस फैसले के चलते खासी नाराजगी है। खबर यह भी है कि हेमंत समर्थक अभी से प्रचार करने में जुट गए हैं कि पार्टी की अगली सरकार उनके नेता के ही नेतृत्व में गठित होगी। भाजपा की इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आने लगा है।

गडकरी का कुछ नहीं बिगड़ेगा

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर स्वीडन के अखबारों में कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके चलते उनके विरोधियों की बांछें खिल उठी हैं। स्वीडन की एक वाहन निर्माता कंपनी 'स्केनिया' के ऑडिट के दौरान यह बात सामने आई है कि इस कंपनी ने गडकरी को उनकी पुत्री के विवाह से ठीक पहले एक लक्जरी बस उपहार में दी थी। इससे पहले 2013 में उन्हें बतौर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा टर्म उनकी कंपनी 'पूर्ति' से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के चलते नहीं मिल पाया था। पुणे के आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश शेट्टी की हत्या मामले की आंच भी गड़करी तक पहुंची थी लेकिन हर बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उनके आगे ढाल बन खड़ा रहा। खबर है कि इस बार भी गडकरी विरोधियों का प्रयास उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के लिए शुरू तो हो चला है लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के आशीर्वाद के चलते उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। गडकरी भी पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं।

क्योंकि कृषि को लाभ का धंधा बनाना है...

केंद्र और राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मप्र में मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार तन, मन और धन से जुटी हुई है। ऐसे में सरकार की मंशा है कि इस विभाग में पूर्व में काम कर चुके अधिकारी को इसके समकक्ष के विभाग में लाया जाए। ये साहब हैं 1990 बैच के आईएएस अधिकारी। साहब पूर्व में कृषि विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ख्यात रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में खेती-किसानी के उत्थान के लिए खूब काम किया है। अब सरकार अपने मिशन को पूरा करने के लिए साहब की सेवाएं उनके पूर्व विभाग के समकक्ष वाले विभाग में लेना चाहती है। वैसे माना जाता है कि साहब की रूचि भी खेती-किसानी में खूब है। यही नहीं वर्तमान में साहब जिस विभाग में पदस्थ हैं, उस विभाग में उनका मन नहीं लग रहा है। साहब भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें ऐसे विभाग में पदस्थ किया जाए, जहां चैलेंज हो। वर्तमान में साहब टोपी और डंडे वाले विभाग में उच्च पद पर पदस्थ हैं। बताया जाता है कि साहब को डंडा बिलकुल नहीं भा रहा है। ऐसे में सरकार भी उनकी मंशा को भांप गई है और हो सकता है कि जल्द ही साहब को उनके पसंदीदा विभाग की जिम्मेदारी मिल जाए। अगर साहब को कृषि विभाग के समकक्ष वाले विभाग में पदस्थ किया जाता है तो कृषि को लाभ का धंधा बनाने के मिशन में कामयाबी हासिल हो सकती है।

चौथी पारी में उपेक्षित

अपनी सूझबूझ और रणनीति के कारण कभी सरकार की आंख और कान रहे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन दिनों उपेक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि साहब के पास महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। लेकिन उन्हें वह महत्व नहीं मिल पा रहा है जो सरकार के मुखिया के पूर्ववर्ती तीन कार्यकाल में मिला है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी ने सरकार को पूर्ववर्ती शासनकाल में कई संकटों से निकाला है। जब भी सरकार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरी है, साहब ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से उसे उबारा है। लेकिन सरकार के मुखिया के तीसरे कार्यकाल के उत्तरार्द्ध में साहब को उपेक्षित करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अब तक जारी है। लेकिन साहब ने कभी भी अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं होने दिया। सरकार ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी, उन्होंने उसका ईमानदारी से निर्वहन किया। आज भी साहब के पास प्रदेश के बड़े विभाग की जिम्मेदारी है और कोरोना संक्रमण के दौरान इस विभाग ने लाखों लोगों को रोजगार देकर महामारी के दंश से उन्हें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब साहब इसी माह रिटायर होने वाले हैं। साहब भले ही रिटायर हो जाएं लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता और शासन-प्रशासन के प्रति उनका समर्पण कभी रिटायर नहीं होगा।

मंत्री का हस्तक्षेप

अपनी ईमानदार और स्टेट फारवर्ड छवि के लिए ख्यात 1987 बैच के एक आईपीएस अधिकारी पसोपेश में नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है विभाग के हर छोटे-बड़े काम में मंत्री का हस्तक्षेप। दरअसल, साहब के बारे में यह ख्यात है कि वह जिस भी विभाग में पदस्थ रहे हैं, उन्होंने उस विभाग का कायाकल्प कर दिया है। साहब वर्तमान में जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उस विभाग की मंत्री एक महिला हैं। महिला मंत्री रोबिले रहन-सहन और अंदाज वाली हैं। उनकी कोशिश रहती है कि उनके कहे बिना विभाग में कोई पत्ता भी ना हिले। वहीं साहब की कोशिश है कि विभाग में हर काम निर्विवादित और निर्विकार रूप से आगे बढ़े। पात्र व्यक्तियों को उचित स्थान और सम्मान मिले। लेकिन मंत्री को यह सब नहीं भा रहा है। वे विभागीय तबादलों से लेकर छोटे-बड़े सभी तरह के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि विभाग में काम प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि साहब की ईमानदार और स्टेट फारवर्ड छवि मंत्रीजी को बिलकुल नहीं भा रही है। इस कारण दोनों के बीच अनबन की स्थिति निर्मित हो गई है। जहां साहब हमेशा इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मंत्री को हर अवसर पर महत्व दिया जाए, वहीं मंत्री अपनी राजसी मानसिकता के कारण साहब को भाव नहीं दे रही हैं। दरअसल, मंत्री चाहती हैं कि विभाग में केवल उनकी चले।

मंत्री की मनमर्जी

प्रदेश की एक महिला मंत्री और उनके पीए की मनमर्जी से विभाग के अधिकारियों के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। दरअसल, मंत्री और उनके पीए केवल उन्हीं लोगों को भाव दे रहे हैं, जो कमाऊ हैं। आलम यह है कि मंत्री जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाती हैं तब भी उनकी मनमर्जी कम होने का नाम नहीं लेती है। क्षेत्र के लोग मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं तो उनके पीए यह कहकर मना कर देते हैं कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री और पीए की हरकत से लोग परेशान हो उठे हैं। एक तरफ मंत्री का भाई क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री लोगों से मिल नहीं रही हैं। ऐसे में लोग अभी से कहने लगे हैं कि यह मैडम की अंतिम पारी है। देखते हैं वे अगली बार हमसे वोट कैसे लेती हैं। गौरतलब है कि मैडम को बड़ी मुश्किल से इस बार सत्ता सुख मिला है। सत्ता सुख मिलते ही वे जनता से दूर हो गई हैं। भोपाल में तो वे किसी से मिलती ही नहीं हैं। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने लोगों से दूरी बना ली है। वे आरामगाह में पड़ी रहती हैं, जिससे जनता नाखुश है।

मंत्री-ठेकेदार की दोस्ती

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक मंत्री और एक ठेकेदार की दोस्ती चर्चा में है। आदिवासी जिले से आने वाले माननीय पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्रीजी सीधे-साधे और सरल स्वभाव के हैं। लेकिन उन्हें इन दिनों इंदौरी हवा भा रही है। इसी हवा के कारण इन दिनों उनकी एक ठेकेदार से दोस्ती गहरा गई है। जानकारों का कहना है कि माननीय मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें अभी वह दांवपेंच बिल्कुल भी नहीं आता है जो एक मंत्री के लिए जरूरी होता है। ऐसे में मंत्रीजी के शुभचिंतकों को यह चिंता सता रही है कि कहीं वे किसी जंजाल में न फंस जाए। क्योंकि किसी मंत्री और ठेकेदार में दोस्ती बेवजह तो होती नहीं है। मंत्रीजी के करीबियों को इस बात का डर है कि ठेकेदार की दोस्ती मंत्रीजी को कहीं भारी न पड़ जाए। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने मंत्रीजी को इस दोस्ती को लेकर सचेत रहने को भी कहा है लेकिन मंत्रीजी दोस्ती के रंग में इस कदर रंगे हुए हैं कि फिलहाल उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा है।

भाजपा में कुछ ही लोगों को बोलने की आजादी है। भाजपा के कई सांसदों ने मुझे बताया है कि वे संसद में खुली बहस नहीं कर सकते। उन्हें बताया जाता है कि क्या कहना है। इसलिए भाजपा के सांसदों में अजब सी घुटन देखी जा सकती है।

● **राहुल गांधी**

कोई भी साजिश मुझे राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से नहीं रोक सकती है और मैं भाजपा के खिलाफ तब तक संघर्ष जारी रखूंगी जब तक मेरे दिल की धड़कनें चलती रहेंगी और उनका कंठ काम करता रहेगा। भाजपा दिल्ली से नेताओं को लाकर भी बंगाल के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती है। 2 मई को भाजपा का जोश शांत हो जाएगा।

● **ममता बनर्जी**

आज भारतीय क्रिकेट टीम की बेंच भी कई देशों की टीमों से मजबूत है। जहां तक हार-जीत का सवाल है, तो वह खेल का हिस्सा है। लोकेश राहुल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो हम बता दें कि वे हमारे चैंपियन प्लेयर हैं और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते रहेंगे। टीम में कई ऐसे प्लेयर हैं, जिनकी प्रतिभा अभी उभारनी है।

● **विराट कोहली**

लोकतांत्रिक पकड़ मजबूत करना और क्षेत्र का आर्थिक स्तर फिर से उठाना, यही हमारा फोकस है। मैं तमिलनाडु में गरीबी रेखा नहीं बल्कि समृद्धि रेखा पर ध्यान दूंगा। इस बार तमिलनाडु में जनता कुछ अलग करने के मूड में है। इस कारण मैं भी चुनाव मैदान में हूं।

● **कमल हासन**

मेरी राय में ओटीटी प्लेटफार्म पर सेंसर लगाना बहुत जरूरी है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आजकल बच्चे भी मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं, उनको भी ओटीटी का कंटेंट आसानी से मिल जाता है। ऐसे में कंटेंट में फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। आजकल कई वेबसीरीज ऐसी बन रही हैं, जिनमें ऐसे कंटेंट रहते हैं, जो बच्चों के देखने लायक नहीं होते हैं। जिस तरह फिल्मों पर सेंसर रहता है, उसी तरह ओटीटी प्लेटफार्म पर भी सेंसर की जरूरत है। सेंसर होने से वेबसीरीज में परोसा जाने वाला सेक्स या तो बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा।

● **दिगंगना सूर्यवंशी**

वाक्युद्ध

5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के छोटे-बड़े नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बांग्लादेश में उन्होंने मतुआ समाज के बीच जाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन जनता उन्हें इसका सबक सिखाएगी। 2 मई को यह दिख जाएगा।

● **रणदीप सुरजेवाला**

कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चुनाव आयोग नाम की एक संस्था है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वह वहां शिकायत करे। दरअसल, कांग्रेस ने अपना विकास छोड़कर किसी और का विकास नहीं किया है। इसलिए आज जब नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस सहम जाती है।

● **संबित पात्रा**

सोम की शराब अमानक

मप्र में अवैध और अमानक शराब ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। अवैध और अमानक शराब को लेकर प्रदेश की राजनीति का पारा भी गर्म है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती शराबबंदी की आवाज उठा रही हैं, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सरकार के संरक्षण में अवैध और अमानक शराब का धंधा चल रहा है। उधर, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने बताया है कि प्रदेश में अवैध और अमानक शराब के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। प्रदेश में शराब दुकानों और निर्माण कंपनियों के यहां शराब जब्त कर उनकी जांच कराई गई तो सबसे अधिक सोम डिस्टलरी की शराब अमानक मिली।

दरअसल, कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी से सवाल किया था कि क्या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं नियम-2011 के अंतर्गत शराब की सैम्पलिंग की जाती है। यदि हां तो इंदौर एवं भोपाल शहर में 1 अप्रैल 2020 से 15 फरवरी 2021 की अवधि में किस-किस ब्रांड या डिस्टलरी की शराब के सैम्पलिंग कर जांच हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन की प्रयोगशाला में भेजा गया है। क्या प्रदेश में मिलावटी एवं जहरीली शराब पीने से मुरैना, उज्जैन, बड़वानी एवं खरगोन जिलों में लोगों की मौतें हुई हैं। इन सवालों के जवाब में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में जितने शराब की सैम्पलिंग की गई उनमें सोम की शराब अमानक पाई गई।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग की तरह शराब की भी सैम्पलिंग होती है। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कुल 84 नमूने शराब के जांच हेतु लिए गए, जिनमें 54 नमूने मानक एवं 18 नमूने फेल हुए। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सोम डिस्टलरी प्रा.लि. सेहतगंज जिला-रायसेन में 2 मई 2019 को 9 सैम्पल लिए गए इनमें 7 सैम्पल मिथ्याछाप मिले, जिनमें ब्लूचिप जिन ऑरेंज टेंगो, ब्लू चिप सादा, लिजेंट प्रीमियम व्हिस्की, देशी मदिरा प्लेन, व्हाईट बॉक्स वोटका एप्पल फ्लेवर, देशी मदिरा, व्हाईट बॉक्स वोटका औरेंज फ्लेवर शामिल हैं। इस मामले में अभी प्रकरण विवेचना के अधीन है। इनके अलावा धार में विदेशी शराब दुकान से बॉम्बे स्पेशल व्हिस्की का सैम्पल मिथ्याछाप मिला। वहीं धार में भारत ढाबा से जब्प देशी मदिरा, इंदौर के आलोक दीप इंटरटेनमेंट प्रा.लि. से जब्त पावरफुल बीयर, के साथ ही अलीराजपुर के 8 सैम्पल मिथ्याछाप निकले। इन मामलों में प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं। ये मामले बताते हैं कि प्रदेश में किस तरह अमानक शराब की बिक्री जोरों पर है।

प्रदेश में अवैध और अमानक शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन अंकुश नहीं लग पाया है। इस कारण जहरीली शराब के सेवन से लोगों की जान जा रही है। हालांकि प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के मामले में सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी दी है, उसके अनुसार उज्जैन में 14 अक्टूबर 2020 की रात को 12 लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि जहरीला रसायन पीने से हुई थी। वहीं बड़वानी जिले में सितंबर में हाथ भट्टी शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसकी जांच पुलिस विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर की जा रही है। मृत्यों के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं मुरैना जिले में 11 जनवरी 2021 को जहरीली शराब की घटित घटना में 24 लोगों की मृत्यु हुई थी। उक्त घटना के पश्चात देशी मदिरा दुकान छैरा, बागचीनी, सुमावली से देशी के सैम्पल लेकर उसके रसायनिक प्रशिक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गए थे। प्राप्त जांच में उक्त मदिरा मानव सेवन के उपयुक्त पाई गई। खरगोन जिले के मिलावटी जहरीली शराब पीने से कोई मौत होने संबंधी प्रकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुरैना और खरगोन में लोगों की मौत किस कारण हुई थी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगातार डिस्टलरियों में निर्मित मदिरा के सैम्पल लेकर उनकी जांच कराई जाती है। उधर, ध्यानाकर्षण में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आबकारी विभाग की मिलीभगत से अवैध और अमानक शराब का धंधा जोरों पर है।

● **सुनील सिंह**

अवैध शराब पर चुप्पी क्यों?

विधानसभा में अवैध शराब के मामले को उठाकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार के मंत्री शराब को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। गृहमंत्री कहते हैं कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई लेकिन अवैध शराब तो बिक रही है उस पर जवाब क्यों नहीं देते कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। कांग्रेस का कहना है कि माना शराब जहरीली नहीं थी, लेकिन छतरपुर और सिवनी की घटनाएं बताती हैं कि प्रदेश में अवैध और अमानक शराब धड़ल्ले से बिक रही है। जब प्रदेश में शराब बनाने पर नकेल कसी गई तो उप्र से शराब की तस्करी शुरू हो गई। न शराब पीने वाले मानते हैं और न शराब बेचने वाले। तो क्या प्रदेश में कभी शराबबंदी मुमकिन है। अगर है तो उसका रास्ता क्या है और अगर मुमकिन नहीं है तो क्या नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए नशामुक्ति करने जैसी बयानबाजी करते हैं। इसका कोई ठोस रास्ता निकालने की जरूरत है वरना इस तरह से शराब से होने वाली मौतें बढ़ती जाएंगी। उधर, भाजपा नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी के लिए लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। उमा भारती के दबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही अन्य भाजपा नेता भी शराबबंदी की बात तो खूब कह रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद प्रदेश में अवैध और अमानक शराब का धंधा जोरों पर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अवैध शराब पर गोल-मटोल जवाब देकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है।

कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण करीब एक साल बाद मप्र विधानसभा का सत्र सुचारु रुप से चला। हालांकि यह बजट सत्र भी कोरोना के कारण 13 दिन ही चल सका, लेकिन इन चंद दिनों में सरकार ने नए प्रतिमान गढ़ दिए। सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के बावजूद सत्तापक्ष ने सभी आवश्यक कार्य समयसीमा में पूरी कर लिए। वहीं सभी विधेयक भी पारित करवाए गए।

चंद दिनों के सत्र में गढ़े नए प्रतिमान

वैसे तो कोरोनावायरस के आगमन के साथ ही संसद एवं देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के सुचारू संचालन पर एक तरह का ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन मप्र की 15वीं विधानसभा ने चंद दिनों के सत्र में कई नए प्रतिमान गढ़ दिए। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 13 दिन में ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन 2021-22 का बजट और सभी विधेयकों को पारित कर दिया गया। बजट पारित करने से पहले विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मप्र विनियोग विधेयक 2021 और वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई। सरकार ने 2 मार्च को 2.41 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया था। बता दें कि बजट सत्र 26 मार्च तक होने की अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन कोरोना के कारण उसे पहले ही स्थगित करना पड़ा।

विधानसभा का बजट सत्र जितने दिन भी चला उतने दिन सदन में सारे काम निपटाए गए। विपक्ष के तानों के बीच सरकार ने नवाचार के अभिनव कदम उठाकर न केवल कोरोना संकट से लड़ने का साहस दिखाया, बल्कि स्पष्ट कर दिया कि चुनौतियों से जूझने के लिए उसके पास इच्छाशक्ति के साथ नीति और योजनाएं भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह वर्ष 2021-22 के बजट में इसका खाका खींचा वह उनकी दूरदृष्टि का ही परिचायक है। पहली बार राज्य में लव जिहाद रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को इसी सत्र में मंजूरी दी गई। इसी तरह दवा और खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए दंड विधि संशोधन विधेयक को भी कानून का रूप दिया गया।

गौर करें तो 22 फरवरी से 16 मार्च के बीच कुल 13 दिन तक चला विधानसभा का यह सत्र छाप छोड़ने में कामयाब रहा। यह सरकार की उपलब्धि ही है कि कम दिनों के बजट सत्र में कई नवाचार हुए तो गंभीर चर्चाएं भी हुईं। प्रतिपक्ष ने जहां जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो सरकार ने भी वस्तुस्थिति सामने रखकर उसे निरुत्तर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमलनाथ सरकार के पतन के बाद से ही विधानसभा को नियमित अध्यक्ष की दरकार थी। कोरोना के गहराते संकट के बीच अनेक कोशिशों के बावजूद जब अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया तो सरकार ने काम चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाने का निश्चय किया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। विधानसभा की परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर केवल प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने एवं नियमित विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कोरोनाकाल की परिस्थितियों ने लंबे समय अर्थात् 10 माह तक रामेश्वर शर्मा को इस पद पर बनाए रखा। उन्होंने नियमित अध्यक्ष की तरह ही अपने दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे दुर्लभ उदाहरण कम ही मिलेंगे। जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य दिखने लगी तो शिवराज सरकार ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराकर विधानसभा को गिरीश गौतम के रूप में नियमित अध्यक्ष दे दिया।

राज्य में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से कराने की परंपरा रही है, जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय टूट गई थी। तब कांग्रेस ने विपक्ष की असहमतियों को दरकिनार

ऐसा पहली बार हुआ

मप्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया। इस दौरान 14 विधायकों ने अपने सवाल पूछे। संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिए। खास बात यह है कि लॉटरी में 14 में से 13 विधायक कांग्रेस के थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में मप्र विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई एक महिला स्पीकर द्वारा संचालित की गई। सदन की बैठक शुरू होते ही महिला मार्शल के साथ विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम आसंदी तक पहुंचे। इसके बाद अध्यक्ष ने घोषणा की कि भीकनगांव से कांग्रेस की विधायक झूमा सोलंकी प्रश्नकाल के दौरान सदन संचालित करेंगी। इसके बाद सोलंकी ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्रवाई संचालित की। संसदीय कार्य और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने समाज में महिलाओं के योगदान को याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक महिला आरक्षक को सम्मानित करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान के रूप में उसे गृहमंत्री की कुर्सी पर बिठाया।

कर नर्मदा प्रसाद प्रजापति को उम्मीदवार बना दिया था। विरोध में भाजपा ने जगदीश देवड़ा को उतार दिया था। तब सत्तापक्ष और विपक्ष के आमने-सामने आने का बड़ा कारण शक्ति परीक्षण भी था, जिसमें अंततः नर्मदा की जीत हुई थी।

इस बार बजट सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर भी मामला गर्माया रहा। कांग्रेस लगातार मांग करती रही कि विधानसभा उपाध्यक्ष किसी कांग्रेसी विधायक को बनाया जाए। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पूरी भाजपा का एक ही जवाब था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भाजपा को उपाध्यक्ष का पद न देकर परंपरा को तोड़ा है। इसलिए किसी भी कीमत पर कांग्रेस का विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, इसका परिणाम यह हुआ कि विधानसभा उपाध्यक्ष का मनोनयन नहीं हो पाया।

इस सत्र में प्रश्नकाल की नई व्यवस्था भी चर्चा में रही। अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कई नवनिर्वाचित विधायक अब तक सदन में बोल नहीं सके हैं, इसलिए प्रश्नकाल में सिर्फ उन्हें ही सरकार से सवाल पूछने का मौका मिलेगा। यह भी व्यवस्था बनाई गई कि नए सदस्यों के सवाल पूछते समय यदि त्रुटि होती है तो भी कोई वरिष्ठ विधायक हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि पीठ की ओर से संबंधित विधायक को ही त्रुटि सुधारने का मौका दिया जाएगा। इस सत्र में पक्ष-विपक्ष के बीच संवाद का स्तर भी सुधरा हुआ था। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद माना जा रहा था कि सामान्य रूप से होने वाले इस सत्र में दोनों पक्षों के बीच की तल्खी दिखेगी। कांग्रेस सत्ता जाने की वजह से आक्रामक रहेगी और स्पष्ट बहुमत होने के कारण सत्तारूढ़ दल भी पलटवार करेगा, पर दोनों के बीच समझदारी ऐसी बनी कि सदन की कार्यवाही सामान्य तरह से चली। सत्तारूढ़ दल ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को पूरा मान-सम्मान दिया तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति सम्मान दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। ऐसा दोनों नेताओं के लंबे संसदीय अनुभव के कारण ही संभव हो सका।

सद्भाव की शुरुआत सत्र के प्रथम दिन ही

हो गई, जब राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अभिभाषण के लिए विधानसभा पहुंचने वाली थीं। उनकी अगवानी के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ उस स्थान पर खड़े हो गए, जहां सदन के नेता मुख्यमंत्री को होना चाहिए था। यह देख मुख्यमंत्री उनके सामने रेड कार्पेट से नीचे खड़े हो गए और बातचीत करने लगे। कुछ समय में ही कमलनाथ का ध्यान उस तरफ गया तो वह मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर उनके स्थान पर ले गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाने साधे, पर गरिमा का ध्यान रखा।

विधानसभा सत्र स्थगित किए जाने से पहले बजट सत्र में पेश किए जाने वाले सभी विधेयक एक साथ पटल पर रखे गए और सभी विधेयक पारित हो गए। इसके अलावा वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि 2020-21 और 2021-22 में कोरोना के चलते सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इस बार कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। दरअसल, बजट सत्र खत्म होने की बड़ी वजह कोरोना का बढ़ता संक्रमण माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 4 विधायक और विधानसभा के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन चार विधायकों में विजय लक्ष्मी साधौ, अमर सिंह, निलय डागा और देवेंद्र वर्मा पॉजिटिव पाए गए थे। ये चारों विधायक सत्र के दौरान सदन में मौजूद थे। ऐसे में विधानसभा का सत्र स्थगित करने के संकेत मिलने लगे। ऐसे में बढ़ते कोरोना के चलते कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई, इस बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना बढ़ते प्रकोप के चलते विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले ही स्थगित कर दिया जाए।

विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रश्नकाल निर्धारित समय से 2 मिनट पहले समाप्त कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल आसंदी पर सभापति लक्ष्मण सिंह थे और सवाल बंडा विधायक सरवर लोधी ने किया था। लेकिन उससे पहले ही गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सदन से उठकर बाहर चले गए, जबकि प्रश्नकाल के लिए 2 मिनट का समय बाकी था। सभापति ने प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसको लेकर कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि यह विधानसभा के नियम के विरूद्ध है। विधायक सवाल करने के लिए खड़े हुए, लेकिन जवाब देने से पहले मंत्री सदन से बाहर चले गए। ऐसे कुछ मंजर भी विधानसभा में देखने को मिले। लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में सफल नहीं हो पाया। कुछ मिलाकर इस बार का विधानसभा सत्र कई मामलों में अलग रहा।

● **कुमार राजेन्द्र**

पूरे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष कमजोर नजर आया

देश और दल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। इन लगभग सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रमुख दलों व उनके नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अजब-गजब मप्र की भांति यहां की प्रदेश कांग्रेस को समझना भी एक पहेली की भांति है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक कमजोर नजर आ रही है। सदन में वह किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर नहीं पाई। चाहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगी होती कीमतों का मामला हो या दिल्ली में लेकर मप्र में चल रहे किसान आंदोलन का मामला, कमलनाथ की कांग्रेस भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा पा रही है। दिग्विजय सिंह अलबत्ता गाहेबगाहे भाजपा सरकार से लड़ने का ऐलान करते दिखते हैं लेकिन कमलनाथ जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष की मुद्रा में नजर नहीं आते। कांग्रेस की इस कमजोरी का फायदा सत्तारूढ़ भाजपा ने सदन में और सदन के बाहर भी खूब उठाया। दरअसल, कांग्रेस में विश्वास की कमी है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ में नेतृत्व की कमी कई अवसरों पर सामने आ चुकी है।

अधर में प्रोजेक्ट

देश में चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट उत्साह के साथ शुरु हुआ था, लेकिन आज स्मार्ट सिटी का सपना दाग बनकर रह गया है। मप्र की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं।

मप्र की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों के साये में रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी साइट पर हजारों पेड़ों को गुपचुप तरीके से काटने का मामला हो या फिर प्रोजेक्ट दस्तावेजों में ग्रीन बेल्ट का दायरा कम करने का, इसको लेकर विवाद उठते ही रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा आरटीआई से हुआ है, उसने पर्यावरण जैसे संजीदा मामले में स्मार्ट सिटी अफसरों की लापरवाही को उजागर किया है। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जमीन पर शुरू करने से पहले केंद्र सरकार के एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 22 सदस्यीय सेल बनानी थी, जिसका काम प्रोजेक्ट की वजह से हो रही पर्यावरण क्षति की मॉनीटरिंग कर उसकी जानकारी स्मार्ट सिटी कंपनी को देना था। लेकिन हैरत की बात ये है कि अब तक ये सेल नहीं बनाई गई।

बता दें कि यह खुलासा पर्यावरणविद् सुभाष सी पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट संबंधी तीन हजार पन्नों की आरटीआई से मिली जानकारी के तहत किया है। पांडे ने बताया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई जाने वाली 22 सदस्यीय टीम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आधार है, लेकिन बिना इस सेल के काम शुरू किया गया और पिछले 4 सालों से निरंतर चालू है। इसकी वजह से शहर को भारी पर्यावरणीय क्षति हुई है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी कंपनी से जानकारी निकालने के लिए उन्हें 6 आरटीआई लगाई थीं। स्मार्ट सिटी कंपनी ने 4 अपीलों के बाद करीब डेढ़ महीने में जानकारी उपलब्ध कराई। पांडे ने बताया कि तीन हजार पन्नों में से एक हजार पन्नों की जानकारी का 40 दिन अध्ययन करने के बाद खुलासा हुआ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अहम आधार एएमपी सेल बनाई ही नहीं गई।

पांडे ने बताया कि सेल के 22 सदस्यों पर प्रोजेक्ट के तहत 21 लाख रुपए प्रतिमाह और ढाई करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाना था। नियम तो ये भी था कि प्रोजेक्ट साइट पर एनएबीएल की लैब स्थापित की जानी थी, जो नहीं बन पाई है। यही नहीं, पर्यावरण की मॉनीटरिंग पर 59 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाने थे। हर साल यह खर्च किया भी जा रहा है, लेकिन कहां, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर को बड़ी पर्यावरणीय क्षति हुई है। इससे ऑक्सीजन और कार्बन का संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि यहां करीब 7 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। इससे न केवल जैव-विविधता प्रभावित हुई है, बल्कि लाखों की संख्या में छोटे-छोटे जीव-जंतु भी गायब हो गए हैं, जो इस संतुलन को बनाए रखते थे। यही कारण है कि राजधानी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिलाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी को करीब ढाई करोड़ रुपए देकर प्रोजेक्ट तैयार करने का ठेका दे दिया। पांडे ने बताया कि दस्तावेजों के मुताबिक 26 नवंबर से 2016 से 28 फरवरी 2017 तक स्मार्ट सिटी साइट पर प्रदूषण की जांच करना बताया गया है। जबकि राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी कंपनी को जमीन 23 मई 2017 को हस्तांतरित की थी। अब सवाल ये है कि जमीन आवंटन से पहले प्रदूषण जांच कैसे कराई गई। यही नहीं, हैरत वाली बात ये है कि स्मार्ट सिटी साइट से पेड़ों को काटने की इजाजत निगम दे रहा है, जबकि इसके लिए एक अलग सेल बनाई जानी थी।

शहर के चौराहों को संवारने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। ट्रैफिक सिग्नल, लेफ्ट टर्न और उन्नयन के लिए 40 चौराहों पर काम चल रहा है। वहीं 60 अन्य चौराहों का भी चयन होगा। इस काम में 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में अनेक चौराहे ऐसे हैं, जहां लेफ्ट टर्न, ट्रैफिक सिग्नल समेत अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए फरवरी में कुछ चौराहों पर स्मार्ट सिटी कंपनी ने काम की शुरुआत कर दी थी। वर्तमान में शौर्य स्मारक, कोलार समेत कई क्षेत्रों में काम चल रहा है। इन्हें अगले दो-तीन माह में पूरी तरह से संवारने की योजना है। ताकि जाम आदि की समस्या से राहगीरों को निजात दिलाई जा सके। दरअसल, यातायात विभाग ने अगले 5 साल के लिए विकास योजना तैयार की है। इसमें चौराहों पर लेफ्ट टर्न को क्लीयर करने की जरूरत बताई गई थी। इसके बाद स्मार्ट सिटी कंपनी ने इन चौराहों को संवारने का काम हाथ में लिया। पहले चरण में 40 चौराहें चिन्हित कर उन पर काम शुरू किया गया। जहां पर अधोसंचरना सुधार, लेफ्ट टर्न की व्यवस्था, साइनेस की व्यवस्था एवं ट्रैफिक लाइट में सुधार किया जाएगा। दूसरे चरण में 60 अन्य चौराहों पर काम होगा।

● **अरविंद नारद**

क्या था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम

- 24 घंटे पानी के स्प्रिंकलर चलाया जाए, ताकि धूल न उड़े।
- पानी की शुद्धता की जांच हर दिन की जाए।
- 3 एसटीपी लगाए जाने चाहिए।
- मिट्टी की जांच की जानी चाहिए।
- मशीनों से निकलने वाले ऑयल के चलते एक कैमिकल लैब बनाई जानी चाहिए।
- स्मार्ट रोड पर 25 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ज्यादा पर वाहन नहीं चलाए जाएं।
- एक हेल्थ केयर सेंटर इस पूरे क्षेत्र में होना चाहिए।
- खुदाई में मिले अवशेषों को यहां काम कर रहे लोग प्रभावित न करें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि यहां देशी पौधे लगाए जाएंगे लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारी यहां पॉम ट्री लगाकर हरियाली दिखा रहे है, जो कि सबसे बड़ा खिलवाड़ है।

8 माह से अधिग्रहण का काम बंद

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 8 महीने से बंद है। राजस्व विभाग एक्सचेंज में दोगुना जमीन देने को सहमत नहीं है। इससे किसान जमीन के बदले उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कराने के लिए प्रशासन से अनुबंध नहीं करना चाहते। इस हाल में 489 हैक्टेयर निजी जमीन एमपीआरडीसी को कैसे मिलेगी इसे लेकर प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों की चिंता 8 महीने से बरकरार है। किसानों को उम्मीद थी कि नए हाईवे के लिए जमीन देने के एवज में उन्हें दोगुना जमीन मिल जाएगी लेकिन भू-राजस्व संहिता में ऐसा नियम न होने के कारण मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन में व्यवधान आ रहा है। मुरैना से श्योपुर तक बनाए जाने वाले अटल प्रोग्रेस-वे के लिए मुरैना के 1358 किसानों की 489 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए गूगल मैप के अनुसार मुरैना, अंबाह, पोरसा, जौरा, कैलारस व सबलगढ़ के किसानों की निजी जमीन चिन्हित कर ली गई है। हालांकि किसान इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनों को देने के मूड में नहीं हैं लेकिन अगस्त-2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर प्रवास के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को जमीन के बदले दोगुना जमीन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा भू-राजस्व संहिता के नियमों के अनुरूप न होने के कारण राजस्व अधिकारियों ने किसानों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जितनी जमीन ली जाएगी उतनी ही जमीन दूसरी जगह एक्सचेंज में मिलेगी। एसडीएम व तहसीलदारों के ऐसे जवाब सुनकर अंबाह व पोरसा के किसानों ने अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन देने से साफ मना कर दिया है। पिछले दिनों एलएन मालवीय ग्रुप के कंसलटेंट अंबाह इलाके में जमीन के सर्वे नंबरों का सत्यापन करने गए तो किसानों ने उन्हें अपनी जमीनों की **लोकेशन दिखाने व सर्वे नंबर बताने** से इंकार कर दिया। जानकारी के अनुसार अटल प्रोग्रेस-वे की कुल लागत 6000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस परियोजना के तहत कोटा से श्योपुर, मुरैना होते हुए भिंड तक हाईवे बनेगा। मुरैना जिले में 1467 हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। राजस्व विभाग ने अगस्त में एनएचएआई को 978 हैक्टेयर सरकारी जमीन दे दी है। अभी 70 गांवों के 1358 किसानों से निजी जमीन ली जानी है। 489 हैक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण करना बाकी है।

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए मुरैना अनुभाग के गड़ौरा, गौसपुर, जखौना, नायकपुरा, गोरखा, पिपरई, विंडवा चंबल, मसूदपुर, जारह व कैंथरी गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। दो शिविर लगाने के बाद भी किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति नहीं दी। अंबाह के ऐसाह, जौंहा, डंडौली, खिरेंटा, गूंज व रिठौना गांव की 73.685 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है लेकिन किसान दोगुनी जमीन मिलने का लिखित अनुबंध होने के बाद ही अपनी जमीन देने की बात कह रहे हैं। उक्त गांवों से होकर ही अटल प्रोग्रेस-वे निकलेगा। इसमें मुरैना के 11, पोरसा के 15, जौरा के 18, सबलगढ़ के 21 व पोरसा के 15 गांव शामिल रहेंगे। 6 हजार करोड़ की लागत के प्रोग्रेस-वे को घड़ियाल अभयारण्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चंबल नदी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 1467 हैक्टेयर जमीन सरकारी है। वहीं 489 हैक्टेयर किसानों की जमीन आएगी। एक्सप्रेस-वे की जद में करीब 1248.86 हैक्टेयर जमीन आ रही है। इसके बदले में किसानों को दूसरी जगह जमीन कलेक्टरों को उपलब्ध करानी होगी। जमीन देने पर काफी किसानों ने अपने सहमति भी दे दी है। औपचारिकताओं को अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अटल प्रोग्रेस-वे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भोपाल की एलएन मालवीय कंपनी को दिया है। इस कंपनी को एक साल में डीपीआर बनाकर एनएचएआई को सौंपना थी। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके अगले चरण में प्रोग्रेस-वे बनाने का काम लेकिन कंसल्टेंट अभी गूगल पर रोडमैप बनाने के लिए सरकारी जमीन से लेकर किसानों व वन विभाग की जमीन के सर्वे नंबरों पर लाइनिंग तक ही सीमित है। डीपीआर कब तक बनेगी इसका कोई जबाव कंसल्टेंट समेत एनएचएआई के अफसरों के पास नहीं है। सड़क विकास निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर पीएस राजपूत कहते हैं कि प्रोग्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जुलाई 2020 से बंद है। शासन से भी नए दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। डीपीआर तैयार कर रही कंसल्टेंसी के कारिंदे पिछले दिनों अंबाह-पोरसा आकर निजी जमीन के सर्वे नंबर पटवारियों से सत्यापित करा ले गए हैं लेकिन किसान दोगुनी जमीन की जिद पर अड़े हैं।

● **प्रवीण कुमार**

उप्र-राजस्थान भी बने राह में रोड़ा

चंबल प्रोग्रेस-वे योजना में उप्र और राजस्थान सरकार से भी सहयोग नहीं मिलने के चलते अटल प्रोग्रेस-वे की लंबाई अटक गई है। निर्माण के लिए एनएचएआई ने दोनों राज्यों को पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण के संबंध में कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। एनएचएआई ने डीपीआर के लिए कंपनी नियुक्त कर दी है। कंपनी रिपोर्ट 6 से 9 माह में दे देगी। दोनों राज्यों के राजी होने के बाद अब इस मार्ग की लंबाई 350 से 400 किमी होगी। पहले चरण में एक्सप्रेस-वे फोरलेन का होगा। इसकी डिजाइन और स्पेस 8 लेन तक रखा जाएगा। परियोजना उप्र के इटावा से शुरू होगी। राजस्थान के कोटा के पास दिल्ली, आगरा और दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर में मिलेगी। अनुमानित लंबाई 398.08 किमी है। एक्सप्रेस-वे मप्र के भिंड से एनएच-92 से शुरू होगा। मुरैना से उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर से होते हुए राजस्थान सीमा तक पहुंचेगा।

मृतप्राय संपत्तियां बिकेंगी

मप्र में फैली राज्य शासन की ऐसी संपत्तियां जो मृतप्राय हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, सरकार उनको बेचने की तैयारी कर रही है। शासन का मानना है कि इन संपत्तियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। इसी के लिए सरकार ने हाल ही में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया है। विभाग प्रदेशभर की अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों को सूचीबद्ध कर रहा है। अभी तक करीब 60 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें बेचना है।

दरअसल, सत्ता में आने के बाद से ही खजाना खाली होने के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार आय के साधन को बढ़ाने में जुटी हुई है। राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए आए दिन बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार प्रदेशभर में मौजूद सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। इसके लिए अभी तक 60 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से कुछ संपत्तियां बेच दी गई हैं, वहीं कुछ को बेचने की प्रक्रिया चल रही है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की कहां, कितनी संपत्ति है, उसका क्या व्यावसायिक या अन्य उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रबंधन करने के लिए सरकार ने एक अलग लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया है। यह विभाग प्रदेशभर में सरकारी संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है। विभाग संपत्ति के रखरखाव के साथ उसके औचित्य का निर्धारण भी करेगा। संपत्ति के बारे में नीति और गाइडलाइन तैयार करेगा। सरकार को इस संपत्ति के बारे में राय देगा कि उसे बेचना उचित है या नहीं। उसका किस तरह से व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। जमीनों के मॉनीटाइजेशन के लिए विकल्प ढूंढ़ेगा, जिससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। इसके लिए वह विभागों से विचार-विमर्श और समन्वय से काम करेगा। पीपीपी प्रोजेक्ट में यह अन्य विभागों या एजेंसियों को सलाह भी देगा।

प्रदेश में तकरीबन सभी विभागों के पास अचल संपत्तियां हैं। लोक निर्माण विभाग के पास जो रेस्ट हाउस हैं, उनमें निर्माण तो एक या डेढ़ हजार वर्गफीट पर है लेकिन ढाई से सात एकड़ तक जमीन खाली पड़ी हुई है। साथ ही वो अचल संपत्ति, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उनके निराकरण की समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। ऐसी सभी संपत्तियों का उपयोग अब राज्य हित में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने लोक निर्माण और सड़क परिवहन निगम की कुछ संपत्तियां नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अपनी कुछ संपत्तियां बेचने जा रहा है। इसके लिए समिति भी बनाई जा चुकी है। वहीं, परिवहन विभाग ने भी सड़क परिवहन निगम की अचल संपत्तियों को बेचने का निर्णय किया है।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ने सरकारी संपत्तियां बेचने की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत बस डिपो, रेस्ट हाउस, मकान, खाली भूखंड, कारखाने, ऑफिस, बिल्डिंग, रेशम केंद्र, सिल्क केंद्र आदि बेचे जा रहे हैं। फिलहाल प्रदेशभर में 60 से अधिक संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संपत्तियों को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई संपत्तियों की बिक्री के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। कुछ संपत्तियों की बोली भी शुरू हो गई है। अपनी योजना के तहत सरकार ने मुरैना जिले के पोरसा नगर के प्राइम लोकेशन पर मौजूद बस स्टैंड को सरकार ने बेच दिया। इस बस स्टैंड को बेचने की नीलामी भोपाल में जनवरी महीने में इतने चुपचाप में कराई गई कि आम जनता तो छोडिए अंबाह ब्लॉक व पोरसा तहसील के अफसरों तक को इसकी जानकारी नहीं लगी। लगभग 16 करोड़ रुपए में बस स्टैंड की जमीन को निर्माणों सहित बेचा गया है। वहीं अब मुरैना शहर का भी एक बस स्टैंड बिकने जा रहा है। यह बस स्टैंड मप्र राज्य परिवहन निगम की संपत्ति है और इसे नीलाम करने के लिए मुरैना जिला प्रशासन प्रस्ताव भी भेज चुका है। उधर, प्रदेश के 20 जिलों की सरकारी संपत्ति को बेचने पर रोक लगाने के लिए मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई है।

● **जितेंद्र तिवारी**

प्रदेश के बाहर की संपत्तियों पर नजर

मप्र के बाहर शासकीय परिसंपत्तियों से आय बढ़ाने के लिए सरकार उनका नए सिरे से उपयोग करेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत मप्र के स्वामित्व वाली वे संपत्तियां जो अन्य राज्यों में है और अविवादित हैं, उन्हें नीति में शामिल किया जाएगा। वहीं, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों की अनुपयोगी परिसंपत्तियों को नीलाम करने कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन और परिसरों के नए सिरे से उपयोग के लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 में लागू की गई थी। इसका दायरा सीमित था लेकिन अब इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नीति में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक निगम, मंडल, प्राधिकरण और नगरीय निकायों के भवन या परिसर भूमि का नए सिरे से उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश के बाहर स्थिति अविवादित और अनुपयोग संपत्ति भी नीति के दायरे में आएगी। प्रदेश की उप्र, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में संपत्तियां हैं। मप्र राज्य परिवहन निगम की कई संपत्तियां गुजरात, उप्र, राजस्थान व अन्य राज्यों में भी हैं। उनमें से कई संपत्तियों की हालत यह है कि कहीं तो दबंगों ने इन पर कब्जा कर लिया है तो कहीं स्थानीय सरकार ने। महाराष्ट्र के नागपुर में भी मप्र राज्य परिवहन निगम की एक संपत्ति थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के आवास बना दिए हैं।

खैर की खैर नहीं

प्रदेश के जंगल कत्था बनाने के काम आने वाले खैर की लकड़ी की तस्करी का बड़ा केंद्र बना है। बीते कुछ सालों में यहां से 4 हजार ट्रक लकड़ियां तस्करों ने चुराई और विभिन्न फैक्टरियों को सप्लाय की है। यह खुलासा दो महीने तस्करों से पूछताछ के बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में खैर की लकड़ी के लिए तस्कर सक्रिय हैं। मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) बड़े रैकेट की पड़ताल में जुटी है, जिसमें तस्करों के तार हरियाणा के एक बड़े कारोबारी से जुड़े हैं। ये पान मसाला बनाने वाली कंपनी के लिए कत्था बनाकर सप्लाय करता है। उधर अब खैर बचाने में वन विभाग गंभीर हो चुका है।

कुछ सालों में खैर की तस्करी व अवैध व्यापार को लेकर प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई चल रही है। वन विभाग और एसटीएसएफ दोनों अलग-अलग कार्रवाई करने में लगे हैं। छिंदवाडा, देवास, भोपाल, सतना, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई वनक्षेत्र से खैर की लकड़ियां चोरी हो चुकी हैं। तीन साल में 80 से ज्यादा प्रकरण बनाए हैं, जिसमें 95 आरोपियों को पकड़ा गया है। अकेले एसटीएसएफ ने नवंबर 2018 से लेकर अभी तक पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए हैं। 69 आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से पकड़ा है, जिनसे 21 वाहन भी जप्त किए हैं। यहां तक कुछ वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया हो चुकी है। अभी तक 324 मैट्रिक टन खैर की लकड़ी जप्त की गई है। आरोपियों से पूछताछ में बीते 3 साल में प्रदेश के जंगल से खैर बड़ी मात्रा में चुराया गया है, जिसमें करीब 4 हजार ट्रक लकड़ियां दूसरे राज्यों में भिजवाई गई हैं।

जनवरी 2020 में देवास स्थित खिवनी अभयारण्य से वनपोज खैर के पेड़ काटने और अवैध परिवहन को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई की। अगले दिन ही एसटीएसएफ ने प्रकरण की जांच अपने हाथ में ली। नियमानुसार अभयारण्य में वन्यप्राणी व वनपोज से जुड़े अपराध की जांच एसटीएसएफ कर सकता है। खिवनी अभयारण्य से खैर तस्करी में पिछले साल ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच में तस्करी के बाद लकड़ियां कई राज्यों में पहुंचने की बात गिरोह ने कबूली। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उप्र, राजस्थान की फैक्टरियों में लकड़ियां सप्लाय हुईं, जिसमें हरियाणा के भाजपा नेता के भांजे की फैक्टरी भी शामिल है। यहां से एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी 2021 में एसटीएसएफ ने एक ट्रक संचालक विनोद कटियार को पकड़ा। बताया जाता है कि कई बड़े कारोबारियों के नाम सामने आए हैं।

गुणों की वजह से खैर के पेड़ों पर वन माफिया की नजर

देशभर में खैर का जंगल तेजी से सिमट रहा है और वन विभाग ने इसे दुर्लभ वृक्ष की श्रेणी में रखा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पेड़ों की प्रजातियों को संतुलित रूप से इस्तेमाल में लाने की बात कही गई है जिससे वे खत्म न हों। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने वर्ष 2004 में विश्व में तकरीबन 552 पेड़ों की प्रजातियों को खतरे में माना गया जिसमें 45 प्रतिशत पेड़ भारत से थे। इन्हीं में खैर का नाम भी शामिल है। इस पेड़ का इस्तेमाल औषधि बनाने से लेकर पान और पान मसाला में इस्तेमाल होने वाले कत्था, चमड़ा उद्योग में इसे चमकाने के लिए किया जाता है। प्रोटीन की अधिकता के कारण ऊंट और बकरी के चारे के लिए इसकी पत्तियों की काफी मांग है। चारकोल बनाने में भी इस लकड़ी का उपयोग होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल डायरिया, पाइल्स जैसे रोग ठीक करने में होता है। मांग अधिक होने की वजह से खैर के पेड़ों को अवैध रूप से जंगल से काटा जाता है। तस्करी के मामलों में पुलिस व वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 50 के अंतर्गत गिरफ्तारी करके कार्रवाई होती है। तस्करों के पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है।

तस्करों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। फैक्टरियों में खैर की लकड़ियां पहुंचने के बाद इनसे कत्था निकाला जाता है। इसे पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को भेजते हैं। हरियाणा के जिस कारोबारी का नाम प्रकरण में शामिल है। इसकी फैक्टरी से भी कत्थे के लिए कंपनी को निरंतर खैर सप्लाय हुआ है। एसटीएसएफ इस कारोबारी को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी को बचाने के लिए एसटीएसएफ के अधिकारियों से रोहित नामक व्यक्ति संपर्क बनाए हुए है।

देश में सबसे अधिक 1.67 प्रतिशत खैर के जंगल मप्र में हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, उप्र, राजस्थान में भी खैर के पेड़ मौजदू हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईईपीएन) ने दुनियाभर में पेड़ों की जिन प्रजातियों को खतरे में माना था उसमें खैर भी शामिल है। प्रदेश में खैर की चोरी होने के बावजूद वन विभाग की सक्रियता थोड़ी कम नजर आती है। बताया जाता है कि कई स्थानों पर तस्कर क्षेत्रीय वनकर्मियों से सांठगांठ बनाए है। पान मसाले और कैमिकल के लिए इस्तेमाल होने वाली खैर की लकड़ी काफी महंगी बिकती है। 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल मूल्य में लकड़ी बिकती है। मांग अधिक होने पर तस्कर इसकी कीमत भी बढ़ा देते हैं। पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ व एसटीएफएस प्रमुख अलोक कुमार कहते हैं कि खैर की तस्करी को लेकर वन विभाग और एसटीएसएफ मिलकर काम कर रहा है। वन विभाग ने जंगल में सर्चिंग बढ़ाई है और एसटीएसएफ तस्करों से पूछताछ कर गिरोह का पता लगाने में जुटे है। कारोबारी पर शिकंजा कसने के लिए सबूत जुटाने का काम किया जा रहा है।

खैर के हरे पेड़ को काटने की सख्त मनाही है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे लगे पेड़ जो बाढ़ में बह जाते हैं, उन्हें वन विभाग बेचता है। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी वन विभाग खराब हुए पेड़ों को बेचता है, जिससे बाजार में इसकी उपलब्धता के साथ जंगल भी बचाया जा सके। हरियाणा में हर 10 साल में वन विभाग खैर के वयस्क पेड़ काटते हैं और नया पौधा लगा देते हैं। मांग अधिक होने की वजह से वन तस्कर बेहताशा इस पेड़ को काटते हैं। बाजार में लकड़ी की कीमत 5 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक है। इस तरह एक वयस्क पेड़ से 5 से 7 लाख रुपए तक का फायदा हो जाता है।

● **नवीन रघुवंशी**

दांव पर साख

दमोह विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का मैदान सज गया है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक राहुल लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के बीच है। लेकिन इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की साख दांव पर है। इसलिए भाजपा ने अपने दो मंत्रियों नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को प्रभारी नियुक्त किया है। इन दोनों नेताओं पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी होगी।

चुनाव आयोग ने 16 मार्च को ऐलान किया कि मप्र की दमोह विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 17 अप्रैल को होगा। अन्य विधानसभा चुनावों के परिणाम के साथ-साथ 2 मई को दमोह सीट का भी नतीजा घोषित होगा। अक्टूबर, 2020 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी। तब राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस उपचुनाव को केंद्रीय मंत्री तथा दमोह से सांसद प्रहलाद सिंह और पूर्व राज्य मंत्री जयंत मलैया के बीच छद्म युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी उपचुनाव के इस जंग में जोरदार तरीके से उपस्थित है। कांग्रेस ने अजय टंडन को यहां का अपना प्रत्याशी बनाया है। वे दमोह से कांग्रेस के वफादार परिवार से हैं।

अजय टंडन पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। इस बार उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राहुल लोधी से होगी। टंडन का इससे पहले दो बार पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया से मुकाबला हो चुका है। मलैया 6 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के राहुल लोधी ने उन्हें हरा दिया था। अब लोधी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। मलैया 2018 में कांग्रेस के राहुल लोधी से करीब 800 वोटों से हार गए थे। राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कुल 26 लोगों में आखिरी शख्स थे। अन्य 25 लोगों को नवंबर, 2020 में मप्र में उपचुनाव का टिकट देकर पुरस्कृत कर दिया गया था। उम्मीद थी कि समझौते के तहत लोधी को टिकट मिल जाएगा। लेकिन लोधी स्थानीय तौर पर बहुत लोकप्रिय नहीं हैं और मलैया दमोह के दिग्गज नेता हैं। ऐसे में लोधी की राह आसान नहीं है। मलैया 1990 और 2013 के बीच 6 बार यह सीट जीत चुके हैं। मलैया के बेटे सिद्धार्थ भी टिकट के दावेदारों में शामिल थे। भाजपा जहां लोधी को पुरस्कृत करना चाहती है, वहीं यह भी चर्चा है कि सिद्धार्थ निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि साल 1984 में दमोह सीट कांग्रेस विधायक चंद्र नारायण टंडन के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। कांग्रेस ने उनके भतीजे अनिल टंडन को मैदान में उतारा था, जो भाजपा उम्मीदवार जयंत मलैया से हार गए थे। मलैया की जीत ने उनके सियासी कैरियर को 2018 तक मजबूत बनाए रखा, तब तक वे भाजपा सरकार में मंत्री बने रहे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दमोह उपचुनाव लोधी के कैरियर को पुनर्जीवित करेगा या किसी नए नेता को उभारेगा।

दमोह में भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व में 6 बार विधायक रह चुके जयंत मलैया को प्रत्याशी न बनाए जाने से उनके समर्थकों में नाराजगी नजर आ रही है। वहीं मलैया के बेटे सिद्धार्थ भी इस सीट से भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इधर, दमोह में सिद्धार्थ और गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव को भी साथ देखा गया है। उधर, शिवराज कैबिनट में मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। कई लोग इन्हें मलैया-विरोधी मानते हैं। जिस तरह दमोह में भाजपा का निश्चित वोट है, उसी तरह कांग्रेस का भी। दमोह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और आगामी चुनावों में शायद ही कोई स्थानीय कारक उभरे। उम्मीद की जा रही है कि जाति ही प्रभावी कारक होगा।

दमोह सीट पर अपना कब्जा बरकरार करने के लिए कांग्रेस ने माइक्रोमैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के संगठन पदाधिकारियों को दमोह में डेरा डाल पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मप्र महिला कांग्रेस ने हर वार्ड में 10 महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम तैनात कर दी है। ये कार्यकर्ता आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक और कमलनाथ सरकार की

अब शोले के जय और वीरू बने भार्गव और मलैया

अमर-अकबर-एंथोनी की जोड़ी टूटने के बाद अब प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने खुद को और पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया को शोले के जय और वीरू की जोड़ी कहा है। उनका कहना है कि यदि चुनाव जीतने के लिए जरूरत पढ़ी तो वह दोनों जय और वीरू बन जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद गोपाल भार्गव, जयंत मलैया और डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को मंत्री बनाया गया था। उस समय जब ये तीनों मंत्री एक कार्यक्रम में दमोह पहुंचे थे तो उन्होंने तीनों को अमर-अकबर-एंथोनी की जोड़ी बताया था और ये भी कहा था कि अब ये जोड़ी खूब कमाल करेगी। समय बदला तो एंथोनी बने डॉ. कुसमरिया ने 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस में चले गए। हालांकि अब वे भाजपा में आ गए हैं, लेकिन मंत्री भार्गव और मलैया से अब उनकी कुछ खास नहीं बनती, इसलिए अब इस जोड़ी ने अपने नए किरदार तय कर लिए हैं। चुनावी समीकरण पर चर्चा के दौरान मंत्री भार्गव ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कोई कशमकश नहीं है। परिणाम सष्ट है, दीवार पर लिखा है। भाजपा भारी बहुमत से दमोह विधानसभा का उपचुनाव जीतेगी। किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। परिणाम देखने के बाद आप खुद स्वीकार करेंगे कि उन्होंने सही कहा था। जहां तक पार्टी की बात है, तो ये उपचुनाव है। भाजपा की ताकत के बारे में पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और अपनी रीति-नीति और अपने संगठन के लिए भी जानी जाती है। संगठन के कार्यकर्ता तो अभी शुरुआती दौर में हैं।

उपलब्धियां बता रही हैं। कभी अपनी परंपरागत रही सीट को कांग्रेस से हथियाने के लिए भाजपा ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। दमोह चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारी की गई हैं। पार्टी ने निचले स्तर तक नेता और कार्यकर्ताओं की टीम तैनात कर दी है। जो भाजपा उम्मीदवार राहुल लोधी के समर्थन में माहौल बनाने में जुटे हैं।

उधर, दमोह विधानसभा सीट उपचुनाव की रणनीति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले रखी है। दिग्विजय सिंह, अरूण यादव सहित दूसरे बड़े नेताओं की कोई भूमिका अब तक सामने नहीं आई। गत दिनों उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन करवाया। इस दौरान भी कांग्रेस का कार्यक्रम फीका रहा। दमोह में अजय टंडन को अपनी पसंद और सर्वे के आधार पर कमलनाथ ने ही टिकट दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तो सिर्फ उम्मीदवार घोषित करने की औपचारिकता की है। दमोह के उपचुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व की भी एक और परीक्षा होना है। कमलनाथ, मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पार्टी विधायक दल के नेता हैं। कमलनाथ पहली बार मप्र में पूरा समय देकर राजनीति कर रहे हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के प्रचार का प्रमुख चेहरा थे। 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी। लेकिन, 15 माह भी सरकार नहीं चल सकी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी उपेक्षा के कारण 25 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी।

सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने के बाद राज्य की कांग्रेस राजनीति का केंद्र कमलनाथ बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और अरूण यादव जैसे कद्दावर चेहरे हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोजित की गई पहली सभा के मंच पर कांग्रेस एकजुट होने का संदेश नहीं दे पाई है। कमलनाथ के अलावा कार्यक्रम में कोई दूसरा बड़ा नेता मौजूद नहीं था। कमलनाथ ने चुनाव की कमान अपने भरोसेमंद समर्थकों को सौंपी है। दो विधायक रवि जोशी और संजय यादव के पास चुनाव संचालन की जिम्मेदारी है।

मप्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज समझने वाले दिग्विजय सिंह अकेले नेता हैं। विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी थीं। राज्य में कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई है। सबसे बड़े गुट के क्षत्रप खुद दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिस्टर बंटाधार के नारे पर ऐतिहासिक जीत मिली थी। पार्टी की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी घोषणा के अनुसार पार्टी में 10 साल तक कोई पद नहीं लिया चुनाव भी नहीं लड़ा। 15 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने वर्ष 2019 में भोपाल से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा, हार गए। इससे पहले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के मैदानी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने में दिग्विजय सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। कांग्रेस की सत्ता में वापसी की एक वजह नेताओं के बीच समन्वय भी रहा। लेकिन, सत्ता में आते ही नेताओं के बीच समन्वय टूट गया। सरकार गिरने का ठीकरा भी दिग्विजय सिंह के सिर फूटा। 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दिग्विजय सिंह मुख्य भूमिका में दिखाई नहीं दिए थे। कमलनाथ ने उम्मीदवारों का चयन भी खुद ही किया था।

कमलनाथ का एक साथ दोनों महत्वपूर्ण पद संभालना कांग्रेस की राजनीति में असंतोष का कारण बने हुए हैं। गोडसेवादी पार्टी से आए बाबूलाल चौरसिया के प्रवेश के समय असंतोष सामने भी आया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरूण यादव ने तो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि बापू हम शर्मिंदा हैं। एक अन्य नेता माणक अग्रवाल को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया। इस सवाल पर प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि वक्त का इंतजार करिए। पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार चेहरों का उपयोग करेगी। दमोह में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन सिर मुडाते ही ओलों का शिकार हो गए। पहले तो चुनावी सभा में कमलनाथ टंडन का नाम ही भूल गए। दूसरी अजीब स्थिति उस वक्त बनी जब नामांकन दाखिल कराने में भी कमलनाथ साथ नहीं गए। जबकि चुनावी सभा और नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए ही कमलनाथ दमोह गए थे। मप्र भाजपा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तंज करते हुए कहते हैं कि कमलनाथ की उम्र चुनाव प्रचार की नहीं है, उन्हें आराम करना चाहिए।

● **लोकेंद्र शर्मा**

कांग्रेस ने खेला ब्राह्मण कार्ड

नगरीय निकाय चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार वो हर दांव खेलने की तैयारी में लगे है जिससे प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को पटखनी दी जा सके। कांग्रेस पिछले साल मार्च में प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद और उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अब किसी तरह की चूक नहीं चाहती। ऐसे में अब संगठनात्मक फेरबदल भी बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। इसी के तहत अब पार्टी के दिग्गज नेता और दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके मनु मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि मिश्रा के अनुभवों का लाभ हासिल कर पार्टी निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदारों में से थे। लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों ने मिश्रा को दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने के साथ ही जिले की कमान सौंपने का निर्णय किया है। ऐसे में जिन चार जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है उसमे मनु मिश्रा को शामिल किया गया है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दमोह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनु मिश्रा को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया है। विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन डकैतों की सक्रियता शुरु हो गई है। पाठा के जंगल से लेकर चंबल के बीहड़ में डकैतों की आहट सुनाई दे रही है।

बीहड़ में डकैतों की आहट

कुछ साल पहले तक डकैतों के लिए कुख्यात चंबल के बीहड़ में एक बार फिर से डकैतों की आहट तेज हो गई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कारण डकैत सक्रिय हो गए हैं। उप्र और मप्र की सीमा पर स्थित पाठा के जंगलों में भी डकैतों की सक्रियता बढ़ गई है। लेकिन ग्वालियर-चंबल संभाग में डकैतों की सक्रियता चुनावी नहीं है, बल्कि डकैत अपहरण और फिरौती के काम में जुट गए हैं। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिससे यह कहा जा सकता है कि बीहड़ में डकैत पनपने लगे हैं। श्योपुर के विजयपुर में डकैतों द्वारा मुरैना जिले के युवक (सरकारी स्कूल के शिक्षक) के अपहरण ही घटना ने चंबल अंचल में डकैतों की आहट फिर तेज कर दी है। हकीकत यह है कि मुरैना व श्योपुर के जंगलों में बीते 4 से 5 महीने से डकैतों की गतिविधियां फिर तेज हो गई हैं।

गौरतलब है कि सबलगढ़ निवासी पवन गुप्ता सरकारी शिक्षक हैं और विजयपुर जनपद के बीसा प्राइमरी स्कूल में पदस्थ हैं। गत दिनों पवन गुप्ता अपनी बाइक से स्कूल जा रहे थे तभी हथियारबंद बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन चारों ओर से पुलिस दबाव के कारण शिक्षक को मुक्त करके डकैत जंगल में भाग गए। इस घटना में 60 हजार के ईनामी डकैत गुड्डा गुर्जर के अलावा दो अन्य गैंगों पर भी पुलिस का संदेह जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि डकैतों ने श्योपुर-मुरैना क्षेत्र में यह पहला अपहरण नहीं किया है। इससे डेढ़ महीने पहले ही विजयपुर के गांवड़ी गांव से सरपंच के बेटे का अपहरण हुआ था। इसके अलावा डकैतों की यह टोलियां मुरैना जिले के निरारा, पहाड़गढ़ और सुमावली थाना क्षेत्र में जंगल में बसे गांवों में दहशत फैला रहे हैं। यह बदमाश ग्रामीणों से रसद वसूली कर रहे हैं। करीब ढाई महीने पहले सुमावली क्षेत्र में मधुमक्खी पालन करने वाले एक किसान को भी डकैतों ने लूट लिया था, इस लूट के बाद ही गुड्डा गुर्जर पर ईनाम की राशि और बढ़ाई गई, पर पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई।

विजयपुर थाने की जद में आने वाले गांवड़ी पंचायत के सरपंच निरी जाटव के बेटे सतीश जाटव का 14-15 फरवरी की रात 1 बजे अपहरण हुआ था। जब अपहरण हुआ था तब सतीश जाटव एक तालाब में जेसीबी से खुदाई करवा रहा था, तभी चार हथियारबंद बदमाश उसे उठा ले गए और छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सूचना मिलते ही विजयपुर थाने की पुलिस गांव में पहुंची और कुछ देर बाद लौट आई। बताया गया है कि सरपंच निरी जाटव ने बेटे की जान का खतरा बताते हुए पुलिस की मदद लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद सरपंच ने 5 लाख रुपए की फिरौती डकैतों तक पहुंचाई उसके बाद 15-16 फरवरी की रात में बदमाशों ने सतीश जाटव को बेरखेड़ा के जंगल में मुक्त किया। यह चारों डकैत पैदल ही थे और पुलिस ने इनकी घेराबंदी के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। सरपंच के बेटे के मुक्त होने के बाद भी पुलिस ने कोई खास पहल नहीं की, इसी का असर है कि डकैतों के हौसले बुलंद होते गए।

मुरैना-श्योपुर के जंगलों में 60 हजार रुपए के ईनामी गुड्डा गुर्जर के अलावा दो और गैंगों की सक्रियता बढ़ गई है। पुलिस सूत्रों की मानें तो मुरैना जिले के बरबासिन गांव में हत्या करके फरार हुए 6-7 आरोपित भी बंदूकें लेकर जंगल में उतर गए हैं। हत्या के यह आरोपित जंगल में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए गुड्डा गुर्जर के खात्मे का भी प्रयास कर चुके हैं। इनके अलावा विजयपुर के भुजपेरिया गांव से हत्या के आरोप में फरार चल रहे तीन बदमाशों द्वारा भी जंगल में शरण लेने और अपना गैंग बनाकर डकैती की घटनाओं को अंजाम देने की चर्चाएं हैं। यह बदमाश गुड्डा गुर्जर के नाम पर जंगली क्षेत्र के गांवों में दहशत फैला रहे हैं। आईजी चंबल रेंज मनोज शर्मा कहते हैं कि शिक्षक के अपहरण की घटना में पहला शक गुड्डा गुर्जर गैंग पर ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य गैंग के मूवमेंट भी जंगल में हैं, यह बात सही है। हमारी टीमें जंगल के हर क्षेत्र में सर्चिंग कर रही हैं। गांवड़ी के सरपंच के बेटे के अपहरण की सूचना तो थी, लेकिन 5 लाख की फिरौती देकर मुक्त होने की जानकारी मुझे नहीं है।

वहीं डकैतों को फिरौती देकर मुक्त हुए सरपंच पुत्र सतीश जाटव का कहना है कि रात 1 बजे चार बदमाश, जिनमें से दो के पास बंदूकें थीं। एक बदमाश की भाषा मुरैना क्षेत्र जैसी थी। ये बदमाश मुझे पैदल चलाकर हीरामन-झिरन्या के जंगल में ले गए। दूसरे दिन मेरे पिता नोटों की गड्डियां लेकर आए, पिता रोने लगे तो एक डकैत ने उन्हें 10 हजार रुपए लौटा दिए। डकैतों पर रुपए पहुंच गए तब वो मुझे बेरखेड़ा के पास छोड़ गए। इसके बाद भी यह डकैत कई बार गोहटा, गांवड़ी, पचनया के आसपास देखे गए हैं। मैं इनके साथ 24 घंटे रहा हूं और चारों बदमाशों को पहचान सकता हूं।

● **राकेश ग्रोवर**

डकैतों की मार से टूटा शिक्षक का हाथ

डकैतों के चंगुल से मुक्त हुए शिक्षक पवन गुप्ता को डकैतों ने इतना मारा कि उनका सिर फूट गया और एक हाथ भी टूट गया है। गत दिनों घायल शिक्षक को उनके स्वजन मुरैना में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके गुप्ता के यहां लाए, जहां एक हाथ में फ्रेक्चर बताया गया और उसके बाद प्लास्टर चढ़ाकर शिक्षक को आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया गया।

मप्र में पिछले 5 साल में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसमें एक भी आईएएस और आईपीएस नहीं हैं। अगर प्रदेश की दोनों जांच एजेंसियों की मानें तो मप्र के ब्यूरोक्रेट्स दागी नहीं हैं।

दागी नहीं मप्र के ब्यूरोक्रेट्स

पिछले 5 साल के दौरान केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को आईएएस अधिकारियों की 3,474 शिकायतें मिली हैं। वहीं सीबीआई ने 5 वर्ष में 44 आईएएस और 12 आईपीएस के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। लेकिन मप्र सरकार की जांच एजेंसियों लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को पिछले 5 साल में ऐसा एक भी आईएएस, आईपीएस नहीं मिला जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए हैं उसमें कोई आईएएस, आईपीएस नहीं मिला जिसके खिलाफ 4 साल में लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की हो।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार से सवाल पूछा था कि वर्ष 2017 से मार्च 2021 तक प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने राज्य में शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभागों में किस-किस स्तर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य के किस-किस स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के यहां छापामार कार्रवाई की। किसकी कितनी चल-अचल संपत्ति जब्त की गई। किन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किए गए और किनमें खात्मा लगाया गया।

सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की ओर से 24 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। लेकिन इनमें एक भी आईएएस-आईपीएस शामिल नहीं है। वहीं लोकायुक्त पुलिस द्वारा जो छापामार कार्रवाई की गई उसमें 81 लोगों पर कार्रवाई की गई उसमें भी कोई आईएएस, आईपीएस शामिल नहीं है। ईओडब्ल्यू ने 10 मामले दर्ज किए और इनमें शामिल 24 लोगों के खिलाफ छापामार कार्यवाही की। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें बसंत पटेल शाखा प्रबंधक किजला सहकारी बैंक कृषि शाखा नरसिंहपुर, शोभा पटेल धनारे कॉलोनी नरसिंहपुर, जलसंसाधन विभाग से सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री कोदूप्रसाद तिवारी और उनके परिजनों में पत्नी गिरिजा देवी, पुत्र राकेश तिवारी और पुत्रवधु प्रीति तिवारी, नगर निगम इंदौर में सहायक यंत्री अभय सिंह राठौर, टाईमकीपर संतोष सिंह राठौर, माया सिंह तोमर, अमित सिंह तोमर, पूनम सिंह, राकेश कुमार जिला सहकारी बैंक सीधी के तत्कालीन लीड प्रबंधक गंगाप्रसाद शाह, ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव भागचंद्र कौरव, सरपंच मालतीबाई कौरव, दुर्गा बाई और संदीप कुमार कौरव, जबलपुर में सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सुरेश उपाध्याय, अनुराधा उपाध्याय और सचिन उपाध्याय, रीवा जिले के ग्राम गनिगवां के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहायक ग्रेड तीन महेन्द्र प्रताप सिंह, उमरिया की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिंगुडी के प्रभारी समिति प्रबबंधक रामसुवन गुप्ता, सतना की अमरपाटन तहसील की सेवा सहकारी समिति ताला के प्रबंधक राजेश त्रिपाठी और नगर निगम ग्वालियर के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा शामिल आदि हैं।

मप्र के 105 अधिकारियों कर्मचारियों पर छापा

मप्र में पिछले 4 साल के दौरान लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने 105 अधिकारियों, कर्मचारियों पर छापामार कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की ओर से 24 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। वहीं लोकायुक्त पुलिस द्वारा जो छापामार कार्रवाई की गई उसमें 81 लोगों पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के अनुसार मप्र में घूसखोरी चरम पर है। लोकायुक्त ने प्रदेश में जितने लोगों को पकड़ा है, उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो घूस लेते पकड़ाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जांच एजेंसियों ने जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर छापामार कार्रवाई की है, उनके खिलाफ या तो विवेचना जारी है या फिर मामला अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार के पास लंबित है।

वहीं लोकायुक्त संगठन ने 4 वर्षों में 81 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें होशंगाबाद के सहकारी बैंक बानापुरा के शाखा प्रबंधक सतीश सिटोके, वाणिज्य कर विभाग होशंगाबाद में कराधान सहायक राजेश मालवीय, सिरोंज विदिशा में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन एमएल व्यास, संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश के सहायक दुदीश कुमार राय, गंजबासौदा में जलसंसाधन विभाग के उपयंत्री संतोष परिहार, पुष्पा परिहार, नितिन परिहार, इंदौर में सहायक आयुक्त आबकारी आलोक खरे, मीनाक्षी खरे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी होशंगाबाद के डिवीजनल इंजीनियर समीर कुमार शर्मा उज्जैन नगर निगम के अपर आयुक्त रविन्द्र जैन, नीमच में डिप्टी रेंजर जगदीश चंद्र चौधरी, सहकारी संस्था ग्राम डिगोद के सेल्समेन बलवान सिंह, कृषि उपज मंडी शुजालपुर के लेखापाल परमानंद, सेवानिवृत्त सचिव आनंद मोहन व्यास बड़नगर नगर पालिका के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप किशुक, मनरेगा में सहायक यंत्री जनपद पंचायत सागर बृजेश साहू, मंडला में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संतोष शुक्ला, सहायक समिति प्रबंधक हेतराम पटेल, सेल्समेन आशीष देव पटेल सहित कुल 81 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर करोड़ों रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है। ये आंकड़े यह बताते हैं कि प्रदेश में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जोरों पर है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले तक मप्र की नौकरशाही को देश की भ्रष्ट नौकरशाहों की श्रेणी में रखा जाता था।

● **रजनीकांत पारे**

7 हजार करोड़ की जमीनें सरेंडर

मप्र में इन दिनों भूमाफिया के खिलाफ दनादन कार्रवाई हो रही है। सबसे अधिक कार्रवाई इंदौर में हो रही है। प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ 18 फरवरी को सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। इंदौर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3,250 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई थी। इंदौर जिले में कुल 858 सोसाइटियों में से 128 की शिकायतें मिली थीं। इनमें से 17 भूमाफियाओं पर प्रकरण दर्ज किए गए थे। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर जिला प्रशासन द्वारा महज चार गृह निर्माण संस्थाओं की 6 हजार 890 करोड़ से ज्यादा की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त करवा ली गई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। प्रशासन के इन प्रयासों के चलते 3 हजार से ज्यादा पीड़ित सदस्यों का सपना पूरा होने की उम्मीद बंध गई है जो वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस काम का श्रेय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने इंदौर कलेक्टर **मनीष सिंह को फ्री हैंड दिया।** बस एक इशारा था और कलेक्टर एंटी भूमाफिया अभियान के रोल मॉडल बनकर उभर गए।

इंदौर में इससे पहले तीन बार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा चुका है। संस्थाओं की जमीनों से कब्जे हटाने और रसूखदार भूमाफियाओं पर नकेल कसने की कार्रवाई पहली बार हुई है। यही कारण है कि जिन लोगों ने भूमाफियाओं के प्रभाव में जमीनें खरीद ली वे खुद आगे आकर जमीन सरेंडर करने के आवेदन दे रहे हैं। अभी तक एक दर्जन लोग जमीन छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। इसके पीछे मुख्य कारण भूमाफियाओं के सरगनाओं पर केस दर्ज होने से फैली दहशत है।

गृह निर्माण संस्थाओं की जमीन खरीदने वालों में खासी दहशत फैली हुई है। रसूखदार भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर जमीन खरीदने वाले 12 लोगों ने प्रशासन को जमीन सरेंडर करने का आवेदन दिया है। देवी अहिल्या संस्था, श्रीराम गृह निर्माण, जाग्रति गृह निर्माण संस्था की 44 एकड़ से ज्यादा जमीन छोड़ने की पेशकश खरीदार कर चुके हैं। इस जमीन का बाजार भाव 1700 करोड़ के लगभग है। जमीन सरेंडर के जो आवेदन मिले हैं उनमें देवी अहिल्या संस्था की 9, श्रीराम संस्था की 3 और जाग्रति गृह निर्माण की 2 रजिस्ट्रियां शामिल है।

भूमाफियाओं के खिलाफ पूर्व में भी दो बड़े अभियान चले मगर भूखंड पीड़ितों को अधिक न्याय नहीं मिल सका। मगर इस बार कलेक्टर मनीष सिंह की सख्ती और सूझबूझ के चलते पीड़ितों को मौके पर कब्जे भी मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ चर्चित भूमाफिया भागे-भागे फिर रहे हैं और जिन रसूखदारों ने संस्थाओं की जमीनें अपने नाम करवा ली वे भी एक-एक कर सरेंडर कर रहे हैं। अभी तक 20 लाख स्क्वायर फीट से अधिक संस्थाओं की जमीनें प्रशासन के समक्ष सरेंडर हो चुकी हैं। अब इनकी रजिस्ट्रियां भी कोर्ट के जरिए शून्य करवाई जाएंगी। 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की इन बेशकीमती जमीनों पर भूखंड पीड़ितों को तेजी से कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए मूल्य की और भी जमीनें इसी तरह सरेंडर होंगी, जिनकी जांच-पड़ताल चल रही है, जिसमें प्राधिकरण से अनुबंधित संस्थाओं और उसके बदले मिली जमीनों की जांच भी शामिल है। पहली बार शासन-प्रशासन, पुलिस का एक खौफ अवैध रूप से **जमीनें खरीदने वालों** में नजर आ रहा है।

संस्थाओं की आमसभा भी एक-एक कर आयोजित की जा रही है। आज मजदूर पंचायत और देवी अहिल्या की सभा बुलाई गई है, जिसमें इन सरेंडर की गई जमीनों के संबंध में ठहराव प्रस्ताव किए जाएंगे। पुलिस के हाथ गत दिनों एक और फरार भूमाफिया केशव नाचानी धराया, जिसे उदयपुर के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी तरफ इंदौर हाईकोर्ट ने भी एक अनूठा और अभिनव फैसला दिया, जिसमें जेल में बंद आरोपी से 17 पीड़ितों की रजिस्ट्री करवाने के आदेश दिए। दूसरी तरफ देवी अहिल्या, मजदूर पंचायत, श्री राम गृह निर्माण से लेकर अन्य संस्थाओं द्वारा बेची गई जमीनों को सरेंडर करवाया जा रहा है। बीते 15 साल में इन संस्थाओं की जमीनों को भूमाफियाओं ने ठिकाने लगाया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अयोध्यापुरी से कलेक्टर मनीष सिंह ने शुरू करवाई और यहां पर पीड़ितों को उनके भूखंडों के कब्जे तो दिलवाए, वहीं जिन रसूखदारों ने जमीनें खरीद ली थी, उनसे सरेंडर भी करवाई गई। श्री राम गृह निर्माण की 15 एकड़ जमीन, गुरु कृपा एसेन्स, बीपीए सिविलकॉन से सरेंडर करवाई गई, तो जागृति गृह निर्माण की 26 हजार 400 स्क्वायर फीट जमीन दीप गणेश से और 1 लाख 80 हजार स्क्वायर फीट सविता गृह निर्माण से सरेंडर हुई है। इसी तरह श्री महालक्ष्मी नगर की जमीनें मिरांडा, मनीकरण, मुमेंटम, सन्नी, रजत, बेस्टैग इंडिया से सरेंडर करवाई जा रही है, तो मजदूर पंचायत की केशव नाचानी, मल्हार होटल्स व अन्य से सरेंडर होगी। अयोध्यापुरी की ही केएस ऑइल, पुष्पेन्द्र ठाकुर सहित अन्य से सरेंडर करवाई गई है, जिसके चलते अयोध्यापुरी, पुष्प विहार में ही 700 से अधिक पीड़ितों को मौके पर भूखंडों के कब्जे भी मिल गए हैं।

● **विकास दुबे**

रेवड़ी की तरह बांट दी गई जमीन

इंदौर में भूमाफियाओं के रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम कानून को ताक पर रख गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनें रेवड़ी की तरह बांट दी गई। यह सारा काम डमी अध्यक्षों के हाथ से करवाया जो आज भागते फिर रहे हैं। बॉबी ने सूदन को देवी अहिल्या संस्था का अध्यक्ष बनवाया था जिसके जरिए अयोध्यापुरी कॉलोनी की 8 एकड़ से ज्यादा जमीन भूमाफिया सुरेंद्र संघवी, दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया उर्फ मद्दा, कई केसों में फरार चल रहा भूमाफिया अरूण डागरिया का साला अतुल सुराणा 14 लोगों के नाम कर दी गई। श्री महालक्ष्मी नगर की 37 एकड़ से ज्यादा जमीन सूदन के ही जरिए 10 लोगों को बेची गई। इसी प्रकार मजदूर पंचायत संस्था की पुष्पविहार कॉलोनी में 4 एकड़ से ज्यादा जमीन संस्था मैनेजर नसीम हैदर के हाथों मल्हार होटल्स प्रा.लि. के गुरमीत पिता भगत सिंह छाबड़ा, केशव नाचानी और ओमप्रकाश धनवानी को बेची गई।

बीहड़ में नाइट सफारी

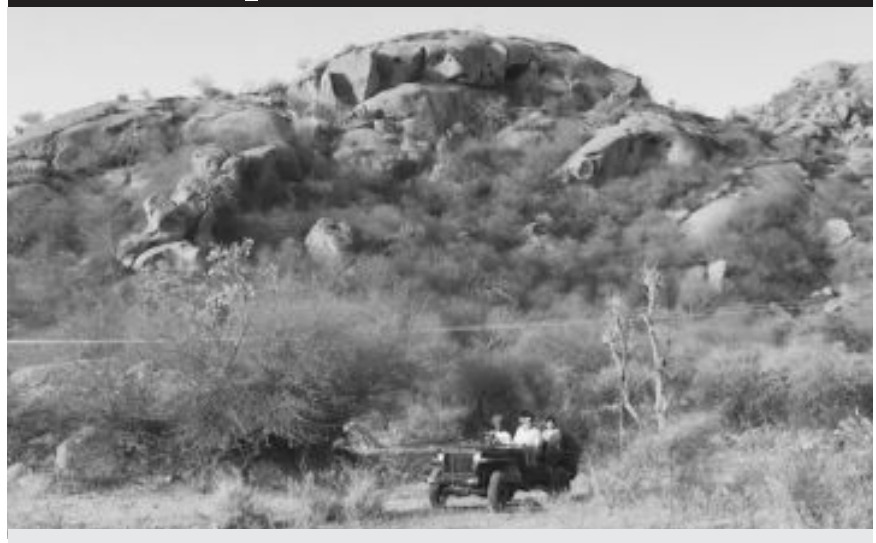

न तो जंगल बचेगा और न ही जंगल में विचरण करने वाले वन्यप्राणी

पन्ना जिले ने देश को यदि इतना बड़ा वन क्षेत्र व बेहतर पर्यावरण दिया है तो इसके बदले में पन्ना को भी प्रतिफल मिलना चाहिए। अन्यथा लाख प्रयासों के बावजूद न तो जंगल बचेगा और ना ही जंगल में विचरण करने वाले वन्य प्राणी। यदि सरकार पन्ना जिले में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं लगा सकती तो कम से कम इसे एजुकेशन हब के रूप में तो विकसित किया ही जा सकता है। यहां की प्राकृतिक आबोहवा और शांतिपूर्ण वातावरण शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है। इसके अलावा पर्यटन के विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना को मिली ऐतिहासिक कामयाबी को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि यहां पर बाघ पुनर्स्थापना का रिसर्च सेंटर खुले ताकि यहां के अनुभवों का लाभ पूरे देश के टाइगर रिजर्वों को मिल सके।

पन्ना टाइगर रिजर्व और केन नदी के जिन बीहड़ों में 14 साल पहले तक डकैतों का आतंक था, वहां अब पर्यटक बगैर किसी डर के नाइट सफारी कर रहे हैं। जिन गांवों और जंगलों में डकैत ठोकिया, मोहन, बलखड़िया, कुंवर का खौफ था, वहां अब होम स्टे, होटल, रिसोर्ट बन गए हैं। जिन लोगों पर डकैतों से तार जुड़ने के आरोप थे, अब पर्यटक उनकी मेहमान नवाजी पसंद कर रहे हैं। डकैतों के एनकाउंटर से इस क्षेत्र की तकदीर बदल गई। 2007 तक यहां के झिन्ना गांव पर कुख्यात डकैत ठोकिया के गिरोह का कब्जा था। उस पर 6 लाख रुपए का इनाम था। उप्र पुलिस को भी उसकी तलाश थी। ठोकिया के खौफ से टाइगर रिजर्व के कर्मचारी भी पेट्रोलिंग नहीं कर पाते थे। यहीं वजह रही कि यहां के बाघों का शिकार हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब इस क्षेत्र को बाघ विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया। फिर ठोकिया का एनकाउंटर हो गया। उसका गिरोह भी खत्म कर दिया गया।

इसके बाद यह क्षेत्र भयमुक्त हो गया। 2009 में यहां फिर से बाघ लाए और अब बाघ का कुनबा इतना बढ़ा कि यहां 60 बाघ हो गए हैं। ये यहां आसानी से दिखाई दे जाते हैं। यहीं वजह कि देशभर के लोग यहां नाइट सफारी के लिए आ रहे हैं। जिसके चलते यहां का पर्यटन उद्योग बढ़ गया है। कोरोनाकाल में यहां विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं लेकिन पिछले कुछ महीने में देश के पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में स्थित झिन्ना गांव के हनुमान मंदिर में डकैत डाक्टर उर्फ ठोकिया की आस्था थी। 2007 में ठोकिया ने मंदिर में भागवत कथा और भंडारा कराया। बदमाशों की दहशत का आलम यह था कि सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब झिन्ना गांव पीटीआर में बफर जोन नाइट सफारी का इंट्री गेट है।

2006 में डकैतों को संरक्षण देने के आरोप में जेल जा चुके रामेश्वर अब मड़ला गांव के एक होटल में चौकीदारी करते हैं। रामेश्वर को डकैतों ने भापतपुरा गांव में घेर लिया था, उन्हें बाजार से टार्च के लिए बैटरी लाने को कहा। रामेश्वर ने बैटरी लाकर ठोकिया गिरोह तक पहुंचा दी। इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामेश्वर कहते हैं अब इलाके हालात बेहतर हैं। दिन में वे घर में खेतीबाड़ी और रात को होटल में चौकीदारी करते हैं। केन नदी के बीहड़ में बसे भापतपुरा, सब्दुआ, हरसा, नहरी, बगौंहा, सलैया, बघा, झिन्ना, टपरियन, बसाटा, मड़ला गांव के कई लोगों की जिंदगी अब बदल गई है। नेशनल हाईवे पर स्थित मड़ला गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व के पर्यटक जोन का इंट्री गेट है। यह पर्यटन का केंद्र बना है। यहां मप्र पर्यटन विकास निगम के होटल के साथ एक दर्जन होटल और रिसोर्ट हैं। मड़ला में बलबीर आदिवासी ने अपने घर में होम स्टे के लिए रूम तैयार कर लिया है। गाइड लखन अहिरवार ने भी घर में होम स्टे के लिए एक कमरा तैयार कर लिया है। इसके अलावा टोरिया, टपरियन, राजगढ़, झिन्ना और बगौंहा के जंगल में भी होटल और रिसोर्ट बन गए हैं।

पर्यटकों के लिए यह सुविधा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पहले से है। अब पन्ना नेशनल पार्क के खूबसूरत जंगल तथा यहां विचरण करने वाले वन्य प्राणियों विशेषकर बाघों का दीदार पर्यटक रात के सन्नाटे में भी कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पन्ना से महज 16 किमी दूर स्थित पन्ना-अमानगंज मुख्य मार्ग के किनारे पन्ना बफर का अकोला गेट है, जिसे नाइट सफारी के लिए खोला गया है। पर्यटक शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक यहां जा सकते हैं। वन परिक्षेत्राधिकारी अकोला बफर लालबाबू तिवारी ने बताया, पर्यटकों को जंगल में नाइट सफारी कराने के लिए जंगल से लगे ग्रामों के युवकों को प्रशिक्षण दिलाकर गाइड बनाया गया है। इस बफर क्षेत्र में जिन लोगों ने भी नाइट सफारी का लुत्फ लिया है उनके अनुभव बेहद उत्साहजनक हैं। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से लगे अकोला बफर का जंगल मौजूदा समय कई बाघों का जहां घर बन चुका है, वहीं एक बाघिन ने तो यहां शावकों को भी जन्म दिया है। यह बाघिन शावकों के साथ जंगल में विचरण करते अक्सर नजर आती है। यही वजह है कि कोर क्षेत्र की ही तरह अकोला बफर भी अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

पन्ना जिले को प्रकृति ने अनगिनत सौगातों से नवाजा है, लेकिन ये खूबियां इस जिले के लिए वरदान साबित होने के बजाय अभिशाप बनी हुई हैं। आजादी के तकरीबन 73 साल गुजर जाने के बाद भी पन्ना जिला जहां अभी भी रेल सुविधा से वंचित है, वही यहां पर औद्योगिक विकास न के बराबर है। इस पिछड़ेपन व गरीबी के लिए यहां के खूबसूरत जंगलों व राष्ट्रीय उद्यान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जिले के लोगों को यह तर्क समझ में भी आता है कि वनों के कारण ही जिले का विकास बाधित है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के जेहन में जंगल के प्रति बैर भाव है। जबकि हकीकत यह है कि यहां की हरी-भरी वादियां व खूबसूरत जंगल यदि उजड़ गया तो पन्ना की सारी खूबी भी तिरोहित हो जाएगी।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

बाघों के घर में घुसपैठ

मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में रह रहे 108 बाघों और सैकड़ों वन्यजीवों की शांति भंग करने की तैयारी हो रही है। खबर है कि राज्य सरकार कान्हा के बफर जोन से सटे रिजर्व फॉरेस्ट में 848.32 हैक्टेयर भूमि पर डोलोमाइट खनन कराना चाहती है। इसके लिए जल्द ई-टेंडर जारी होंगे। जंगल में बसे गांवों में खनन के लिए खनिज विभाग ने डेढ़ महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। उसने पेसा एक्ट 1996 (पंचायत-अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम) की अनदेखी कर गौण खनिज अधिनियम बदले। 31 मेजर मिनरल को माइनर घोषित कराया।

खनन की मंजूरी का अधिकार कलेक्टर को दे दिया। डोलोमाइट अब गौण खनिज हो गया है, जो पहले केंद्र के अधीन मेजर मिनरल की सूची में था। इससे खनन के लिए अब पर्यावरण मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। मामले में प्रदेश के खनिज विभाग के संचालक विनीत ऑस्टिन का कहना है कि नए प्रावधानों से किसी केंद्रीय कानून या फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ, बल्कि खनिज मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनी है। कान्हा के आसपास खनन की अनुमति देने का अधिकार अब तक गोंड आदिवासियों के पास था, लेकिन खनिज विभाग ने डेढ़ महीने पहले नियम बदले और यह हक कलेक्टर को दे दिया।

मप्र गौण खनिज नियम 1996 के अनुसार राज्य द्वारा गौण खनिजों के लिए तीन प्रकार के खनिज अधिकार मिलते हैं, जो खान का पट्टा, नीलामी और अस्थाई अनुज्ञा हैं। इसके दायरे में वे खनिज आते हैं, जिनका राजस्व राज्य सरकार के पास जमा होता है और केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। 2015 में केंद्र सरकार ने डोलोमाइट सहित 31 बड़े खनिजों को गौण के रूप में नए सिरे से परिभाषित किया था। इसी आधार पर विभाग ने 22 जनवरी को गौण खनिज नियम बदले हैं।

डोलोमाइट को माइनर मिनरल की सूची में डाला, ताकि पर्यावरण की मंजूरी न लेनी पड़े। विभाग के इस खेल का खुलासा तब हुआ, जब मंडला जिला प्रशासन ने जिला पंचायत के जरिए बिछिया तहसील के भंवरताल, काताजर, कातामाल, चंद्रपुरा की ग्राम सभाओं से डोलोमाइट खनन के लिए ई-टेंडर जारी करने के लिए अभिमत मांगा। प्रशासन 11 स्थानों पर खनन करना चाहता है, जिस पर ग्राम सभाओं ने आपत्तियां लगाई हैं। ये गांव कान्हा के उत्तर-पश्चिमी छोर पर हैं और गोंड आदिवासी बहुल होने के चलते **संविधान की पांचवीं अनुसूची** में आते हैं। इसलिए यहां पेसा एक्ट लागू है और किसी भी तरह के खनन के लिए प्रशासन को ग्राम सभाओं से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन, खनिज विभाग ने एक्ट के प्रावधानों को अनदेखा कर खनन की मंजूरी के अधिकार कलेक्टर को दे दिए।

अब कलेक्टर ग्राम सभा को नोटिस देकर सूचित करेगा। अभिमत लेगा। अभिमत नहीं मिला तो उसे डीम्स अनुमति माना जाएगा। अधिनयम में नई धारा 18 ए (2) जोड़ी, जिसे कलेक्टर सुझाव-आपत्ति सुनेगा। इसी नियम के आधार पर मंडला कलेक्टर ने अभिमत मांगा है। मंडला के पर्यावरण कार्यकर्ता विभूति झा कहते हैं कि भंवरताल, काताजर में निस्तार जमीन बफर जोन से सटा क्षेत्र है। कान्हा में बाघों की संख्या ज्यादा है और जगह कम पड़ रही है। इसलिए यहां टेरिटोरियल फाइट और इंसानों-बाघों की भिड़ंत की स्थिति हमेशा रहती है। 2015 से 2021 के बीच बाघों और तेंदुओं ने पार्क के बाहर 131 पालतू पशु मारे। ये वे मामले हैं, जिनमें वन विभाग ने मुआवजा दिया है। यदि यहां हजारों हैक्टेयर में खनन होगा तो न केवल जंगल काटा जाएगा, बल्कि वायु-ध्वनि प्रदूषण से पार्क की जैव विविधता और पर्यावरण भी खतरे में पड़ जाएगा।

कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मप्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान कान्हा क्षेत्र को क्रमशः 250 और 300 किमी दो अभयारण्यों, हॉलोन और बंजार में विभाजित किया गया था। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज यह दो जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किमी के क्षेत्र में फैला है। यह इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए शीर्ष 10 प्रसिद्ध स्थानों में से एक हैं। पार्क में टाइगर, भारतीय तेंदुओं, सुस्त भालू, बारहसिंघा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। रूडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाए गए जंगल को कुछ लोगों द्वारा इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित माना जाता है। यह आधिकारिक रूप से शुभंकर 'भूरसिंह द बारहसिंघा' पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

बफर जोन के पास खनन

प्रदेश में खनन माफिया किस कदर हावी है इसकी बानगी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास देखने को मिल रही है। टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से लगे संवेदनशील क्षेत्र जाजागढ़ के पिपहि नदी का सीना चीरने में लगा रेत माफिया का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि यहां रेत खनन में खुलेआम मनमानी कर पानी के अंदर से रेत निकाली जा रही है। जानकार बताते हैं कि जाजागढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का संवदेनशील क्षेत्र है, यहां वन्यप्राणियों का मूवमेंट बना रहता है। जंगल के अंदर तक नदियों से रेत खनन से पानी का बहाव प्रभावित होगा। नदी का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा और इसका सीधा असर वन्यप्राणियों के विचरण और उनके जीवन पर पड़ेगा। रेत के मनमाने खनन पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कटनी जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी आमने-सामने हैं। दोनों विभाग के अफसर एक-दूसरे पर जवाबदेही की बात कहकर कार्रवाई से करने से बच रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विसेंट रहीम ने बताया कि जाजागढ़ स्थित पिपहि नदी में रेत खनन बफर एरिया या संवदेनशील क्षेत्र में होगा तो कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई भी, बिजली भी

जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को लेकर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ दोनों प्रदेशों के बीच पानी को लेकर चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। अब बुंदेलखंड की जनता को सिंचाई से लेकर जल विद्युत का लाभ मिलेगा। पेयजल भी मिलेगा और सूखे का संकट खत्म हो जाएगा। इस परियोजना से सिंचाई समेत पेयजल और जलविद्युत का लाभ मिलेगा। प्रति वर्ष 10.62 लाख हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी और लगभग 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति होगी। इसके अलावा 103 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन होगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना दो राज्यों मप्र और उप्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है। संयुक्त परियोजना होने के कारण दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का भी प्लान तैयार किया गया है। इसमें हर साल नवंबर से अप्रैल माह के बीच (नॉन मानसून सीजन) में उप्र को 750 एमसीएम तो वहीं मप्र को 1834 एमसीएम पानी मिलेगा। इन सभी बिंदुओं पर दोनों राज्य सरकारों का केंद्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। इसी समझौते को एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर डोढ़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में चार बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना करीब 10.62 लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना में दो बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट है।

राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा देश में प्रस्तावित 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक केन-बेतवा लिंक परियोजना भी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 45000 करोड़ है, जिसका 90 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दाऊधन डैम बनाया जाएगा और एक नहर के जरिए दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा।

मप्र में छतरपुर व पन्ना जिलों की सीमा पर केन नदी के मौजूदा गंगऊ बैराज के अपस्ट्रीम में 2.5 किमी की दूरी पर डोढ़न गांव के पास एक 73.2 मीटर ऊंचा ग्रेटर गंगऊ बांध बनाया जाएगा। कांक्रीट की 212 किमी लंबी नहर द्वारा केन नदी का पानी उप्र के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित बरुआ सागर में डाला जाएगा। यह परियोजना बूंद-बूंद को तरसते बुंदेलखंड के लिए एक उपहार है। सालों से पानी की किल्लत से जूझ रहे क्षेत्र के लिए बौछार है। इस परियोजना में मप्र के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं तो उप्र के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट केन-बेतवा लिंक परियोजना को लगभग 16 साल बाद दोनों राज्यों की आपसी सहमति हुई है। यह परियोजना छतरपुर, पन्ना सहित मप्र और उप्र के बुंदेलखंड वाले हिस्से को हरित क्षेत्र बनाने के रूप में देखी जा रही है। परियोजना का बजट 35,111 करोड़ रुपए है जिसके अंतर्गत पन्ना टाईगर रिजर्व क्षेत्र में मौजूद डोढ़न गांव में एक विशाल बांध बनाया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना की मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इसे दो चरणों में पूरा किया जाना था। जल संसाधन मंत्रालय ने मूल परियोजना रूपरेखा में परिवर्तन करते हुए अब दोनों चरणों को एक साथ मिला दिया है। जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय द्वारा केन-बेतवा लिंक के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाने का फैसला मप्र सरकार के आग्रह पर किया गया है। इसके कारण इस परियोजना के संबंध में कुछ आवश्यक मंजूरी पर मंत्रालय काम कर रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना में चार बांध बनाए जाएंगे। डोढ़न बांध के अलावा तीन और बांध भी मप्र के रायसेन और विदिशा में बेतवा नदी पर बनेंगे। केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा व 19633 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षमता वाले इस डोढ़न बांध में 2584 एमसीएम पानी भंडारण की क्षमता होगी। 2613.19 करोड़ की लागत वाले इस बांध से दो बिजली घर बनेंगे जिससे 36 मेगावाट बिजली बनेगी। इस बिजली घर पर 341.55 करोड़ की राशि व्यय होगी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

2005 में अक्स ने उठाए थे सवाल

केन-बेतवा परियोजना को लेकर अक्टूबर 2005 में मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, तब अक्स ने उस पर सवाल उठाए थे। अक्स ने

आशंका जताई थी कि यह एमओयू कागजी न साबित हो जाए। हुआ भी यही। अब दोबारा इस पर एमओयू हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार परियोजना आकार लेगी। लेकिन इस बार भी इस परियोजना में कई तरह की विसंगतियां हैं। इस बांध के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व की 5258 हैक्टेयर जमीन सहित कुल 9 हजार हैक्टेयर जमीन डूब जाएगी। इस जमीन पर बसे सुकुवाहा, भावर खुवा, घुगारी, वसोदा, कुपी, शाहपुरा, डोढ़न, पल्कोहा, खरयानी और मेनारी गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में सत्ता किसके हाथ लगेगी यह 2 मई को ही स्पष्ट होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बीच हो रहे चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ ही जनता के लिए भी अग्निपथ से कम नहीं हैं। एक तरफ जहां देशभर में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में कोरोना गाइडलाइन पूरी तरह दरकिनार है। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या कोरोना चुनावी नारों से डर रहा है?

● राजेंद्र आगाल

चुनाव गणित का खेल है मगर इसमें 'केमिस्ट्री' गणित पर हावी हो जाती है। इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हो रहे विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। चुनावी गणित के अनुसार इन पांचों राज्यों में चुनाव के दौरान बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, जो कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। लेकिन चुनावी केमिस्ट्री उस गणित पर हावी है। यानी कोरोना महामारी के बावजूद यहां चुनाव कराया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश में लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में गाइडलाइन पूरी तरह दरकिनार है। ऐसे में पूरा देश अग्निपथ बना हुआ है। इस अग्निपथ पर चलकर देश कितना सुरक्षित रहेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। आज भारत कोरोना संक्रमण के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया है। फिर भी देश अग्निपथ पर चल रहा है।

दरअसल, चुनावी गणित में केमिस्ट्री का प्रयोग आधुनिक भारत के निर्विवाद 'चुनाव गुरु' नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भरपूर किया है। पिछले 7 वर्षों से इधर-उधर मिले एक-दो झटकों को छोड़ चुनावों में भाजपा का पलड़ा जिस तरह भारी रहा है उसके चलते यह एक तरह से स्वयंसिद्ध सत्य बन गया है। मोदी और शाह का कहना यह है कि कुछ सामाजिक या जातीय **समूहों और उनके संख्याबल** पर विपक्ष की निर्भरता बेमानी है। काम तो करती है भाजपा (यानी मोदी) और मतदाताओं के बीच की 'केमिस्ट्री', जो जनहित योजनाओं, व्यक्तिपूजा आदि से बनती है और जातीय समीकरणों से ऊपर होती है। आज अपनी इसी केमिस्ट्री के दम पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जो भी हो, अमित शाह आज जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने में व्यस्त हैं, उन्हें असम में अपनी कमजोरियों का जरूर एहसास होगा। दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग में रिकार्ड मतदान ने पार्टियों को असमंजस में डाल दिया है। जहां पश्चिम बंगाल में 80 फीसदी मतदान हुआ है, वहीं असम में 72 फीसदी।

बंगाल पर सबका फोकस

2021 विधानसभा चुनाव असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव केवल बंगाल में ही हो रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि भाजपा ने अपनी सारी ताकत बंगाल में झोंक दी है। इसी के चलते बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प और कांटेदार हो चुकी है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की **परेड ग्राउंड में चुनावी रैली** के बाद बंगाल में चुनाव प्रचार ने और तेजी पकड़ी है। भाजपा ने बंगाल में कई कद्दावर नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को ममता के खिलाफ उतारकर मुकाबले को कांटे का बना दिया है। भाजपा समेत तृणमूल, कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में होने जा रहा है। नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि ममता अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया की निगाहें नंदीग्राम सीट पर टिक गई हैं। वास्तव में नंदीग्राम ने ही ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाया था। इस वजह से यह उनके लिए काफी भाग्यशाली रहा है। लेकिन नंदीग्राम के जरिए ममता को सत्ता दिलाने में अधिकारी की अहम भूमिका थी।

बंगाल में नए रंग और मोड़

भयंकर खेला होबे, एई माटी ते खेला होबे (भयंकर खेल होगा, इसी मिट्टी में खेल होगा)। हाल की एक रैली में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के इस बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य का जवाब था कि जो भयंकर खेल की चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें चुनाव के बाद अपने ड्राइंग रूम में बैठकर लुडो खेलने का ढेर सारा समय मिलेगा। ये आरोप-प्रत्यारोप साफ संकेत हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो गरमी ऊपर यानी बड़े नेताओं से नीचे कार्यकर्ताओं तक उतर रही है, उसमें कितनी आंच है। यह आंच कई रूपों में प्रकट हो रही है, जिसके अक्स नारों, तुकबंदियों, गीतों के जरिए हर जुबान पर खिलने लगे हैं। यूं तो हर कहीं, हर बार चुनाव नए रंग और लय के दर्शन कराते हैं, लेकिन बंगाल में नारों, तुकबंदियों, दीवाल लेखन के रंग तो लाजवाब हैं। इन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के महासचिव देबांग्शु भट्टाचार्य ने कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर के गीत 'मोदेर जेमोन खेला, तेमनी जे काज' (हमारा जैसा खेल, वैसा ही काम) की तर्ज पर 'खेला होबे' गीत बनाया, जो अब इन चुनावों का सबसे चमकदार नारा बन गया है। जवाब में भाजपा ने 'खेलार माठे लड़ाई होबे' (खेल के मैदान में लड़ाई होगी) और 'पीशी जाओ' (बुआ जाओ) की तुकबंदी आगे बढ़ाई। उधर, वाम मोर्चे तथा माकपा ने 'टुम्पा, तोके निए ब्रिगेड जाबो' (टुम्पा, तुझे लेकर ब्रिगेड जाऊंगा) और 'लाल फेराओ, हाल फेराओ' (लाल लौटाओ, स्थिरता लाओ)। जाहिर है, इन नारों या तुकबंदियों में कौन सबसे अधिक जुबान पर चढ़ता है, शायद उससे भी संकेत मिलता है कि हवा का रुख क्या है। हवा का यह रुख किधर जोरदार है या आगे होता जाएगा, यह तो 2 मई को नतीजे के दिन पता चलेगा लेकिन अभी तक रिकार्ड मतदान ने सभी को असमंजस में डाल दिया है। इस कारण चुनावी पैंतरेबाजी और तेज हो गई है।

वहीं बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में आने से पार्टी को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। भाजपा ने उन्हें क्या सोचकर अपनी नाव में सवार किया ये तो उसके रणनीतिकार ही जानते होंगे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के साथ मंच देकर पार्टी ने ये संकेत तो दे ही दिया कि उनमें उसे तुरुप का इक्का दिखाई दे रहा है। बंगाल की सियासत और समाज दोनों पर फिल्मों व साहित्य का जबर्दस्त असर रहा है, शायद इसलिए भाजपा ने मिथुन दादा को अपने साथ जोड़ा है। पूरी तस्वीर देखें तो अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। तृणमूल, भाजपा और लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन के बीच। ऐसा नहीं कि लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में पहली बार साथ आए हों। इससे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए थे। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि ममता सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही हैं। अगर उनके साथ मिलकर गठबंधन करते तो शायद कांग्रेस और लेफ्ट का राजनीतिक **अस्तित्व खत्म हो जाता।** यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने तृणमूल को चुनौती देने के लिए एक होना सही समझा। वैसे लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन के लिए भाजपा सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल गठबंधन दोनों पार्टियों से ही समान दूरी बनाकर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन उनकी इस रणनीति से तृणमूल को नुकसान होगा या फिर भाजपा को ये अभी कह पाना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भाजपा का हिंदू वोट है और कांग्रेस का भी है। उसी तरह से तृणमूल के पास भी मुस्लिम वोट हैं तो लेफ्ट के पास भी मुस्लिम वोटर हैं। ये गठबंधन दूसरी पार्टी के वोट काटेंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बंगाल में भाजपा की बढ़त ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।

चुनाव कई मायनों में अलग

इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव पिछले चुनावों से कई मायनों में अलग हैं। अलग इसलिए, क्योंकि इस चुनाव में सत्ताधारी दल के सामने एक ऐसा दल चुनौती बनकर उभरा है, जिसे 2016 के चुनाव में सिर्फ 10.3 फीसदी वोट और केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी। इसके ठीक 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली। बंगाल के लिहाज से यह चुनाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2016 के जनादेश में वाम-कांग्रेस गठबंधन प्रमुख विपक्षी दल के रूप में थे, जो इस बार के चुनाव में भी असरहीन नजर आ रहे हैं। भाजपा की बड़ी कामयाबी यह है कि उसने बहुत कम समय में प्रमुख विपक्षी दलों, वाम-कांग्रेस गठजोड़, को हाशिए पर धकेलकर स्वयं को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बरक्स प्रभावी विकल्प के तौर पर स्थापित किया है। अब सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में बंगाल में बदलाव का विकल्प बनने की भाजपा की कोशिश सफल होगी? पिछले दो-तीन वर्षों में यहां की राजनीति में हुए बदलावों तथा इस चुनाव में भाजपा के लिए जीत की संभावनाओं का आधार समझने के लिए कुछ तथ्यों पर गौर करना होगा। चुनावी राजनीति के इतिहास का विश्लेषण करने पर बंगाल में सत्ता परिवर्तन का एक पैटर्न नजर आएगा। इसका मूल यह है कि वहां के मतदाताओं के मन में बदलाव की अकुलाहट होना पर्याप्त नहीं होती। विकल्प का आत्मविश्वास पैदा होना भी जरूरी कारक है।

विपक्ष का मजबूत गणित

मोदी-शाह का 'केमिस्ट्री बनाम गणित' वाला जो चुनावी सिद्धांत है उसकी कड़ी परीक्षा पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर-पूर्वी राज्य असम में होने जा रही है। इस परीक्षा को व्यापक, राष्ट्रीय संदर्भ इस तथ्य से मिलता है कि भाजपा अपने सहयोगियों का जिस तरह इस्तेमाल करके खारिज करती रही है उसके कारण असम में विपक्ष का गणित मजबूत हुआ है। असम में राजनीतिक समीकरण के उलटफेर के कारण बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में वापस शामिल हो गया है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस से अलग होकर **भाजपा से हाथ मिला लिया था।** इसकी जगह, बीपीएफ की प्रतिद्वंद्वी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल), जो 2016 में कांग्रेस के साथ थी, अब भाजपा के साथ हो गई है। बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले उस गठबंधन के साथ है, जिसमें 3 वाम दल और 4 छोटी पार्टियां शामिल हैं। जैसी कि स्थिति है, एनडीए के सहयोगियों, भाजपा, बीपीएफ, और असम गण परिषद ने मिलकर 41.59 प्रतिशत वोट बटोरे थे, अब कांग्रेस की साथ आ गई बीपीएफ ने तब 3.94 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। 2016 में वोटों के बंटवारे में बीपीएफ के वोटों को अगर एनडीए के वोटों में से घटा दिया जाए तो 2016 में उसका वोट 38 प्रतिशत रह जाता है। यूपीए के जो आज घटक हैं (कांग्रेस, एआईयूडीएफ, बीपीएफ, वाम दल और अन्य) उन्होंने 2016 में 49 फीसदी वोट हासिल किए। इस तरह दोनों बड़े गठबंधनों के वोटों में 11 प्रतिशत का अंतर भाजपा की नींद जरूर खराब कर रहा होगा। उधर, कांग्रेस का परचम लहराने के लिए राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला है। खासकर प्रियंका गांधी के कारण वहां कांग्रेस में अजब का उत्साह दिख रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी टीम के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं।

पुडुचेरी में भाजपा का रिहर्सल

तमिलनाडु की राजनीति का उसके पड़ोसी, छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बहुत कम असर होता है। 20 लाख मतदाताओं वाले इस पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में कांग्रेस या उससे निकली एनआर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इससे अधिक मतदाता तो तमिलनाडु के कई नगर निगमों में हैं। यहां भाजपा की पहली राजनीतिक चाल किरण बेदी को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करना था, जिनकी कांग्रेस मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के साथ लगातार लड़ाई चली। आखिरकार कुछ दिनों पहले भाजपा ने आखिरी प्रहार किया। कांग्रेस के कई विधायकों के इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भाजपा को उम्मीद थी कि पूर्व पीडब्लूडी मंत्री ई. नामसिवयम को वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी सहयोगी एनआर कांग्रेस इसका विरोध करेगी। एनआर कांग्रेस के प्रमुख एन. रंगास्वामी दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब रंगास्वामी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तब जाकर भाजपा ने सुर बदला, और वह उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने पर राजी हुई। कांग्रेस के कमजोर पड़ने और रंगास्वामी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा को लगता है कि यहां एनडीए की सरकार बन जाएगी। भाजपा पहली बार सरकार का हिस्सा बनेगी। हालांकि यहां अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसे अभी इंतजार करना पड़ेगा। तमिलनाडु के एक भाजपा नेता कहते हैं कि तमिलनाडु में बड़ा कदम रखने से पहले पुडुचेरी हमारे लिए रिहर्सल की तरह हो सकता है।

जनहित योजनाओं के जरिए एनडीए की केमिस्ट्री

भाजपा के नेता कांग्रेस पर एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल से हाथ मिलाने के लिए हमले करके मतदाताओं को हिंदू-मुस्लिम आधार पर ध्रुवीकृत करने की कोशिश में जुटे होंगे, मगर लोगों को भाजपा सरकार की जनहित वाली **योजनाएं आकर्षित कर रही हैं।** असम के कई जिलों में लोगों से यही उजागर हुआ कि लोग सर्बानंद सोनोवाल की सरकार से संतुष्ट हैं। 'ओरुणोदोई' योजना (जिसके तहत हर चुनाव क्षेत्र में 15 से 17 हजार के बीच महिलाओं को हर महीने बैंक खाते में सीधे 830 रुपए जमा हो रहे हैं) से लेकर छात्राओं के लिए स्कूटर और साइकिल देने के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए तमाम तरह की योजनाओं की बहार है। इन सबके ऊपर से केंद्रीय योजनाएं भी हैं।

चुनावी राज्यों में कोरोना पर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों?

कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये एक बड़े खतरे की ओर इशारा है। ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत वर्तमान में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में कोरोना के 3 करोड़ मामले हो चुके हैं और साढ़े 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि ब्राजील में 1 करोड़ 20 लाख संक्रमण के मामले अब तक सामने आए हैं और 2 लाख 93 हजार मौतें हुई हैं। भारत में 1 करोड़ 16 लाख संक्रमण के मामले आए हैं और 1 लाख 60 हजार मौतें हुई हैं। चिंता की बात यह है कि चुनाव वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल से कोरोना मामलों का लगातार ताजा अपडेट नहीं मिल रहा है। हाल में आई खबरों में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। जिसमें 500 से अधिक कोरोना के नए मामले आने की बात कही गई थी। ममता सरकार पर कोरोना के मामले छिपाने का आरोप भी लगता रहा है। बावजूद इसके इस चुनावी राज्य में कोरोना को लेकर संवेदनशील तरीके से नहीं निपटा जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल लोगों की ट्रेसिंग जांच की व्यवस्था भी कारगर ढंग से नहीं हो रही है और केंद्र सरकार के निर्देशों पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। ममता सरकार की यह लापरवाही अन्य राज्यों में कोरोना फैलने का कारण भी बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही चिंता का इजहार करते हुए कह चुके हैं कि अगर गांवों में कोरोना फैलता है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। केरल में कोरोना 1239 ताजा मामले सामने आए हैं। राज्य के कई जिलों जैसे कन्नूर, कोझिकोड, कोल्लम, एरनाकुलम और वायनाड में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। चुनाव के दौरान लोगों को संक्रमण फैलने से बचाना राज्य सरकार की बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क न पहनने वाले उम्मीदवारों और नेताओं को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने इन नेताओं को चुनाव-प्रचार से प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका विक्रम सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विराग गुप्ता ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के दिशा-निर्देशों पर अमल नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी करने का विरोध किया है। निर्वाचन आयोग की ओर से वकील पंकज चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहे हैं। मास्क संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना राज्यों के जिला स्तर के अधिकारियों का काम है। सिर्फ चुनाव आयोग का दफ्तर दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

केरल में अभी कमल कोसों दूर

केरल में ऐसा क्या है जो, भाजपा के लिए मुश्किल पैदा करता है? केंद्र में सत्तारूढ़ दल, एलडीएफ शासित राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस सवाल से दो-चार हो रहा है। तिरुवनंतपुरम में एक चुनावी सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में केरल का उल्लेख सामाजिक सुधार की भूमि के रूप में किया। सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के चेयरमैन डी. धनुराज कहते हैं, यहां सुर मद्धिम थे, पश्चिम बंगाल के भाषणों की तरह आक्रामकता नहीं थी। भाजपा समझ गई है कि सांप्रदायिक बयानबाजी से यहां मदद नहीं मिलेगी। शाह ने लोगों को माकपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चों को वोट देने के पुराने पैटर्न से बाहर निकलने का आह्वान किया। 88 वर्षीय टेक्नोक्रेट ई. श्रीधरन जैसे विश्वसनीय चेहरे को लाकर पार्टी ने केरल में राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है। राजनीतिक पर्यवेक्षक जोसेफ मैथ्यू कहते हैं, श्रीधरन जैसा लोकप्रिय चेहरा पार्टी को उस समाज में स्वीकार्यता दिलाएगा जहां कभी इसे राजनीतिक अछूत माना जाता था। लेकिन श्रीधरन कितने वोट दिला पाते हैं, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि मलयाली नायकों की पूजा करने के लिए नहीं जाने जाते। 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मुख्य मुकाबला तो माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच होगा, भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन कहते हैं, त्रिपुरा में हम शून्य सीटों से सत्तारूढ़ पार्टी बन गए। यहां भी हमें 35-40 सीटें जीतने और सरकार बनाने का भरोसा है। चुनाव के बाद कांग्रेस, माकपा और दूसरी पार्टियों से लोग भाजपा में आएंगे।

असम में कड़ी टक्कर के दांव

इस बार विधानसभा चुनावों में एक पार्टी छोड़कर बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं की कतार लगी हुई है। लेकिन असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखी बात हुई है। इस सीट पर विधायक अजंता नियोग भाजपा की उम्मीदवार हैं। उनके सामने चिर प्रतिद्वंद्वी बिटोपन सैकिया हैं, जिन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मजे की बात यह है कि 2016 के चुनाव में नियोग कांग्रेस की प्रत्याशी थीं और सैकिया भाजपा से लड़े थे। नियोग कुछ ही दिनों पहले भाजपा में चली गईं। नाराज सैकिया कांग्रेस में चले गए और अब उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोलाघाट की यह घटना बताती है कि इस बार असम विधानसभा चुनावों में किस तरह राजनीतिक उलटफेर हो रहे हैं। भाजपा जीतने योग्य नेताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है तो विपक्षी दल उन नेताओं पर दांव आजमा रहे हैं, जिन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला। असम पारंपरिक रूप से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में यहां भाजपा को जीत हासिल हुई थी। 5 साल बाद भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। भले ही वह इसे स्वीकार न करे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले 8 दलों के गठबंधन, जिसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल है, को लगता है कि 2 मई को आने वाले नतीजों में उसे बहुमत मिल सकता है।

प्रदेश की सर्बानंद सोनोवाल सरकार के पीछे असली ताकत कहे जाने वाले मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ मिलकर भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सरमा का गणित शायद ही कभी गलत होता हो, तब भी जब वे 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सरमा में एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसी कड़ी में उसने पुराने साथी बोडो पीपुल्स फ्रंट को छोड़कर यूपीपीएल को नया साथी बनाया है।

भाजपा ने अभी तक सोनोवाल को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया है। पार्टी प्रवक्ता रितु बरन सरमा कहते हैं, जब हमारे पास एक मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जरूरत नहीं रह जाती है। उनका यह बयान जवाब से कहीं ज्यादा

सवाल खड़े करता है। एक सवाल सीधे हेमंत बिस्वा सरमा से जुड़ा है। पहले कई मौकों पर चुनाव नहीं लड़ने की बात वे कह चुके हैं। फिर भी भाजपा ने जुलुकबाड़ी सीट से 52 साल के सरमा को उम्मीदवार बनाया है। उनकी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश किसी से छिपी नहीं है। उनके कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह यही थी। तब पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने लगे थे।

सरमा समर्थकों को उनके मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश में कुछ भी गलत नहीं लगता। प्रदेश में अनेक लोगों को लगता है कि विपक्ष का मुकाबला करने और उनके किले ध्वस्त करने में मुख्य भूमिका सरमा की ही है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बाद 2020 की शुरुआत में असम में भाजपा के खिलाफ माहौल बनने लगा था। अनेक जगह विरोध प्रदर्शन और हिंसा भी हुई। तब भाजपा विरोधी माहौल को बदलने में सरमा ने ही मुख्य भूमिका निभाई। रितु बरन कहते हैं, यह चुनाव इस बात को लेकर लड़ा जाएगा कि हमने राज्य के लिए क्या किया है। सीएए ठंडे बस्ते में चला गया है। अब यह कोई मुद्दा नहीं है।

तमिलनाडु में बीज बोने की कोशिश

कई साल पहले तक तमिलनाडु में भाजपा का निकटतम प्रतिद्वंद्वी नोटा हुआ करता था। 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 3 फीसदी वोट मिले थे और तब भाजपा पहचान के संकट से गुजर रही थी। आज वही भाजपा शशिकला फैक्टर की वजह से उत्पन्न हुए संकट को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले तो उसने ऑल इंडिया अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के दोनों धड़ों के बीच दूरी पाटने की कोशिश की। जब वह संभव न हो सका तो पार्टी ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। भाजपा ने शशिकला को राजनीतिक परिदृश्य से हटने के लिए राजी कर लिया, इस संदेश के साथ कि एआईएडीएमके के सभी कार्यकर्ता डीएमके को हराने के लिए मिलकर लड़ेंगे। यह मास्टरस्ट्रोक तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते राजनीतिक कद को भी दिखाता है। विधानसभा में 234 सीटें हैं और पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर वह कुछ प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रही तो दो राजनीतिक ध्रुवों वाले प्रदेश में उसका महत्व और बढ़ जाएगा। देखा जाए तो पड़ोसी राज्य केरल की तुलना में तमिलनाडु में भाजपा का चुनावी रिकॉर्ड बेहतर रहा है। 1988, 1989 और 2014 में उसने गठबंधन में चुनाव लड़ा और उसके सांसद चुने गए थे। डीएमके की अगुवाई में 2001 के विधानसभा चुनाव में इसके कुछ विधायक भी चुने गए। उसके बाद डीएमके ने 2004 में कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उसके बाद भी लोकसभा चुनावों में भाजपा को सहयोगी मिले। 2004 में उसने एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ा। 2014 में पीएमके, डीएमडीके और एमडीएमके जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर यह चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे कोई सफलता नहीं मिली। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हकीकत को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हमारी मौजूदगी से विधानसभा चुनावों में हमारे सहयोगी दलों को अतिरिक्त वोट नहीं मिले। जब जयललिता थीं तब भाजपा समर्थक भी उनकी एआईएडीएमके को वोट देते थे ताकि डीएमके को हराया जा सके। जयललिता की मौत के बाद 2017 में भाजपा ने जिस तरह ईके पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम के बीच समझौता करा एआईएडीएमके सरकार को स्थिरता दी, उसने प्रदेश की **राजनीतिक दिशा तय करने में** केसरिया पार्टी की भूमिका बढ़ा दी। हालांकि इस समीकरण का 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई फल नहीं दिखा। इसके बावजूद पार्टी ने प्रदेश में अपना आधार मजबूत करने का सिलसिला जारी रखा। उसने दलित को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और फिर दूसरे दलों के जाने-माने चेहरों को शामिल करने लगी। उनमें फिल्म सेलेब्रिटी से लेकर मजबूत आधार वाले नेता भी थे। अब यहां स्थिति बदल गई है। भाजपा अपना आधार मजबूत कर रही है। इसमें उसको कितनी सफलता मिलती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

उधर, अब देखना यह है कि चुनावी अग्निपथ पर चल रहे इस देश में कोरोना महामारी का यह दौर क्या गुल खिलाता है। देश में कोरोना का संक्रमण गत वर्ष की अपेक्षा दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस रफ्तार के बीच चुनावी राज्यों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इन राज्यों में मतदान के बाद यहां के लोग अन्य राज्यों में जाएंगे। इससे कोरोना का संक्रमण और बढ़ने का डर बना हुआ है।

ममता बनर्जी की कोर वोटर पर मोदी का फोकस

65 वर्षीय गीता पाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र दक्षिण कोलकाता, जिसे छोड़कर वह इस विधानसभा चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम से मैदान में उतरी हैं, के भवानीपुर (पहले भोवानीपोरा कहा जाता था) में रहती हैं। गीता कुम्हार जाति की है और गणेशजी-लक्ष्मीजी की मूर्तियां बनाया करती थीं। हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ आई बीमारियों के कारण उसका काम धीमा पड़ गया है। लेकिन उसे अब तक स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं मिला है जिसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था। इसकी वजह से ही बंगाल ने नरेंद्र मोदी सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना को लागू नहीं किया है। वह दावा करती है कि 'दीदी' की तरफ से 10 साल के शासनकाल के दौरान महिलाओं के लिए घोषित की गई तमाम योजनाओं का उसे कोई लाभ नहीं मिला है। गीता की ही रिश्तेदार सोनिका पाल ने बताया कि राज्य सरकार की एक योजना के तहत आवास अनुदान के लिए उसने कागजात जमा किए थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। भवानीपुर में ही रहने वाली सुनीता पाल ने कहा कि वादे के तहत 10 किलो राशन की जगह उसे 5 किलो राशन ही मिल रहा है। भवानीपुर बाजार में मछली बेचने वाली 45 वर्षीय संगीता कहती हैं, '35 साल हमने वामपंथियों को देखा। हमने ममता के 10 साल का शासन देखा। मोदी को 5 साल देने में बुरा क्या है? लॉकडाउन के दौरान मैं राशन कार्ड के लिए एक से दूसरे कार्यालय भटकती रही लेकिन मुझे यह नहीं मिला।'

...तो सरकार क्या करेगी?

केंद्रीय मंत्रिमंडल से पारित होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए एक विधेयक के बाद दिल्ली में अधिकारों को लेकर केजरीवाल की आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर टकराव होना निश्चित है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी द्वारा गत दिनों लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल (एलजी) होगा और हर काम के लिए दिल्ली सरकार को पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी।

इस विधेयक के कानून बनने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में काफी इजाफा हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद दिल्ली में सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि विधेयक में साफ कहा गया है कि दिल्ली में सरकार का अर्थ 'एलजी' होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की **ताकत एलजी** रखेगा। यही नहीं बिल में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशविरा लेना होगा। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई, 2018 को दिए अपने एक फैसले में कहा था कि प्रदेश सरकार के दैनिक कामकाज में उपराज्यपाल की ओर से दखल नहीं दिया जा सकता।

गृह मंत्रालय द्वारा पेश उक्त बिल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके जरिए भाजपा पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से दिए गए फैसले के विपरीत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा कि, 'दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटें और एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न पाकर रिजेक्ट हुई भाजपा ने अब पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत उसने लोकसभा में बिल पेश किया है। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक **बेंच के फैसले के खिलाफ** है। हम भाजपा के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करते हैं।'

एक अन्य ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, 'बिल कहता है कि सरकार का अर्थ एलजी होगा, ऐसा है तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें उसने कहा था कि सभी फैसले दिल्ली सरकार की ओर से लिए जाएंगे और उसकी एक कॉपी एलजी के पास भेजी जाएगी।' वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली की एक विधानसभा होगी, चुनी हुई सरकार होगी और इस सरकार के पास सभी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। संविधान में यह अधिकार सभी राज्यों के पास होता है। संविधान में लिखा है कि उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच मतभेद होगा तो मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा और वे फैसला लेंगे। सिसोदिया ने आगे कहा कि, 'इससे पहले जब पुराने एलजी थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं ही सरकार हूं, तब हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए और संविधान पीठ के पास भी गए। जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में लिखे का मतलब है कि हर एक मंत्री और कैबिनेट अपने-अपने मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य के विधानसभा क्षेत्र के दायरे में केंद्र सरकार दखल न करे इसके लिए राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए है। विधानसभा और कैबिनेट को पूरी पावर है कोर्ट के आदेश में ये साफ लिखा हुआ है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ये जो अमेंडमेंट ला रही है, उसके मुताबिक, दिल्ली सरकार को हर फैसले से पहले एलजी से इजाजत लेनी होगी। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के चुने मंत्रियों के पास पूरी पावर होगी। अगर एलजी की अलग राय होगी तो वे राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, लेकिन हर फैसले पर मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर पहले भी टकराव हो चुका है। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 4 जुलाई 2018 को और दो सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला सुनाया था। तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सहायता में काम कर सकते हैं और मंत्री परिषद के सलाह के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन वह सरकार के दैनिक कामकाज में दखल नहीं दे सकते। इन फैसलों के बाद लगा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन अब इस विधेयक के संसद में आने के बाद मामला और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है।

● **राजेश बोरकर**

टूट सकता है अरविंद केजरीवाल का सपना

दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूरे देश में एक 'मॉडल स्टेट' के रूप में पेश करना चाहते हैं। उप्र हो या पंजाब, उत्तराखंड हो या गुजरात में सूरत का नगर निगम चुनाव, आम आदमी पार्टी ने हर जगह दिल्ली को एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश किया। पार्टी ने जनता से कहा कि अगर वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाएं पाना चाहते हैं तो उन्हें अपने राज्य में भी आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना होगा। यानी दिल्ली में किए गए कामकाज को पार्टी पूरे देश में अपना मॉडल बताकर राष्ट्रीय राजनीति में जगह पाना चाहती है। सूरत नगर निगम में सफलता पाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां की जनता को यही सपने दिखाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की जगह पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह दिल्ली में तो जनता की पहली पसंद के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अब उनकी निगाहें उप्र, उत्तराखंड और गुजरात में पार्टी के विस्तार पर हैं। आम आदमी पार्टी की लोकलुभावनी नीतियां जनता के बीच आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं, जो पार्टी के दूसरे राज्यों में उभार का कारण बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को राजनीतिक नुकसान होने का अनुमान रहेगा।

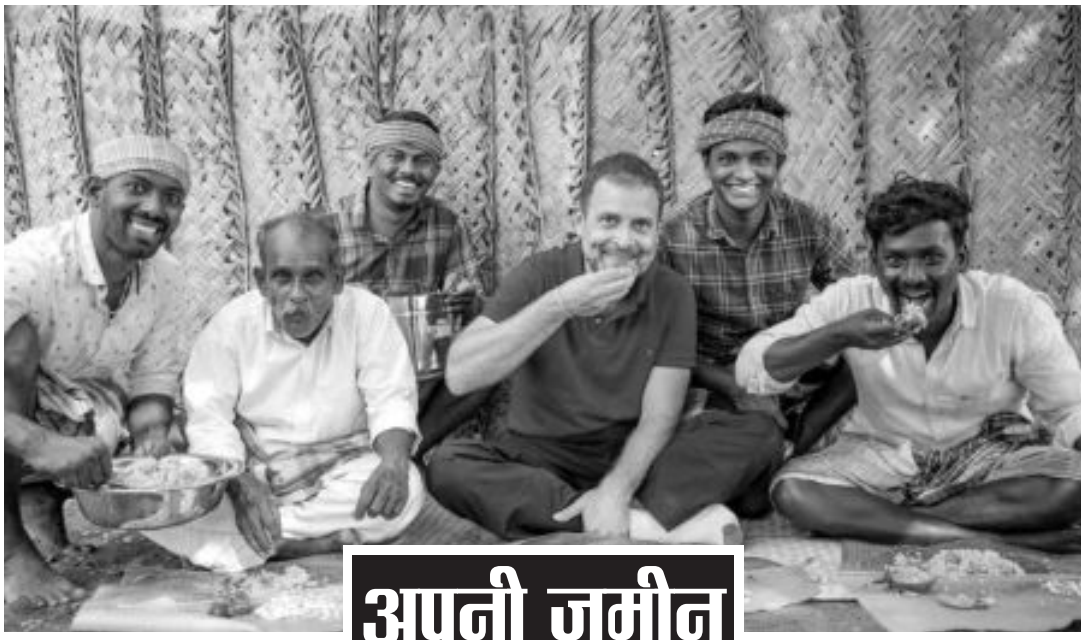

अपनी जमीन छोड़ती कांग्रेस

राहुल गांधी पर लगता है लॉकडॉउन का असर अब हो रहा है। हाल फिलहाल राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वे बातें लंबे आत्ममंथन का नतीजा लगती हैं। हालांकि, ऐसा ठीक-ठाक समझने के लिए अगले साल होने जा रहे पंजाब चुनाव तक इंतजार करना पड़ सकता है। अभी-अभी की ही तो बात है। राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देश में इमरजेंसी लागू करने के फैसले को गलत बताया था। क्या मालूम पंजाब में चुनावी माहौल तैयार होते-होते राहुल गांधी 1984 के दिल्ली में हुए सिख दंगे और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर भी कुछ कहने का मन बना चुके हों। वैसे अब तक तो वो पूछे जाने पर भी ऐसे सवालों को ये कहते हुए टाल जाते हैं कि कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा जा चुका है।

अब तो राहुल गांधी कांग्रेस में यूथ पर फोकस करने के फैसले पर भी अफसोस जताने लगे हैं। राहुल गांधी के मुंह से ये सुनने के बाद उनके करीबी साथियों पर क्या गुजर रही होगी, आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी के ऐसा बयान देने राजनीतिक संदेश भी समझना आवश्यक होगा। एकबारगी तो लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर राहुल गांधी ने बुजुर्ग कांग्रेसियों के साथ-साथ पार्टी छोड़ चुके नेताओं से कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को सिंधिया ने तो जवाब दे ही दिया था, सीनियर कांग्रेस नेता पीसी चाको ने तो जवाबी मैसेज भी भेज दिया है, सीधे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे के रूप में। वो भी तब जबकि राहुल गांधी केरल में कांग्रेस को सत्ता दिलाने के लिए मछुआरों के साथ पानी में छलांग लगाने से लेकर अमेठी के बहाने देश में उत्तर और दक्षिण के लोगों की समझ पर अपनी सोच शेयर करने का जोखिम तक उठा चुके हैं।

भाजपा के मुकाबले सिंधिया के कांग्रेस में बेहतर स्थिति में होने और मुख्यमंत्री तक बन जाने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने सचिन पायलट का नाम याद दिलाया है। मप्र के गृहमंत्री ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की है कि वो चाहें तो अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर भूल सुधार कर सकते हैं? सवाल है कि क्या राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर वास्तव में सचिन पायलट को ही कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी किसी और को नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही कोई खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर सिंधिया और सचिन के नाम भर उछाले जा रहे हैं ये संदेश गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के लिए है?

राहुल गांधी हर फोरम का अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। नियमित तौर पर कुछ न कुछ कहने के लिए वो अक्सर ट्विटर का ही इस्तेमाल करते हैं। बीच-बीच में मीडिया से मुखातिब होकर भी अपनी बातें शेयर करते रहते हैं। कुछ खास बात करनी हो तो रिकॉर्डेड या लाइव वीडियो की मदद लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए वो हमेशा ही युवा मंचों का ही इस्तेमाल करते हैं। भाजपा नेता

आखिर राहुल गांधी ये सब कर क्यों रहे हैं?

2021 की शुरुआत में ही राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें आने लगी थीं। ऐसी भी खबर आई कि कांग्रेस के बागी सीनियर नेता राहुल गांधी की दोबारा ताजपोशी में खलल डाल सकते हैं। लिहाजा कमलनाथ की सलाह पर जी-23 नेताओं के साथ पैचअप के मकसद से एक मीटिंग भी बुलाई गई, वो मीटिंग कितनी असरदार रही अभी-अभी जम्मू में गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में पहुंचे नेताओं ने भगवा साफा बांधकर इशारा तो कर ही दिया है। तो क्या राहुल गांधी अब बुजुर्ग कांग्रेसियों को खुश करने के लिए युवाओं को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार हो गए हैं। जैसे दक्षिण भारत में वोट हासिल करने के लिए वे उत्तर भारतीय की नाराजगी मोल ले चुके हैं?

राहुल गांधी ने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालते वक्त कहा था कि वो युवाओं के जोश और सीनियर कांग्रेस नेताओं के अनुभव को मिला कर इस्तेमाल करना चाहेंगे। हुआ इसका ठीक उलटा। राहुल गांधी के करीबी युवा नेताओं की एक मजबूत ब्रिगेड ऐसी तैयार हो गई कि कांग्रेस में सीनियर नेता उपेक्षित महसूस करने लगे। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस सीनियर और युवा नेताओं में बंट गई, जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने कोई पहली बार रिएक्ट नहीं किया है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ देने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो उनके कॉलेज के दिनों के सबसे क्लोज फ्रेंड थे और इतना अधिकार रखते थे कि वो कभी भी उनके पास पहुंच सकते थे। बगैर किसी पूर्व अनुमति लिए भी।

जैसे राहुल गांधी ने अभी सिंधिया का नाम लेकर यूथ कांग्रेस को संदेश दिया है और यूथ के बहाने वे बाकी कांग्रेसियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही एनएसयूआई की एक मीटिंग के जरिए सचिन पायलट को भी संदेश देने की कोशिश की थी। जुलाई, 2020 में राहुल गांधी को लेकर एनएसयूआई की एक बैठक के अंदर से जो खबर आई, साफ-साफ लग रहा था कि कह रहे हों, जिसे जाना है वो चला जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा।

राहुल गांधी को लेकर उस खबर का एनएसयूआई नेताओं की तरफ से आधिकारिक तौर पर खंडन भी किया गया था और इस बार यूथ कांग्रेस की बातों को भी ऐसे ही झुठलाने की कोशिश चल रही है। असल बात जो भी हो, एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी युवाओं के बीच काफी सहज महसूस करते हैं। और कुछ नहीं तो चेन्नई के स्टेला कॉलेज और हाल में उनके केरल के एक स्कूल का वीडियो देख सकते हैं। विदेशों में जब सैम पित्रोदा राहुल गांधी के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो भी वो बेहद खुश देखे जा सकते हैं। माहौल देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे न तो उनको कभी गुस्सा आता है, और न ही कभी वो अपने बयानों से भूकंप लाने जैसी बातें भी सोचते होंगे। राहुल गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा ही नपा-तुला बयान दिया है। सामान्य तौर पर सिंधिया जब भी बोलते हैं ज्यादा आक्रामक कांग्रेस नेता कमलनाथ पर ही रहते हैं और वैसे ही दिग्विजय सिंह पर भी। हालांकि, हाल ही में राज्यसभा में दोनों को एक-दूसरे के प्रति बड़े ही आदर भाव व्यक्त करते देखा गया था।

दरअसल, राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के फैसले को गलत ठहराने की कोशिश की है। साथ ही, ऐसा भी लगता है जैसे राहुल गांधी खुद तो भूल सुधार की कोशिश कर ही रहे हैं, पुराने दोस्त सिंधिया से भी वैसी ही अपेक्षा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूथ कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी ने पार्टी के प्रति युवा नेताओं को मोटिवेट करते हुए कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में जाकर वो बैकबेंचर बनकर रह गए हैं। अक्सर देखा गया है कि मप्र के कांग्रेस नेता ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब वो सिंधिया को भाजपा नेताओं के साथ कहीं बैठे देखते हैं। कभी बताते हैं कि सिंधिया को मंच की जगह सामने ऑडियंस में बिठाया जा रहा है तो कभी कुछ और आखिर में कटाक्ष जैसी भी कोई लाइन होती ही है, ये क्या हो गया महाराज?

राहुल गांधी के बयान की खबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, जितनी चिंता राहुल गांधी को अब है, काश उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। बात राहुल गांधी की है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतना ही कहा है। अगर ऐसी बातें दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की तरफ से कही गई होतीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के शब्द ही नहीं भाव भी बिलकुल अलग होते। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने युवा कांग्रेसियों को समझाते हुए बताया कि वो उनसे कह रहे थे कि एक दिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। करीब सालभर पहले जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी तो राहुल गांधी ने कई बार दोहराया था कि उनको अपने फैसले पर अफसोस होगा। एक बार राहुल गांधी ने ये समझाने की भी कोशिश की कि उनका वहां मन नहीं लगेगा और इसकी वजह भी बताई थी, मैं जानता हूं उनको।

सिर्फ सिंधिया की बात ही नहीं, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही है। अब तक तो यही समझा जाता रहा है कि राहुल गांधी युवा चेहरों को पार्टी में प्रमोट करने के पक्षधर रहे हैं, लेकिन अब तो वो इमरजेंसी की तरह ही अपनी सोच या उसके हिसाब से किए गए कामों को ही गलत बनाने लगे हैं। यूथ कांग्रेस के ही कार्यक्रम में, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट हैं, राहुल गांधी ने माना है कि युवा चेहरों पर बहुत ज्यादा फोकस करना या उनको ज्यादा तवज्जो देना उनकी गलती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस में जितने सीनियर नेता थे वे या तो पार्टी से किनारा कर गए या हाशिए पर हैं। क्या अब कांग्रेस उन्हें तवज्जो देकर सभी को नाराज करेगी।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

कांग्रेस अब सहयोगियों पर रहने लगी निर्भर

लगातार कमजोर होती कांग्रेस भाजपा के लिए भले ही लाभकारी हो, पर देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं। एक समय जो कांग्रेस अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ती थी, वह अब सहयोगियों पर निर्भर रहने लगी है। उसकी यह निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में द्रमुक ने कांग्रेस को महज 25 सीटें दी हैं तो बंगाल में वाम दलों ने 92। असम, केरल और पुडुचेरी में कांग्रेस अवश्य गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, लेकिन वह पहले जैसी सक्षम नहीं दिख रही। असम में जो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, वहां उसे 5 दलों से समझौता करना पड़ा है। इनमें सांप्रदायिक छवि वाली अजमल की पार्टी भी है। एक समय कांग्रेस ने इस पार्टी से समझौता करने से इंकार कर दिया था। हाल ही में पीसी चाको ने इस्तीफा देकर केरल में भी कांग्रेस को झटका दे दिया है। चाको ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है। उन्होंने जिस तरह गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा किया, उससे उसकी और फजीहत ही हुई है। इसके पहले जी-23 गुट के नेता भी परोक्ष रूप से गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम दिखने वाली कांग्रेस अब जिस तरह राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी जमीन छोड़ रही है, उससे वह और कमजोर ही हो रही है। कांग्रेस की यह कमजोरी भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है।

राजनीति में अच्छे और ईमानदार लोगों को लाने का कानूनी प्रावधान आवश्यक है। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन देश और देश की राजनीति आसानी से सुधर नहीं सकती, उसके लिए मुश्किल काम करने ही पड़ेंगे। हमारा लोकतंत्र जैसे-जैसे उम्रदराज होता जा रहा है, दल-बदल की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सत्ता सुख पाने के लिए नेता विचारों को त्याग रहे हैं। यह भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

माननीय क्यों बदल रहे पार्टियां?

भारतीय राजनीति में आचरण की शुचिता और वैचारिक प्रतिबद्धता का लोप हुए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, लिहाजा व्यक्तिगत या सामूहिक दल-बदल की खबरें अब किसी को भी चौंकाती या हैरान नहीं करती हैं। हां, इस बात पर कोफ्त जरूर होती है कि आजादी के सात दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी हमारे लोकतंत्र के अनुभव ने देश की राजनीति को पतन के किस दलदल में लाकर खड़ा कर दिया है। एडीआर की रिपोर्ट में पता चला है कि इस दौरान 443 सदस्यों ने दलबदल कानून तोड़े। इनमें से 170 (42 फीसदी) विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना उचित समझा, तो भाजपा के मात्र 18 विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा। जबकि 182 (45 फीसदी) विधायक अपनी पार्टी छोड़ भाजपा में गए। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पिछले दिनों मप्र, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में पुरानी सरकार का गिरना और नई सरकार का गठन होना दलबदल के कारण ही हुआ। सांसद और विधायक इतनी जल्दी दल क्यों बदलते हैं? वैसे तो इसके बहुत कारण हो सकते हैं, पर सामान्य रूप से मंत्री बनने या धनराशि मिलने का प्रलोभन प्रमुख है। इससे कई सवाल उत्पन्न होते हैं। पहले तो नवनिर्वाचित विधायकों के आत्मसम्मान पर शंका होती है। अक्सर इन्हें वातानुकूलित बसों या हवाई जहाज में बिठाकर महंगे रिजॉर्ट या होटलों में ले जाया जाता है और लगभग नजरबंद करके रखा जाता है। अब अमूमन हर विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे दृश्य आम हैं। खुद विधायकों को भी नहीं महसूस होता कि इस तरह बंदी बनना उनके विवेक और परिपक्वता पर प्रश्नचिन्ह है। किसी भी व्यक्ति, खासतौर से चुने हुए नेता के आत्मसम्मान को इस तरह के व्यवहार से घोर आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन उनकी तस्वीरों और वीडियो क्लिप से दिखता है कि वे इस हालत में बहुत खुश हैं।

इसका यही अर्थ है कि हमारे विधायकों-सांसदों में परिपक्वता की कमी है। यह कहा जा सकता है कि राजनीति में नैतिकता खत्म ही हो गई है। राजनीति में आने वालों का एकमात्र उद्देश्य रुपए कमाना और संपत्ति बढ़ाना है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में जारी अपनी एक रिपोर्ट में यह लिखा था कि 'सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों का राजनीति में आने का और चुनाव लड़ने का केवल एक ही कारण है कि वे रातोंरात धनवान हो जाएं।' राजनीति का अपराधीकरण भी नैतिकता के अभाव का एक प्रमुख कारण है। जब लोकसभा के 43 फीसदी सदस्यों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले अदालतों में चल रहे हों, तब नैतिकता की आशा रखना अव्यावहारिक लगता है। हमारे राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। हर राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष, एक समूह या एक परिवार की मर्जी पर चलता है।

चुनावों में उम्मीदवारों का चयन भी इनकी मर्जी से होता है। उसमें कोई लोकतांत्रिक प्रावधान नहीं है। दलबदल को रोकने के लिए वर्ष 1985 में संविधान में 52वां संशोधन कर दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया था। उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई सांसद या विधायक संसद या विधानसभा के सत्र में अपनी पार्टी की व्हिप के विपरीत मत दे, तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। किसी दूसरे दल में शामिल होने पर भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन इसमें एक ढील भी दी गई कि दो तिहाई या उससे ज्यादा सांसद या विधायक दलबदल करें, तो सदस्यता खत्म

दल बदलने वाले 48 फीसदी चुनाव जीते

दरअसल, जिन लोगों ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी का दामन थामा है, उनमें से अधिकांश वे हैं जिन्हें या तो टिकट कटने का डर रहा है या फिर सत्ता में भागीदारी की स्थिति में। एडीआर के आंकड़ों से पता चलता है कि दोबारा चुनाव लड़ने वाले सांसदों और विधायकों की संपत्ति में औसतन 39 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 357 विधायक जिन्होंने दल बदलकर दोबारा चुनाव लड़ा, उसमें से 170 (48 फीसदी) ने जीत दर्ज की। विधानसभा उपचुनावों में दलबदलुओं की सफलता दर बहुत अधिक थी। 48 दलबदलुओं में से 39 यानी 81 फीसदी का दोबारा चयन किया गया। रिपोर्ट कहती है कि विधायकों-सांसदों के पार्टियां बदलने के सबसे प्रमुख कारणों में मूल्य आधारित राजनीति का नहीं होना, पैसे और सत्ता की लालसा, धन और ताकत के बीच सांठगांठ है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब तक इस तरह के ट्रेंड पर रोक नहीं लगती, देश की चुनावी और राजनीतिक स्थिति बदतर होती जाएगी। अगर उन कमियों को दूर नहीं किया जाता, जिनकी वजह से ऐसे पार्टियां बदली जाती हैं तो यह लोकतंत्र का मजाक होगा।

नहीं होगी। दलबदल कानून किस सांसद या विधायक पर लागू होगा या नहीं होगा, यह फैसला केवल संसद या विधानसभा के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। दलबदल कानून बन गया और कुछ साल तक इसका थोड़ा-बहुत असर भी दिखाई पड़ा। लेकिन दो तिहाई वाले प्रावधान का नतीजा यह हुआ कि लोगों ने कहना शुरू किया कि विधायकों और सांसदों की थोक में तो खरीद-फरोख्त हो सकती है, फुटकर नहीं।

इस कानून से बचने की एक और अनूठी तरकीब निकाली गई। इसके तहत विधानसभा के अध्यक्ष इस बात का फैसला ही नहीं करते थे कि अमुक सदस्य ने इस कानून का उल्लंघन किया है या नहीं। बदलते समय के साथ यह कानून लगभग निरर्थक हो गया। वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन में कहा गया कि दलबदल के बाद सांसद या विधायक कोई लाभकारी पद धारण नहीं कर सकते। संशोधन में यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार में मंत्रियों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या से 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। इन संशोधनों की वजह से भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि सदस्यों के दल बदलने का फैसला संसद या विधानसभा अध्यक्ष के बजाय संसद के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए राज्यपाल करें।

फैसला करने से पहले उन्हें चुनाव आयोग की सलाह लेनी चाहिए। एक कानून यह भी होना चाहिए कि राजनीतिक दलों का आंतरिक कामकाज कैसा होगा। यदि राजनीतिक दल आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं होंगे, तो वे भला देश में लोकतांत्रिक प्रणाली कैसे चला सकेंगे? इस बारे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 1999 में जारी रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 के अपने एक फैसले में कहा कि अगर राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले अदालतों में चल रहे हैं, तो दलों को इसके विस्तृत कारण बताने होंगे। शीर्ष अदालत ने तो यहां तक कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार होना आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट देने का कारण नहीं हो सकता।

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के दौरान पाला बदलकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले 405 विधायकों में से 182 भाजपा (44.9 प्रतिशत) में शामिल हुए तो 38 विधायक (9.4 प्रतिशत) कांग्रेस और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति का हिस्सा बने। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सदस्य भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए तो वहीं 2016-2020 के दौरान कांग्रेस के 7 राज्यसभा सदस्यों ने दूसरी पार्टियों का हाथ थामा। 2016 से 2020 के दौरान हुए चुनावों में कांग्रेस के 170 विधायक (42 प्रतिशत) दूसरे दलों में शामिल हुए तो इसी अवधि में भाजपा के सिर्फ 18 विधायकों (4.4 प्रतिशत) ने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मप्र, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार का बनना-बिगड़ना विधायकों का पाला बदलने की बुनियाद पर हुआ यानी विधायकों के पाले बदलने से सरकारें गिरीं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2020 के दौरान पार्टी बदलकर राज्यसभा चुनाव फिर से लड़ने वाले 16 राज्यसभा सदस्यों में से 10 भाजपा में शामिल हुए। 2016 से 2020 के बीच कुल 12 लोकसभा सांसदों ने पार्टी बदलकर दोबारा चुनाव लड़ा। इनमें से 5 (41.7 फीसदी) सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। लगभग इतने ही लोकसभा सांसद कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी बदलने वाले 16 राज्यसभा (43.8 फीसदी) सांसदों ने 2016 से 2020 के दौरान कांगेस छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा।

एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतंत्र लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार पर निर्भर करती है, जहां नागरिकों के हित हमारे नेताओं के निजी हितों की तुलना में सर्वोपरि हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है, 'अब वक्त आ गया है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां और नेता सुविधा और खुद के लाभ की राजनीति को खत्म कर दृढ़ विश्वास, साहस और आम सहमति की राजनीति शुरू करे।' रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत के संसदीय लोकतंत्र के नैतिक गुणों के पतन की वजह से मौलिक सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आया राम, गया राम सिंड्रोम, पैसे और सत्ता के लिए कभी खत्म नहीं होने वाली भूख अब हमारे सांसदों और राजनीतिक दलों के लिए आम बात हो गई है।

● इन्द्र कुमार

बिगड़ेगी मौजूदा चुनावी और राजनीतिक स्थिति

गौरतलब है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक इन प्रवृत्तियों में सुधार नहीं होता, हमारी मौजूदा चुनावी और राजनीतिक स्थिति और बिगड़ेगी। राजनीति को निष्पक्षता, स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, समानता और ईमानदारी की कसौटी पर खरे उतरने की जरूरत है। यह लोकतंत्र का मखौल होगा, अगर हम इन कमियों को दुरुस्त नहीं कर पाए, जिनकी वजह से सांसदों और विधायकों द्वारा दल बदले जा रहे हैं। छोटे राज्यों की विधानसभाओं में तो, जहां दो राजनीतिक दलों के बीच बहुमत के लिए बहुत कम सदस्यों का अंतर होता है, अक्सर ही विधायकों को पाला बदलकर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा करते देखा जाता है। वैसे जनतांत्रिक राजनीति में दल-बदल अपने आप में कोई बुराई नहीं है। एक खुले और लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और वह उसे कभी भी बदलने का अधिकार रखता है। अगर विचारों में परिवर्तन को सिरे से ही बुराई मान लिया जाए तो यह उस व्यक्ति के अधिकार का हनन या उसमें हस्तक्षेप करना होगा। आजादी के बाद भारत की राजनीति में दल-बदल की ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं, जिनसे इस अधिकार की सिर्फ पुष्टि ही नहीं हुई है बल्कि हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है।

कर्ज के बोझ में डूबता छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय संकट कम होता नहीं दिख रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। सरकार पहले से ही 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। राज्य सरकार ने इस साल जनवरी महीने में ही 2759 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसको मिलाकर सरकार पर कुल कर्ज 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया था कि दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब सरकार पर 41 हजार 239 करोड़ का कर्ज था। बीते दो वर्षों में इसमें 36 हजार 170 करोड़ रुपए का नया कर्ज जुड़ गया। इस रकम के प्रबंधन के लिए पिछली बार 5996 करोड़ कर्ज का ब्याज भरने के लिए और 4841 करोड़ रुपए मूलधन की रकम अदा करने के लिए बजटीय व्यवस्था करनी पड़ी थी।

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तिजोरी पर कर्ज भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि लगभग हर महीने भूपेश सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो भूपेश सरकार ने अब तक 30 हजार करोड़ से अधिक का ऋण लिया है और अब नए वित्तीय वर्ष के लिए 18 हजार करोड़ का ऋण प्रस्तावित किया है। किसी भी राज्य के लिए विकास तभी संभव है जब उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। राज्य अपने मद से साधन-संसाधन जुटाने में सक्षम हो। मगर छत्तीसगढ के भूपेश सरकार की कहानी कुछ दूसरी है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि सरकार को औसतन हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो राज्य की भूपेश सरकार ने नवंबर 2020 की स्थिति में कुल 30 हजार 632 करोड़ रुपए का ऋण लिया है और साल 2019-20 में कर्ज के ब्याज के रूप में 4 हजार 225 करोड़ रुपए पटाएं हैं। बात अगर नए वित्तीय वर्ष की करें तो वित्त विभाग में पदस्थ सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में 18 हजार करोड़ रुपए ऋण लेने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर सूबे के वरिष्ठ और प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र हमारा पैसा रोक रही है। हमें खर्च करने के लिए ऋण लेना पड़ेगा। अब केंद्र के कारण राज्य कर्ज ले रही है या फिर वित्तीय प्रबंधन में कुछ कमी है यह तो आना वाला वक्त ही तय करेगा। मगर बात कर्ज के आकड़ों की करें तो भूपेश सरकार को 41,695 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। भूपेश सरकार ने 21 माह में 30 हजार 632 करोड़ रुपए कर्ज लिया। साल 2019-20 में राज्य को बतौर ब्याज 4225 करोड़ रुपए चुकाना पड़ा। राज्य पर कुल कर्ज 66 हजार 968 करोड़ का है। केंद्र से राज्य को 13 हजार 440 करोड़ रुपए मिलने हैं। नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 18 हजार करोड़ कर्ज लेने का प्रस्ताव तैयार किया। आंकड़ों के बाद जानकारों की मानें तो राज्य पर कर्ज का बढ़ता बोझ, घटती हुई प्रति व्यक्ति आय, दोगुना वित्तीय घाटा चौतरफा चोट दे रहा है। आंकड़ों की मानें तो बीते वर्ष वित्तीय घाटे के रूप में 11 हजार 518 करोड़ रुपए अनुमानित था मगर वास्तविक घाटा करीब 23 हजार करोड़ रुपए का हुआ, जिससे राज्य की स्थिति और गड़बड़ हो गई। अब स्थिति यह है कि इस साल के प्रस्तावित कर्ज के साथ भूपेश सरकार अपने कार्यकाल में करीब 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इससे आने वाले कई सालों तक सरकार को यह कर्ज चुकाना पड़ेगा।

बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा अधिक कर्ज लेने के लिए जानकार सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून में बदलाव कर अपने जीएसडीपी का 5 फीसदी तक कर्ज ले रही है, जो पूर्व में 3 फीसदी निर्धारित था और इसके लिए राज्य सरकार कोरोनाकाल को जिम्मेदार मान रही है। कर्ज के इन तमाम बातों के बीच अगर राजनीतिक बात करें तो विपक्ष इस स्थिति के लिए सरकार के वित्तीय प्रबंधन को कुप्रबंधन बता रही है, तो वहीं सत्तापक्ष राज्य के बदले केंद्र को नसीहत देने का दलील दे रही है। राज्य की व्यवस्था हो या फिर आपका और हमारा घर, जानकार यही मानते हैं कि कर्ज हमेशा से घातक रहा है। मगर जिस तेज गति से राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने कर्ज पर कर्ज लेते जा रही है, आने वाले समय में यह दुखद परिणाम ही देगा, क्योंकि राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

केंद्र से नहीं मिला 21 हजार करोड़ का बकाया

प्रदेश के कृषि, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि यह तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है। केंद्र सरकार ने हमारे 21 हजार करोड़ रुपए नहीं दिए और किसानों के धान का पैसा हमको देना है तो कहीं से तो इंतजाम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से चल रहे टकराव के बीच केंद्र सरकार की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक करीब 1800 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन देने जा रहा है। 0.25 फीसदी के ब्याज पर लोन की अदायगी 50 सालों में करनी होगी। यह कर्ज नगरीय विकास और उद्योग से जुड़े मापदंडों के पूरा करने के कारण दिया जा रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ सरकार को इससे बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने सॉफ्ट लोन के लिए 4 मापदंड बनाए थे। इसको 31 जनवरी तक पूरा करना था। इसमें नगरीय प्रशासन में सुधार, जिला स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाए जाने के अलावा बिजली व्यवस्था में सुधार और वन नेशन, वन राशन कार्ड बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने थे। प्रत्येक सुधार पर राज्य को 895 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन देने प्रस्ताव दिया गया था। वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि नगरीय प्रशासन में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और ये कदम केंद्र के मापदंडों में खरे उतरे हैं। इसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 895 करोड़ सॉफ्ट लोन देने की अनुशंसा वित्त मंत्रालय को भेजी है। इसी तरह जिला स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए किए गए सुधार पर भी केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने संतोष जाहिर किया है। कांग्रेस सरकार ने बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, कई तरह की रियायतें दी गई हैं। जिसकी काफी सराहना हो रही है। उद्योग मंत्रालय में इसके लिए भी छत्तीसगढ़ को 895 करोड़ रुपए का ऋण देने की अनुशंसा वित्त मंत्रालय को भेजी थी और वित्त मंत्रालय ने यह आरबीआई को भेज दी है।

राजस्थान में विधायक पिछले कुछ साल से विधायक निधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, इसको देखते हुए सरकार ने इस बार विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है और विधायक निधि 5 करोड़ रुपए कर दी है।

5 करोड़ की विधायक निधि

राजस्थान में विधायकों के कद के साथ अपने क्षेत्र में विकास के लिए खर्च करने की उनकी क्षमता अब और बढ़ गई है। अपने क्षेत्र में विधायक के विवेक से विकास कार्य कराने के लिए विधायकों का बजट दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब तक सवा दो करोड़ रुपए सालाना एमएलए लेड फंड को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 करोड़ कर दिया है। सदन में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर जवाब देने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने विधायक निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा की। लेकिन इससे पहले सदन में घटनाक्रम बेहद रोचक रहा। अपना जवाब देकर बजट की पूरक घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री अपनी सीट पर बैठने लगे तो मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्यमंत्री को एक पर्ची थमाई।

मुख्यमंत्री ने पर्ची देखी लेकिन उसे लगभग-लगभग इग्नोर सा करते हुए अपनी सीट पर बैठ गए। मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हो चुका था लिहाजा और विनियोग विधेयक पारित कराने के बाद विधानसभा स्थगित होने का ऐलान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से होना था, लेकिन स्पीकर ने दो बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि क्या वह अपनी बात बोल चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीकर साहब ने उनसे दो बार पूछा और उनके दो बार पूछने के कुछ खास मायने होते हैं। गहलोत ने पूछा कि क्या कुछ विशेष बात रह गई है? इस पर स्पीकर ने कहा कि कई सदस्य विधायक कोष की रकम बढ़ाने की बात कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी चाहते हैं कि विधायक कोष की राशि बढ़े, लेकिन कितनी बढ़े यह तय किया जाना होगा। इस पर सदन में कई सदस्यों ने 5 करोड़ रुपए तक विधायक कोष किए जाने की मांग रखी।

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पीकर सीपी जोशी को विधायक निधि कोष की बढ़ोतरी तय करने के लिए अधिकृत कर दिया। गहलोत ने कहा, 'स्पीकर साहब जो रकम कह देंगे उतना विधायक कोष कर दिया जाएगा।' इधर, स्पीकर ने गेंद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के पाले में डाल दी। स्पीकर ने कहा कि आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने बहुत अच्छा संबोधन दिया है और इस मौके की खुशी साझा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो रकम बोल देंगे वह विधायक निधि कोष के लिए तय कर दी जाए। नेता प्रतिपक्ष थोड़ी देर खामोश रहे, तो प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अपने आपको अधिकृत किए जाने की बात कहते हुए महंगाई का हवाला दिया और कहा कि विकास कार्यों के लिए विधायक निधि कोष 5 करोड़ रुपए कर दी जानी चाहिए। इस पर सदन में सभी ने राजेंद्र राठौड़ की बात का समर्थन किया। लेकिन स्पीकर नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ही इस बात को सुनने का मन बना चुके थे।

स्पीकर ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह भी सदन के दूसरे सदस्यों से अलग नहीं हैं, वह भी विधायक हैं और वह भी अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। कटारिया ने भी 5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोष किए जाने की बात पर सहमति जताई और कहा कि जब सभी सदस्य 5 करोड़ रुपए तक विधायक निधि कोष का आकार किए जाने का आग्रह कर रहे हैं तो उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ा मन दिखाते हुए सदन में घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से 5 करोड़ का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर सभी सदस्यों की इच्छा है तो विधायकों की इच्छा का सम्मान होगा और जो वह कह रहे हैं इतनी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इस पर सदन में मौजूद सभी विधायकों ने टेबल बजाकर मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करने वालों में सत्ताधारी कांग्रेस के साथ ही भाजपा, बीटीपी, माकपा, आरएलपी और राष्ट्रीय लोकदल और निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। इसके तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के बजट को पारित कराया। वित्त और विनियोग विधेयक पर सदन में ध्वनिमत से परीक्षण किया गया तो केवल हां पक्ष में ही आवाज आई। राजस्थान का बजट तो इसके साथ पास हो ही गया, लेकिन विधायकों के लिए भी हर साल एमएलए फंड में 5 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

विधायकों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

विधानसभा इसके तत्काल बाद स्थगित कर दी गई तो सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने उनकी सीट पर पहुंचे। विपक्ष के तरफ से सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आभार जताया। इस बीच सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी लॉबी में पहुंचे और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत तकरीबन 20 विधायकों को मुख्यमंत्री की सीट तक ले आए। राजेंद्र राठौड़ के साथ ही भाजपा के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। काफी देर तक विधायकों से घिरे रहने के बाद मुख्यमंत्री सदन से बाहर निकले तो सीधे स्पीकर सीपी जोशी के चेंबर में पहुंचे। यहां एक बार फिर स्पीकर जोशी ने मुख्यमंत्री के बड़े दिल की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड-19 के बावजूद जो घोषणा की गई है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार कैलाश मेघवाल के संबोधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल ने चर्चा में शामिल होकर डिबेट का स्तर भी सुधारा और बहुत गंभीर मुद्दे भी रखें।

शरद पवार की सियासी हसरतें

पिछले वर्ष 12 दिसंबर 2020 को अपना 80वां जन्मदिन मना चुके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की एक बार फिर विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए 'सियासत जवां' होने लगी है। यानी 80 वर्ष की आयु में भी पवार कांग्रेस को दरकिनार कर विपक्ष के रूप में नेतृत्व संभालने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि शरद पवार आज देश के सर्वाधिक अनुभवी राजनीतिज्ञों में से एक हैं। यहां तक कि पूरे देश में अपनी राजनीति का लोहा मनवा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरू मानते हैं। कैंसर की लंबी बीमारी के बावजूद पवार की सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। गत दिनों मुंबई में जब शरद पवार, कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज नेता पीसी चाको को अपनी पार्टी एनसीपी में शामिल करा रहे थे उसी दौरान उनकी फिर से जवां होती 'सियासी हसरतें' बाहर भी आ गईं, जिसकी 'धमक' राजधानी दिल्ली में गांधी परिवार तक सुनाई दी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कांग्रेस को हटाकर 'नया फ्रंट' बनाने के संकेत दे दिए। पवार ने कहा कि अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव मंच खड़ा हो, इसके लिए सोचने की जरूरत है। शरद पवार ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी ने फोन पर कहा कि अल्टरनेटिव मंच बनाने की जरूरत है, इसके बारे में सोचिए। येचुरी के जवाब के बाद एनसीपी के मुखिया पवार ने कहा कि कोई भी साथी जब भी इस तरह के प्रस्ताव देते हैं तो हम इस पर ध्यान देते हैं। शरद पवार की इस नई कवायद के बाद कांग्रेस विपक्ष के तौर पर और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और राज बब्बर समेत कई ऐसे नेता है जो गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं चाहते हैं। बता दें कि ये कांग्रेसी नेता गांधी परिवार के नेतृत्व पर पहले से ही सवाल उठाते आ रहे हैं। कांगेस पार्टी में असंतुष्ट चल रहे यह सभी नेता शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में नेतृत्वविहीनता की स्थिति बहुत पहले से महसूस की जा रही है। आज के दौर में न सिर्फ विपक्षी दल, बल्कि सत्तापक्ष के लोग भी एक मजबूत विपक्ष की कमी महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की दिशाहीनता अन्य विपक्षी दलों के अंदर भी असंतोष पैदा कर रही है, कांग्रेस से इतर विपक्ष के कई राजनीतिक दलों के नेता सही और परिपक्व विपक्ष का न होना मोदी सरकार के खिलाफ संसद और संसद के बाहर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में सर्वाधिक संख्या रखने वाली कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व ही रोड़ा बना बैठा है। विपक्षी दलों के नेता यह मानने लगे हैं कि देश को एक गंभीर विपक्ष के नेतृत्व की जरूरत है।

आपको बता दें, कई राजनीतिक दलों के नेता अब खुलेआम कहने भी लगे हैं कि मजबूत विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में तो खड़ा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर शरद पवार अब कांग्रेस में भले न हों, लेकिन इसी पार्टी से निकले हुए नेता हैं। आज भी कांग्रेस में अग्रिम पंक्ति के अधिकांश सभी नेता उनके मित्र हैं। इसके साथ पवार के कई क्षेत्रीय दलों से भी काफी मधुर संबंध हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार गैर-भाजपा, गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे हैं। बता दें कि शरद पवार अपने लंबे राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी जता चुके हैं। वर्ष 1991 में शरद पवार ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, उस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दौड़ में पवार भी शामिल थे। लेकिन ऐन मौके पर पीवी नरसिम्हा राव के हाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी लग गई थी। उसके बाद भी शरद पवार ने हार नहीं मानी। वर्ष 2001 में पवार ने अपने 61वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी से साफतौर पर कहा था कि मैं भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता हूं, मेरे अंदर सभी काबिलियत मौजूद है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने केंद्र में कमान संभाली तभी से विपक्ष बिखरता चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि विपक्ष की कई पार्टियों को कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असमंजस से जूझ रही है तो दूसरी तरफ उसके तमाम सहयोगी दल भी अपनी अलग सियासी राह तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना राहुल के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार चला रही हो लेकिन उन्हें कांग्रेस का केंद्र के स्तर पर नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कुछ महीने पहले ही शिवसेना ने कहा था कि राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके नेतृत्व में कमी है।

● **बिन्दु माथुर**

पवार के नाम पर कई दलों ने दी सहमति

गौरतलब है कि अगर शरद पवार अगुवाई करते हैं तो विपक्ष को एक मजबूत ताकत मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती भी अगले वर्ष उप्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं। यानी सपा और बसपा को भी कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी चाहती हैं कि चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बने, जिसका अपना एजेंडा हो। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की ओर से ममता के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं शरद पवार के इस आह्वान के बाद शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, टीएमसी चीफ ममता के समर्थन में प्रचार करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा विपक्षी दल टीआरएस, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस भी पवार के साथ उनके अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, और उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं। अब शरद पवार गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों को साथ लाने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके लिए सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। इन राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अगर शरद पवार कांग्रेस को हटाकर 'थर्ड फ्रंट' बनाते हैं तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और गांधी परिवार को लगेगा। बता दें कि 1999 में ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था।

लाल होती टोपियां

सियासत में रंगों का अलग ही खेल है। पहचान उन्हीं से है, तो उत्साह का स्रोत भी। भगवा की अपनी अलग तस्वीर है, तो लाल रंग भी उप्र में चर्चा में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूछते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लाल रंग से क्यों डरते हैं? योगी ऐसे सवालों को जवाब के लायक नहीं मानते, लेकिन विधानसभा में सवाल जरूर उठाते हैं कि गंभीर अपराधों के पीछे सपा का नाम ही क्यों आता है? सियासत है तो सवाल होंगे और जवाब आने तक कयास जारी रहेंगे। बहस जारी है कि लाल का डर क्यों, तो सपा का नाम अपराध के साथ फिर कैसे?

दरअसल, उप्र में विस चुनाव में महज एक साल बचे हैं। भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो समाजवादी पार्टी 2017 से सबक लेकर एकला चलो पर है। करीब 30 साल के दौरान विधानसभा चुनावों में कोई पार्टी अकेले सत्ता नहीं बचा सकी है, तो सपा की उम्मीदें कुलाचें मार रही हैं। उसे बसपा और कांग्रेस के सिमटते वोट बैंक से आस है। इन उम्मीदों को जमीन पर उतारने अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। कोरोना के घटते प्रभाव में वह पिछले कुछ महीनों से लखनऊ में कम ही मिलते हैं। पूरे प्रदेश में उसी स्फूर्ति से पहुंच रहे हैं, जैसा उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले किया था। तब उन्होंने बसपा के नीले रंग की चमक फीकी करने में सफलता हासिल कर ली थी। इस बार वह मुकाबला भगवा बनाम लाल बनाने की कोशिश में हैं।

सपा ने अनोखे अंदाज में कार्यकर्ताओं के सीक्रेट कैंप आयोजित किए। बताते हैं कि इसमें सिर्फ समर्पित कार्यकर्ताओं को बुलाकर संगठन की मजबूती और जीत का मंत्र दिया गया। इन शिविरों की फोटो खींचने की इजाजत नहीं थी, न इसकी जानकारी साझा करने की छूट। चित्रकूट, कानपुर, श्रावस्ती और बरेली मंडल की विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हर शिविर में 8 से 10 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता जुटे थे। शिविर में अखिलेश यादव द्वारा गठित 20 सदस्यीय टीम कार्यकर्ताओं को समाजवादी विचारधारा, देश-विदेश के आर्थिक सरोकार, केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जनता का समर्थन जैसे कई मुद्दों पर प्रशिक्षित कर चुकी है।

अखिलेश ये भी जानते हैं कि अगले साल के चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर भाजपा को माइलेज मिलना तय है, इसलिए उन्होंने अयोध्या के संतों का सानिध्य भी शुरू कर दिया है। उन्होंने संतों को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस मौके पर उन्होंने वादा भी किया कि सपा की सरकार बनी, तो अयोध्या नगर निगम के सभी टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे। हालांकि ये स्पष्ट होना शेष है कि संतों के लिए टैक्स कैसे भारी पड़ सकते हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि उप्र में परंपरागत मतदाताओं के बजाय सत्ता का फैसला स्विंग वोटर्स करते रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला ही कभी मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता है, तो कभी सपा एकतरफा जीत हासिल करती है। इसी पर आगे बढ़कर 2017 में भाजपा ने सभी को चौंका दिया।

2012 में अखिलेश यादव की लहर में सपा ने 403 में से 224 सीटें हासिल की थी। उसका वोट शेयर भी 2007 के 25.4 प्रतिशत से बढ़कर 29.9 हो गया था। हालांकि तब बसपा को सत्ता मिली थी और सपा का आंकड़ा 97 सीट पर सिमट गया था। 2017 में अखिलेश ने सत्ता बनाए रखने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसे भारी झटका लगा। सीटें 47 ही बचीं, वोट शेयर भी लुढ़ककर 22 प्रतिशत रह गया। अखिलेश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया और उसे यहां भी नुकसान उठाना पड़ा। बसपा शून्य से 10 सीट तक पहुंच गई, जबकि सपा 5 सीट ही हासिल कर सकी। वोट शेयर भी घटकर 18.1 प्रतिशत रह गया, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 5 सीटें जीतकर 22.3 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया था। ये आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश यादव इस बार गठबंधन से परे जाकर चुनावी दंगल को भगवा बनाम लाल बनाने में अभी से जुट गए हैं। उत्तर विधानसभा चुनाव में महज एक साल का वक्त बचा है, ऐसे में सूबे की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल अपने सियासी-सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं तो नेता अपने सियासी भविष्य के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुट गए हैं। ऐसे में आयाराम और गयाराम का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सत्तासीन है, लेकिन दलबदल करने वाले नेताओं का राजनीतिक ठिकाना और पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनती जा रही है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

भाजपा का विकल्प सपा

समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता अताउर रहमान कहते हैं कि उप्र की सियासी तस्वीर साफ है कि भाजपा का विकल्प सिर्फ सपा है। यही वजह है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि बसपा के भी बड़े नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। 2022 की सीधी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की होगी। मायावती भाजपा की बी-टीम बन चुकी हैं। ऐसे में सपा ही उप्र के लिए मजबूत विकल्प है और सूबे के लोग अखिलेश यादव के विकास कार्यों को देख चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि उप्र में विपक्ष की भूमिका सपा नहीं बल्कि कांग्रेस निभा रही है। फिलहाल उप्र में भाजपा का विकल्प के रूप में सपा अपने आपको स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि सपा के पास एक अपना वोटबैंक है, जो पूरी मजबूती के साथ है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के बीच भी अखिलेश की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं दिख रही है। उप्र में बसपा और कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में बड़ी तादाद एंटी भाजपा विचारधारा वाले नेताओं की है। इनमें दलित और मुस्लिम की संख्या है, जिनका भाजपा में जाने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। ऐसे में उनके पास सूबे में सिर्फ सपा ही एक विकल्प दिखती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि सपा के साथ 10 फीसदी यादव और 20 फीसदी मुस्लिम वोट हैं। यह 30 फीसदी वोट उप्र की सियासत में काफी अहम माना जाता है, जो दलबदल करने वाले नेताओं को आकर्षित कर रहा है।

एक साथ आए दुश्मन नंबर वन

कई दशकों से बिहार की राजनीति अनवरत रूप से जातिगत समीकरणों पर ही चलती चली आ रही है। जो इन समीकरणों को जितना अधिक साध सका है, सत्ता की कुर्सी पर उसका अधिकार उतना ही प्रबल होता है। बिहार की राजनीति में जनता दल के छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली भाजपा, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। मुख्यमंत्री के पद पर भले नीतीश कुमार काबिज हों, लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। यही एक वजह है कि कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार के विरोधियों में शामिल रहे दुश्मन नंबर वन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब गलबहियां करते नजर आ रहे हैं।

नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ लंबे समय तक राजनीतिक दुश्मनी निभाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के इस 'भरत मिलाप' को बिहार की राजनीति में 'लव-कुश' समीकरण कहा जाता है। लव-कुश समीकरण (कुर्मी और कुशवाहा का जातिगत समीकरण) के सहारे अपने वोटबैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने मिलकर ये दांव खेला है। बिहार के डीएनए में अंदर तक घुस चुकी जाति की राजनीति के चलते दोनों नेताओं का एक साथ आना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। बिहार की करीब 30 विधानसभा सीटों पर लव-कुश समीकरण सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखता है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटों पर कब्जा जमाया था। भाजपा की बड़ी और जेडीयू की छोटी भूमिका में बस इन्हीं 30 सीटों का अंतर है। कहा जा सकता है कि लव-कुश समीकरण के सहारे नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के 'पर' कतरने की कोशिश की है। यह समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी खतरे की घंटी है। उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में जितना कद बढ़ा, उतना ही नीतीश कुमार को फायदा हुआ है। 2005 और 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन इस बात का गवाह रहा है।

नीतीश और उपेंद्र दोनों को ही एक-दूसरे की जरूरत है। बिहार में कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं की संख्या करीब 9 फीसदी है। इन वोटों के नीतीश के साथ आ जाने पर भाजपा और राजद दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अपना कद भाजपा के सामने बढ़ाना चाहते हैं। जिससे उसके ठीक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को इस बार के जैसे हालातों का सामना न करना पड़े। उदाहरण के तौर पर भाजपा ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लंबे समय तक टाल रखा था। वहीं, करीब दो महीने पहले ही अरूणाचल प्रदेश में भाजपा ने जेडीयू विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया था।

नीतीश कुमार के साथ जुड़ने के अलावा उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई खास राजनीतिक विकल्प बचे भी नहीं थे। इसे उनके राजनीतिक कैरियर से समझा जा सकता है। कुशवाहा साल 2000 में पहली बार समता पार्टी से विधायक बने और 2004 में नेता प्रतिपक्ष बने। 2005 में नीतीश कुमार की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, पार्टी में घटते कद की वजह से अलग होकर एनसीपी में शामिल हो गए। 2009 में फिर से जेडीयू में वापसी की और राज्यसभा गए। 2013 में उन्होंने फिर से नीतीश के साथ अपने रास्ते जुदा कर लिए। 2013 में कुशवाहा ने अपनी खुद की पार्टी आरएलएसपी बनाई और 2014 में एनडीए में शामिल हो गए।

लोकसभा चुनाव 2014 में एनडीए से मिली तीनों सीटों पर जीत दर्ज की। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री रहे। वहीं, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23 सीटों में से केवल दो पर जीत हासिल कर सके। एनडीए में हाशिए पर जाने के बाद 2018 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन दोनों सीटें हार गए। 2020 में उन्होंने नया गठबंधन बनाया, लेकिन यहां भी हार मिली। पार्टी में टूट के आसार बनने लगे। इस स्थिति में जेडीयू में विलय के अलावा उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आ रहा था। विलय से ठीक पहले ही बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया था।

उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से अलग होकर और एनडीए में रहते हुए उनका विरोध कभी सफलता नहीं दिला सका। इसका असर बिहार की राजनीति में नीतीश और उपेंद्र दोनों पर ही पड़ा। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि कुशवाहा के पास भले ही विकल्प खत्म हो गए हों, लेकिन वो अब नीतीश की भी जरूरत बन गए हैं। फिलहाल इस जोड़ी के वापस आने से बिहार की राजनीति में नीतीश की सियासी हैसियत का मजबूत होना तय माना जा रहा है। हालांकि, उन्हें अपनी यह हैसियत दिखाने के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश और उपेंद्र की जोड़ी राजद के लिए चुनौती!

कुशवाहा के जदयू में आने के बाद नीतीश कुमार ने जहां उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, वहीं राज्यपाल कोटे से उन्हें बिहार में उच्च सदन का सदस्य भी बनवा दिया। वैसे, नीतीश और कुशवाहा के एक होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती राजद के लिए मानी जा रही है। आंकडों पर गौर करें तो राजग में उपेंद्र कुशवाहा, जदयू, भाजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहने के बाद राज्य में जातीय वोटबैंक का बड़ा हिस्सा राजग के साथ माना जा रहा है। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम पर गौर करें तो राजद सत्ता से मामूली अंतर से पिछड़ गई है। नीतीश कुशवाहा को अपने साथ लाकर लव-कुश (कुर्मी और कुशवाहा) समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं।

भारत का कवच

क्वाड ने चीन की दबंगई पर लगाया विराम

चीन की ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसी हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि बीते कुछ दशकों से दुनिया चीन की दबंगई देख चुकी है और विगत एक वर्ष में चीन का पूरा चरित्र दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। उसके बढ़ते दबदबे और दुस्साहस पर विराम लगाने के लिए क्वाड वही विचार है, जिसके साकार रूप लेने का समय अब आ गया है। अच्छी बात यह है कि इससे जुड़े अंशभागी भी यह भलीभांति समझ रहे हैं। उनके बीच बढ़ता सहयोग इसका सूचक है। इस प्रकार विगत एक वर्ष के घटनाक्रम ने क्वाड के उभार में निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि इससे जुड़े देशों को यह आभास हुआ कि चीन को उसकी भाषा में जवाब देना आवश्यक हो गया है। इस तरह कोरोनाकाल में नया आकार लेता वैश्विक ढांचा क्वाड की नियति में नाटकीय बदलाव का निमित्त बना। इन चारों देशों के साथ आने से अब बीजिंग के तेवर भी बदले हुए हैं। उसे समझ आ गया है कि जब दुनिया की बड़ी शक्तियां लामबंद होंगी तो उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? यही कारण है कि कुछ समय पहले तक क्वाड को लेकर आंखें तरेरने वाला चीन अब सहयोग और मित्रता की भाषा बोल रहा है।

बीते एक हजार साल से दुनिया में उतना बदलाव नहीं आया, जितना बीते 10 वर्षों में हुआ है। इसी तरह विगत एक वर्ष में दुनिया बदलाव के उससे भी बड़े दौर से गुजरी है, जितना पिछले 10 वर्षों के दौरान हुआ। क्वाड भी ऐसे परिवर्तनों का एक अहम पड़ाव और परिणाम है। यह 4 देशों का एक ऐसा उभरता हुआ समूह है, जो विस्तारवादी, बिगड़ैल और अड़ियल चीन को चुनौती देने का माद्दा रखता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी से बने इस समूह के राष्ट्राध्यक्षों ने गत दिनों अपने विचार साझा किए। मौजूदा दौर में यह घटनाक्रम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे उल्लेखनीय वैश्विक पहल कहा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि दोस्त क्या अब दुश्मन भी उसका लोहा मानने लगे हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने में असफल देश की विपक्षी पार्टियों को छोड़कर पूरी दुनिया हमारी इस उपलब्धि को स्वीकार भी कर रही है और सराह भी रही है। गत दिनों संपन्न क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन इसका ताजा उदाहरण है। इस सम्मेलन से स्पष्ट हो गया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों के जवाब में भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान ने 14 साल पहले जिस क्वाड का गठन किया था, वह अब अपने सामरिक महत्व से आगे बढ़कर आर्थिक जरूरत में बदल गया है और देखा जाए तो पिछले साल आई कोरोना महामारी ने भारत को पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना दिया है।

कोरोना से पहले भारत सहित क्वाड के सभी देश अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर थे। सिर्फ ये देश ही नहीं, बल्कि चीन तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर इतना हावी था कि वह पूरी दुनिया को सस्ते माल आपूर्ति का केंद्र बना हुआ था। अब भारत ग्लोबल फैक्ट्री बनकर उभर रहा है। जब पूरी दुनिया को पीपीई किट की आवश्यकता हुई तो एक भी किट नहीं बनाने वाला भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर सामने आया। आज हमारे पास प्रतिदिन 10 लाख पीपीई किट बनाने की क्षमता है। सिर्फ पीपीई किट ही क्यों, कोरोना की वैक्सीन से लेकर सिरिंज तक की वैश्विक आपूर्ति भारत से हो रही है। हाईड्रोक्लोरोक्वीन से लेकर वेंटीलेटर उत्पादन के मामले में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि निर्यात भी कर रहा है।

हाल में अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के निर्माण का ऑर्डर भारत की कंपनी को मिलना यह बताता है कि हमारे प्रति भरोसा बढ़ रहा है। इसमें दोराय नहीं है कि भारत की वैक्सीन कूटनीति ने उसे दोस्तों के साथ दुश्मनों का भी सम्मान दिलाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलावा भारत मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मामले में पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का नतीजा है कि एप्पल और सैमसंग जैसी चोटी के ब्रांड सहित दो दर्जन बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। मोदी सरकार के तहत खासकर रक्षा के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों ने दुनिया का विशेष ध्यान खींचा है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश और रक्षा उत्पादों की आयात सूची में कटौती के बाद से इस दिशा में खास प्रगति हुई है। हमारी वायुसेना ने देशी कंपनी को एकसाथ 83 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देकर यह साबित कर दिया कि हम पूरी दुनिया की सेनाओं को विश्वस्तरीय रक्षा निर्यात करने में सक्षम हैं। पिछले 5 साल के दौरान देश के रक्षा निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगले 4 साल में इसे 5 अरब डॉलर यानी 35 हजार करोड़ रुपए पर ले जाने का लक्ष्य है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत की इस बढ़ती ताकत में उन उद्यमियों का बड़ा हाथ है जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न यानी ऐसे उद्यम जिन्हें उन लोगों ने शुरू किया जिन्हें विरासत में पूंजी नहीं मिली थी। इन लोगों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर ऐसी कंपनियां खड़ी की हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। देश में कम से कम 100 ऐसी यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन एक अरब डॉलर यानी 73 अरब रुपए से ज्यादा है। इन कंपनियों में विदेशी निवेशक धड़ल्ले से पैसे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों में उन्हें भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। यह सब देश की विपक्षी पार्टियों को नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्हें सिर्फ विरोध करना है। इसलिए वे कहते हैं कि इस देश को सिर्फ दो उद्योगपति चला रहे हैं। दरअसल, उन्हें तो अपना ही जमाना याद है, जब चुनिंदा पूंजीपतियों की ही चलती थी। उन्हें ही प्रोजेक्ट भी मिलते थे और बैंकों से कर्ज भी। आज तो जिसके पास आइडिया है, वह यूनिकॉर्न है यानी भारत न सिर्फ एक मजबूत राजनीतिक लोकतंत्र है, बल्कि इसका आर्थिक तंत्र भी समानता के सिद्धांत पर ही चल रहा है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

गुलाबी लहर की वापसी

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने राजनीतिक मैदान में पूरी धमक के साथ अपनी वापसी की है। देश की सर्वोच्च अदालत के आश्चर्यचकित कर देने वाले फैसले के द्वारा उनकी ब्राजीली राजनीति के अग्रिम मोर्चे में वापसी हो सकी है, जिसमें घोषित किया गया है कि जिस भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के कारण 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में लूला को राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा से चुने जाने की दावेदारी का कत्ल कर दिया गया था, वह देश के इतिहास में सबसे बड़ा न्यायिक घोटाला था। गत दिनों लूला की ओर से एक प्रेरणादायी और संभावित ऐतिहासिक संबोधन को पेश किया गया, जिसे व्यापक तौर पर राष्ट्रपति पद की भिड़ंत में बोली लगाने की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। लूला ने धुर-दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जायेर बोल्सोनारो की कोरोनावायरस महामारी को लेकर की गई 'मूर्खतापूर्ण' एवं भौंड़ी कार्यवाहियों को लेकर जमकर लताड़ लगाई। कोविड संकट के **व्यापक स्तर को देखते** हुए बोल्सोनारो की अयोग्यता और इंकार वाले रुख की वजह से अभी तक लगभग 2,70,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से ब्राजीली राजनीति पहले से ही उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।

पिछले सप्ताहांत हुए एक सर्वेक्षण नतीजे में पता चला है कि बोल्सोनारो के लिए 38 प्रतिशत समर्थन की तुलना में ब्राजील के 50 प्रतिशत लोग अगले चुनावों में लूला के पक्ष में वोट कर सकते हैं या निश्चित तौर पर वोट करेंगे। इतना तो तय है कि लूला की पुनर्वापसी ने 2022 के चुनावों को तरंगित कर डाला है और तथाकथित 'गुलाबी लहर' और विषाक्त दक्षिणपंथी लोक-लुभावनवाद के बीच में एक प्रचंड संघर्ष का होना तय है। (इस गोलार्ध के सरकारों की ऐतिहासिक रूप से हार्ड-लाइन या 'लाल' वामपंथी आंदोलनों के विपरीत कहीं अधिक उदार नीतियों के साथ व्यापक लैटिन अमेरिकी नीतियों में वाम की ओर झुकाव की अभिव्यक्तियों को 'पिंक टाइड' बतौर चिन्हित किया जाता रहा है।)

निश्चित ही गरीबी के खिलाफ चलाए गए अभियान की वजह से लूला बेहद सम्माननीय व्यक्तित्व बने हुए हैं। बतौर राष्ट्रपति उनके 8 वर्षीय शासनकाल के दौरान ब्राजील ने जिन आर्थिक उछाल के आनंदमयी दिनों को देखा था, उन्हें आज अतीत की खुशनुमा यादों के तौर पर देखा जाता है। लूला ने चरम रुख न अपनाकर कहीं अधिक व्यवहारिक नजरिए के साथ अपने देश में गरीबी, असमानता और आर्थिक विकास की सतत चुनौतियों से निपटने में खुद को लगा रखा था। लूला के शानदार योगदान के बगैर ब्राजील का पश्चिमी गोलार्ध में एक क्षेत्रीय केंद्रक के बतौर उदय अधूरा ही रह जाता, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को रिकॉर्ड वृद्धि की राह पर ले जाने का काम किया था। इसका ही नतीजा था कि सामाजिक निवेशों के वित्तपोषण में मदद की गई, जिसने देश में चरम स्तर पर धन की असमानता को आधा कर दिया था। 2003 और 2013 के बीच ब्राजील का सकल घरेलू उत्पाद 64 प्रतिशत की दर से बढ़ा और गरीबी में जी रही आबादी का प्रतिशत आधा रह गया था। इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यय में तीव्र वृद्धि हुई, वहीं न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक अर्थों में बढ़ोत्तरी 75 प्रतिशत तक हो गई थी और हर वर्ष लाखों की संख्या में नए औपचारिक रोजगार सृजित हो रहे थे। अमेरिकी राजनीति में वामपंथ के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने हर्षोल्लास के साथ सक्रिय राजनीति में लूला की वापसी का स्वागत किया है। गत दिनों अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है 'राष्ट्रपति के तौर पर लूला ने ब्राजील में गरीबी को कम करने और श्रमिकों के समर्थन में खड़े होने का अतुलनीय काम किया था। उनके खिलाफ निहायत संदेहास्पद सजा को रद्द किया जाना एक बेहद शानदार खबर है। यह ब्राजील में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।'

सैंडर्स के सराहनापूर्ण शब्दों में एक दक्ष वामपंथी के ब्राजील की सत्ता में वापसी को लेकर किसी भी प्रकार की दुश्चिंता के भाव नजर नहीं आते, जो संभवतया लैटिन अमेरिका के तीन सबसे बड़े और सबसे अधिक प्रभावशाली देशों-ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको को 'गुलाबी लहर' की चपेट में ले सकता है। यह उस प्रकार की कूटनीति और राजनीति के बारे में काफी कुछ कहने के लिए पर्याप्त है, जिसको लेकर लूला से उम्मीद की जा सकती है कि वे राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज (अर्जेंटीना) और आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर (मैक्सिको) के साथ आगे बढ़ाएंगे। हालांकि फर्नांडीज और ओब्रेडोर, जो कि बौद्धिक तौर पर संपन्न हैं, की तुलना में लूला की औपचारिक शिक्षा नाममात्र की ही है। 10 वर्ष की उम्र तक उन्हें पढ़ना नहीं आता था और दूसरी कक्षा के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था, और अपने परिवार की मदद करने के लिए वे काम पर जाने लगे थे। 12 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया, और फिर फेरी लगाने का काम किया था। 14 साल के होने पर उन्हें एक गोदाम में औपचारिक काम मिल गया था।

● **कुमार विनोद**

ट्रेड यूनियन नेता से राष्ट्रपति तक का सफर

लूला राजनीति में बतौर एक ट्रेड यूनियन नेता बनकर उभरे थे, जिनकी ठोस मजदूर वर्ग वाली पृष्ठभूमि थी। लेकिन वर्कर्स पार्टी की स्थापना के दौरान प्रगतिशील विचारों के साथ एक वामपंथी रुझान वाली पार्टी के निर्माण का विचार, 1980 में ब्राजील के सैन्य शासन के दौरान जन्मा था, जिसके संचालन के केंद्र में यूनियन नेताओं का सलाहकार मंडल और शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों का एक समूह शामिल था। बतौर राष्ट्रपति लूला ने इक्वाडोर, बोलीविया और वेनेजुएला में होने वाली कहीं अधिक रेडिकल प्रक्रियाओं को अस्थिर करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व में चल रहे प्रयासों से बचाव के लिए फायरवाल सुरक्षाचक्र प्रदान करने का काम किया था। हालांकि ये देश उनके वैचारिक प्रक्षेपवक्र के हिसाब से नहीं चल रहे थे। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों के संघ और लातिनी अमेरिकी एवं कैरबियन राज्यों के समुदाय जैसी पहलकदमियों, जिसके जरिए इस क्षेत्र के वृहत्तर एकीकरण की चाह थी, को उनका भरपूर समर्थन हासिल था। इसके साथ समाजवाद के उनके अपने खास ब्रांड के साथ, विदेश-नीति में बदलाव का एजेंडा उनकी निगाह में अंतर्निहित था, जिसमें साम्राज्यवाद-विरोधी स्वर निकल रहे थे। इसकी वजह से उनके आंदोलन को अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान से विद्वेष का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर अमेरिकी-विरोधी स्वरों को बुलंद नहीं किया था। लूला इस बात को लेकर बेहद सचेत थे कि ब्राजील को पश्चिम के साथ व्यापार और निवेश और विशेषकर अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाने की सख्त आवश्यकता है।

लड़कियों को लेकर हमेशा यह बात उठती रहती है कि उनकी मॉडर्न और वेस्टर्न ड्रेस उनके साथ होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। क्या वाकई महिलाओं के कपड़े उनके साथ होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं या यह सिर्फ लोगों की गलत मानसिकता है, जवाब आप खुद तय कीजिए।

बेटियों के पहनावे पर नजर क्यों?

उत्तराखंड़ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। कई लड़कियों और महिलाओं को फटी जींस में देखा जा सकता है। एक एनजीओ चलाने वाली महिला घुटने पर फटी जींस पहनी थीं और कह रही थीं वे समाज सुधार करती हैं। ऐसी महिलाएं समाज सुधार क्या करेंगी। रावत के इस बयान के बाद देशभर में एक बार फिर से लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठने लगे हैं। रावत के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों के साथ ही फिल्मी दुनिया भी उतर गई है, और उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की बात कह रही है।

दरअसल, अक्सर हम लड़कियों या महिलाओं के पहनावे पर उसके चरित्र का आंकलन करते हैं। सड़क पर अगर कोई लड़की जाती हुई दिख जाए लोगों को सिर्फ दो मिनट लगता है यह बताने में कि लड़की का कैरेक्टर क्या है। अगर लड़की ने लोगों की सोच के हिसाब से कपड़े पहने हों तब तो ठीक है वरना उसी 2 मिनट में उसके कैरेक्टर का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। लोग लड़कियों को उनके पहने गए कपड़ों के हिसाब से जज करते हैं। जबकि सूट या साड़ी पहनने वाली महिलाएं भी अपराध कर सकती हैं। कोई इंसान कैसा है इसका पता उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से लगता है। गांव की ज्यादातर लड़कियां तो सूट और सलवार पहनती हैं फिर उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं।

समाज की इसी सोच की वजह से कई मां-बाप अपने बच्चियों को उनके मन मुताबिक कपड़े नहीं पहनने देते। मेरे ख्याल से महिलाओं को वे परिधान पहनने चाहिए जिसमें वे कंफर्टेबल हों। किसी ऑफिस में कोई महिला जितना कंफर्टेबल जींस-कुर्ता, सूट में होगी उतना साड़ी में नहीं। यहां तो सूट भी पहनो तो भी लोगों की नजर दुपट्टे पर होती है। दुपट्टा लगाया की नहीं और अगर लगाया भी है तो गले में है या पूरे शरीर पर लपेटा हुआ। अब जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र को ही ले लीजिए, इनको देखकर कहां लगता है कि ये अपनी बेटियों को सलवार सूट में देखना पसंद करते होंगे। हेमा मालिनी की बायोग्राफी में एक चैप्टर पूरा ईशा देओल के ऊपर है। इसमें ईशा ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अभी तक दुनिया को पता नहीं थीं। ईशा के अनुसार धर्मेंद्र रोज हेमा मालिनी और बेटियों से मिलने जाते थे और एक टाइम का खाना भी साथ खाते थे, लेकिन उनका रुकना बहुत कम हो पाता था। धर्मेंद्र रात में बहुत कम रूकते थे। साथ ही ईशा ने इस बात को भी स्वीकारा है कि उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रही।

वहीं हेमा मालिनी के अनुसार, धर्मेंद्र को अपनी बेटियों को वेस्टर्न ड्रेस में देखना खास पसंद नहीं था। यही वजह थी कि जब भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी और दोनों बेटियों ईशा और अहाना से मिलने घर आते थे तो दोनों उनके डर की वजह से सूट पहन लेती थीं। भले ही धर्मेंद्र को वेस्टर्न ड्रेस से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी लेकिन पिता की पसंद और नापसंद को तो लड़कियां समझ गईं थीं। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करें, इसलिए उन्होंने ईशा से 6 महीने तक बात भी नहीं की थी। अब इस बारे में क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल तो पहले से ही फिल्म के हीरो थे। हालांकि ईशा को अभिनय करते देखने के बाद उन्होंने बाद में तारीफ की थी।

गौरतलब है कि आज भी घरों में लोग भले ही कितने मॉडर्न होने का दिखावा करें लेकिन लड़कियों के मामले में उनकी सोच दोहरी होती है। लड़के भी तो उल्टे-सीधे कपड़े पहनते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन घर की बेटी क्या पहन रही है इस पर सबको टोकना होता है। शादी के बाद बहू बनते ही उस लड़की के पहनावे पर उसका छोड़कर बाकी पूरे ससुराल वालों का हक होता है। कहा यह जाता है कि यह रिवाज है करना तो पड़ेगा।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

कितनी ऊंची हो ड्रेस

कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि ठीक है तुम्हारा मन है तो पहनो जो तुम चाहती हो, लेकिन कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे लोग फिर यह मापते हैं कि स्कर्ट की लंबाई घुटने से कितनी छोटी होनी चाहिए। अगर मॉडर्न ड्रेस है तो वह घुटने के कितना ऊपर है। मतलब यह है कि अगर कोई महिला मॉडर्न ड्रेस पहनती भी है तो नियम और शर्तों के साथ। स्लीवलेस ड्रेस है तो बाजू की लंबाई कितनी बड़ी है और गला कितना गहरा है। कई पति तो पत्नियों को पहवाने के मामले में इतना डराकर रखते हैं कि वे चाहते हुए भी अपने हिसाब से कपड़े नहीं खरीदतीं, क्योंकि हमारे यहां कपड़ों की ऊंचाई से कैरेक्टर मापा जाता है। हमेशा इसी बात को लेकर विवाद होता है कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। छेड़खानी और बलात्कार के लिए अक्सर लड़कियों की ड्रेस को जिम्मेदार माना जाता है। लोगों को यब बात समझनी चाहिए कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपना कंफर्ट होता है। आज भी भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहां जींस और वेस्टर्न ड्रेस पर बैन है। लड़कियों को दब्बू और शालीन बनाने से कहीं बेहतर है बोल्ड और स्ट्रांग बनाना ताकि जब उन्हें कोई छेड़ने की सोचे तो उसी रूप में जवाब भी पाए। और हां, फैशनेबल ड्रेस का मतलब खराब चरित्र नहीं होता।

शिव-पार्वती के गुण से सफल होगी गृहस्थी

शिव परिवार में सबको साथ लेकर चलने की सोच देखी जाती है। शिव के परिवार में भूत-पिशाच, देव-दानव-गण सभी शामिल हैं। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों और खुशियों का मिलन ही जीवन को सुखी बनाता है। इसके अलावा समाज और प्रकृति को भी साथ लेकर चलने की सीख मिलती है, जिससे आज के समय में लोग दूरी बना रहे हैं।

शिव को गृहस्थों का देवता कहा जाता है। लड़कियां महाशिवरात्रि के दिन व्रत करके मनचाहे जीवनसाथी की कामना करती हैं। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जीवन को सफल बनाने के लिए जोड़े मां पार्वती और भगवान शंकर को आदर्श मानते हैं। अगर कपल अपनी जिंदगी में शिव-पार्वती के गुण उतार लें तो उनकी गृहस्थी सफल हो जाती है। आज के समय में बिखरते रिश्तों को और ज्यादा संभालने की जरूरत है। समय कितना भी क्यों ना बदल जाए, पति-पत्नी के रूप में शिव-पार्वती की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती।

पति-पत्नी को यह समझना होगा कि उनका साथ और उनकी समझ ही उनके रिश्ते का आधार है। शंकर-पार्वती की सात्विक जोड़ी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शिव और पार्वती दोनों ही एक-दूसरे की शक्ति हैं। मां गौरा को यूं ही शिव की अर्धांगिनी नहीं कहा जाता है। सिर्फ सुख-सुविधा, इच्छाओं को पूरा करना और भागमभाग जिंदगी में सहूलियत जुटाना ही जिंदगी को सुखी नहीं बनाता। महादेव के परिवार की जिंदगी बहुत सरल है, इससे प्रेरणा लेकर रिश्तों में संतुलन और प्रेम बनाकर चलने से जिंदगी आसान हो सकती है।

शिव परिवार में सबको साथ लेकर चलने की सोच देखी जाती है। शिव के परिवार में भूत-पिशाच, देव-दानव-गण सभी शामिल हैं। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों और खुशियों का मिलन ही जीवन को सुखी बनाता है। इसके अलावा समाज और प्रकृति को भी साथ लेकर चलने की सीख मिलती है, जिससे आज के समय में लोग दूरी बना रहे हैं। भगवान शिव को आदर्श मुखिया माना जाता है, जिनसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आपको शिव-पार्वती की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल कर आप भी दांपत्य जीवन का सुख ले सकते हैं और पति-पत्नी अपने बीच प्रेम को बढ़ा सकते हैं।

सरल प्रेम: शिव का प्रेम सरल व सहज है और उन लोगों के लिए सीख है जो शादी के समय खूबसूरती और पैसा को प्राथमिकता देते हैं। शिव के प्रेम में समर्पण के साथ सम्मान भी है। शिव प्रथम पुरुष हैं फिर भी उनमें मेल ईगो नहीं है। सती के पिता दक्ष ने शिव को न्यौता नहीं दिया फिर भी उन्होंने सती के मायके जाने के फैसले का सम्मान किया और अपने दांपत्य जीवन में कड़वाहट नहीं आने दिया। शिव और शक्ति कई बार अलग हुए लेकिन एक-दूसरे को ढूंढकर अपनी संपूर्णता को पाया। शिव ने सिखाया कि प्रेम में आधा बंटकर भी कैसे वे संपूर्ण हो गए। वहीं मां पार्वती ने भस्मधारी, गले में सर्प की माला वाले शिव को पसंद करके लोगों को यह सीख दी कि प्रेम में बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता। गृहस्थ जीवन में पैसा और खूबसूरती नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण जरूरी है।

समानता है जरूरी: महादेव को यूं नहीं अर्धनारीश्वर कहा गया है। इसका मतलब है कि भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री रूप में रहता है। इस बात से कपल को सीख लेनी चाहिए कि भले ही पति-पत्नी शरीर से दो होते हैं लेकिन उनका मन एक होना चाहिए। आज के समय में कई जोड़े इस बात पर लड़ते हैं कि दोनों में से किसका ओहदा बड़ा है, जबकि शिव-पार्वती यह सिखाते हैं कि पति-पत्नी दोनों एक हैं।

रिश्ते में ईमानदारी: आज के समय में बहुत कम रिश्तों में ईमानदारी देखने को मिलती है। जिसकी वजह से कलह और तलाक तक की नौबत आ जाती है। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति भोले जैसा सीधा और प्यार करने वाला मिले। जो उसकी बात सुने और उसका सम्मान करे। भगनाव शिव, पार्वती से कितना प्रेम करते थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मां पार्वती, शिव के अपमान से दुखी होकर सती हो गईं थीं तो उन्होंने रौद्र रूप धारण करके दुनिया का विनाश करना शुरू कर दिया था। इस बात से कपल को सीख मिलती है कि पति-पत्नी को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

आदर्श मुखिया: भगवान शिव को एक आदर्श मुखिया के रूप में जाना जाता है। जो अपने परिवार को एक साथ रखते हैं। आज के समय में अलग-अलग विचार ही पति-पत्नी के बीच कलह की वजह बन जाती है। भगवान शिव के गले में सांप की माला है जो उनके पुत्र गणेश के वाहन चूहे का शत्रु माना जाता है। वहीं भगवान शिव का वाहन बैल है और माता पार्वती का वाहन शेर है। ये दोनों भी एक-दूसरे के शत्रु हैं लेकिन सब मिलकर रहते हैं, इनमें कोई बैर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, हमें शिव की तरह अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। अगर ये बातें जोड़े अपने जीवन में शामिल करते हैं तो उनकी गृहस्थी भी शिव-पार्वती की तरह सफल हो सकती है।

● **ओम**

मेरा मुन्ना आएगा

घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल पसरा है। आज सावित्री की बेटी नीना का विवाह जो है। सावित्री एक कोने में चुपचाप उदास मन बैठी कुछ सोच रही थी कि अब उसकी नीना कुछ पल की मेहमान है, फिर तो पराई हो जाएगी। इससे कई गुना ज्यादा अपने बेटे मुन्ना की बातें उसे अंदर-ही-अंदर खाए जा रही थी। मुन्ना पहले कहा करता था अपनी मां से कि तुम इन चारों बेटियों को इतना मत पढ़ाओ। एमए, बीएड या कंप्यूटर कोर्स मत करवाओ। वैसे भी ये तो दूसरे के घर जाएगी, पढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। और भी कई बातों से सावित्री का दिल मुन्ना से उचट गया था। तभी बाहर से आवाज आती है - 'सावित्री बुआ बारात चौखट तक आ गई है।' फिर सभी रस्मों-रिवाजों से नीना की शादी हो गई। सवेरा होते ही नीना ससुराल चल गई।

कुछ दिन बाद सावित्री के घर में फिर वैसा ही कोहराम मचा हुआ था। मुन्ना का कहना था कि अब इन तीनों को मत पढ़ाओ। जितना पढ़ना था, पढ़ ली। इनकी भी अब शादी करा दो। किंतु सावित्री का कहना था कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चे को जहां तक हो पाएगा वहां तक पढ़ाएंगे। वैसे वो मुन्ना से कुछ नहीं कहती, बस सुनकर आंसू बहा लेती थी। सावित्री और मिट्ठूदास दोनों पति-पत्नी ने मेहनत कर अपनी तीनों बेटियों और बेटे को पढ़ाया। कर्ज लेकर तीनों बेटियों की शादी की। शादी में लिए कर्ज दोनों पति-पत्नी ने पाई-पाई चुका भी दिए ताकि कल को मुन्ना पर कहीं कोई बोझ ना रह जाए। किंतु मुन्ना अलग ही किस्म का लड़का था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा- 'आप लोगों ने मेरे लिए क्या रख रखा है? सारा धन-दौलत तो उन बेटियों पर लुटा दिया।' बात-ही- बात में मुन्ना ने अपने पिता पर हाथ भी उठा दिया और कहा- 'तुम दोनों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। तुम दोनों अभी के अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर निकल दूंगा।' मुन्ना सावित्री और मिट्ठूदास को धकियाते-घसीटते वृद्धआश्रम छोड़ आया। लेकिन जब मुन्ना आने लगा तो सावित्री भरे आंखों मे आंसू लिए बोली- 'बेटा... अपना ख्याल रखना।' लेकिन मुन्ना ने उन लोगों को पलटकर भी नहीं देखा। आज तक सावित्री इस इंतजार मे बैठी है कि उसका बेटा उसे लेने जरूर आएगा। मिट्ठूदास ने जहां इसे अपनी नियति समझ मौन धारण कर लिया है, वहीं सावित्री पथराई आंखों से बाहर देखते अचानक बोल उठती है- 'मेरा मुन्ना आएगा।'

- राज कुमारी

हम नए सपने सजाने चल दिए

चंद सपने मर गए तो क्या हुआ,
हम नए सपने सजाने चल दिए।
हर तरफ पतझार है तो क्या हुआ,
हम बसंती गीत गाने चल दिए।
लक्ष्य पथ चलते रहो, हारो नहीं।
भीरु होकर, चाह को मारो नहीं।
अब तुम्हें केशव जगाएंगे नहीं,
पार्थ! तुम तूणीर धनु डारो नहीं।
शकुनियों की भीड़ को तुम रोक लो!
वो नया चौपड़ सजाने चल दिए।
चंद सपने मर गए...
हर जगह आसीन घन-आनंद है।
अहं है सत्ता का, सो मतिमंद है।
क्या करें विद्वान ऐसे राज्य में,
राह प्रतिभा की सकल दिशि बंद है।
घूंट पी अपमान का, कुछ प्रण किया,
चंद्रगुप्तों को बनाने चल दिए।
चंद सपने मर गए तो...
हवाओं की कोशिशें पुरजोर थीं।
दीप की सांसे बहुत कमजोर थीं।
कांपती लौ ने न माना हार को,
लड़ाई तम से बड़ी घनघोर थी।
तुम दिवाकर को बुझा सकते नहीं,
तिमिर को हम ये बताने चल दिए।
चंद सपने मर गए तो क्या हुआ...

- डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी

डर के आगे जीत

भाभी की जचगी पर खुशी भाभी के मायके आई थी। कुछ दिनों से नन्हीं के साथ खेलने के बहाने भाभी के कमरे में ही सो जाती थी।

आज भइया आए तो लाचारी में खुशी को दूसरे कमरे में सोना पड़ा।

वह परेशान हो रही थी। दिलोदिमाग में मची हलचल में रिश्तों की अहमियत उसे कुछ भी गलत करने से हर बार रोक लेती थी।

चाहकर भी भाभी के छोटे भाई की गंदी नजरों एवं हरकतों के बारे में किसी से भी खुलकर बोल नहीं पा रही थी।

आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी, तभी खिड़की से कूद कर किसी को अपने बेड तक आते देखा।

'खुशी कब तक तुम हमें तड़पाओगी? एक बार गले लगकर हमारी प्यास बुझा दो।'

खुशी मानों इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह साये से लिपटते हुए जोड़ से उसकी बांहों में अपने दांत गड़ा दी।

आह, ऊफ्फ... मर गया कहते हुए वह भागने लगा।

'बुजदिल कायर कमीने, हिम्मत है तो घरवालों को इस जंगली बिल्ली के पंजे से परिचय करवाओ।'

लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही वह साया 'नौ दो ग्यारह' हो गया। अपने फैसले पर गर्व कर मुस्कुरा उठी। डर के आगे जीत है, पापा अक्सर कहा करते हैं।

- आरती रॉय

'आलसी' लड़की का 'नजीर' बन जाना!

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के दौरान लखनऊ में मिताली ने ये रिकॉर्ड बनाया है। 'लेडी सचिन' के नाम से मशहूर 38 साल की ये क्रिकेटर ऐसा कारनामा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन चुकी है। इंग्लैंड की शॉरलॉट एडवर्ड्स पहले स्थान पर हैं। मिताली अब तक 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। साल 2005 के वर्ल्ड कप में वह पहली बार टीम की कप्तान बनी थीं, तब भारतीय टीम उप विजेता रही थी।

बहुत कम लोग जानते हैं कि मिताली राज ने बचपन से क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में तो वह भरतनाट्यम में पारंगत हो गई थीं। लेकिन बचपन से बहुत आलसी थीं, इसीलिए वायुसेना में वारंट अधिकारी उनके पिता ने उन्हें सक्रिय बनाए रखने के लिए डांस के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग भी दिलानी शुरू कर दी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनको डांस और क्रिकेट में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने क्रिकेट को गले लगाया। आज मिताली महिला क्रिकेट टीम की पहचान हैं। बहुत लोगों को तो मिताली के आने के बाद पता चला कि महिला क्रिकेट टीम भी अच्छा खेल सकती है।

मिताली के पिता दोराय राज ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'मिताली बहुत आलसी थी। सुबह बहुत देर से जागती थी। उसे एक्टिव बनाने के लिए मैं बेटे के साथ उसे भी ग्राउंड पर ले जाने लगा। वहां कभी-कभी प्लास्टिक और टेनिस बॉल फेंकने के लिए कहता था। उस समय वहां कोच ज्योति प्रसाद थे। मिताली की गेंदबाजी देख उन्हें एक हफ्ते के लिए ट्रायल पर रख लिया। एक दिन उन्होंने कहा कि इस लड़की में टैलेंट है। आप इसे प्रॉपर क्रिकेट कैंप में भेजिए। इसके बाद स्कूली लड़कियों को क्रिकेट की कोचिंग देने वाले संपत कुमार उसके कोच बन गए। फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास है।'

तमाम संघर्षों, विवादों और उतार-चढ़ाव के बाद आज मिताली राज वर्ल्ड क्रिकेट में नजीर बन चुकी हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। वह एक दिवसीय मैचों में लगातार सात अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। मिताली से आगे पाकिस्तान के जावेद मियांदाद एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार 9 अर्धशतक बनाए हैं। वह एकमात्र ऐसी क्रिकेटर हैं (पुरुष या महिला), जिन्होंने एक से अधिक आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम की कप्तानी की है। उन्होंने साल 2017 और 2005 में दो बार ऐसा किया है। वह पहली भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 1000 से अधिक रन बनाए हैं।

क्रिकेट को पुरुषों का खेल माना जाता है। इस खेल के बड़े रिकॉर्ड्स अधिकांशत: पुरुष खिलाड़ियों के नाम पर होते रहे हैं। लेकिन मिताली राज जैसी क्रिकेटर ने इस मिथक को तोड़ दिया है। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर देश का नाम रौशन किया है। उन्होंने कई रिकॉर्ड ऐसे बनाए हैं, जो पुरुष क्रिकेटर उनके बाद बना पाए हैं। 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली राज शुरुआती दिनों में जब अपनी किट लेकर खेलने जाती, तो लोग यही समझते कि वे हॉकी प्लेयर हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते थे कि लड़कियों की क्रिकेट टीम होगी।

साल 2003 में 'अर्जुन अवार्ड' और साल 2015 में 'पद्मश्री' से सम्मानित मिताली राज ने महज 17 साल की उम्र में वर्ल्ड क्रिकेट में अपना कैरियर शुरू कर दिया था। साल 1999 में मिल्टन केन्स में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें नाबाद 114 रन बनाए थे। साल 2002 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। अपने तीसरे टेस्ट मैच में मिताली ने 214 रन बनाकर कैरण रोल्टन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में आज तक का यह सर्वाधिक स्कोर का कीर्तिमान है। उन्होंने 10 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 663 रन बनाए हैं।

कहते हैं जब कोई इंसान बुलंदियों पर होता है, तो उसके साथ कई बार अनावश्यक विवाद होते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मिताली राज के साथ भी हुआ। साल 2018 में उनका अपनी टीम के तत्कालीन कोच रमेश पवार और कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ एक मैच को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मिताली को उस साल आयोजित टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच से बाहर कर दिया गया। मिताली ने बीसीसीआई को कोच और सीओए के खिलाफ लेटर लिख दिया। यह विवाद लंबा खिंचा, लेकिन बाद में रमेश पवार को कोच पद से हटा दिया गया और मिताली की टीम में वापसी हो गई।

● आशीष नेमा

यूं ही कोई महान खिलाड़ी नहीं बन जाता!

कुछ खिलाड़ी 'मुंह' चलाने की जगह 'हाथ' चलाना पसंद करते हैं। जो महान होते हैं, वो कभी अपनी आलोचनाओं पर पलटवार नहीं करते, बल्कि अपने खेल से यह साबित कर देते हैं कि वो सच में महान हैं। क्रिकेट की ही बात करें तो महान क्रिकेटर की संज्ञा धारण करने वाले सचिन तेंदुलकर हों या महेंद्र सिंह धोनी, हर बार आलोचना का जवाब इन दोनों ने अपने बल्ले से दिया। जब रिटायरमेंट की बात हुई, तब दोनों ने शतक जड़ दिया। आलोचकों का मुंह खुद बंद हो जाता। कुछ ऐसा ही मिताली का भी हाल है। हाल ही में उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई थीं, लेकिन इसी बीच रनों का पहाड़ खड़ा करके, अनोखा रिकार्ड बनाकर मिताली ने रिटायरमेंट की चर्चा करने वालों के मुंह बंद कर दिए।

कंगना को डॉक्टर बनाना चाहते थे उनके पिता, सालों तक नहीं की थी बात

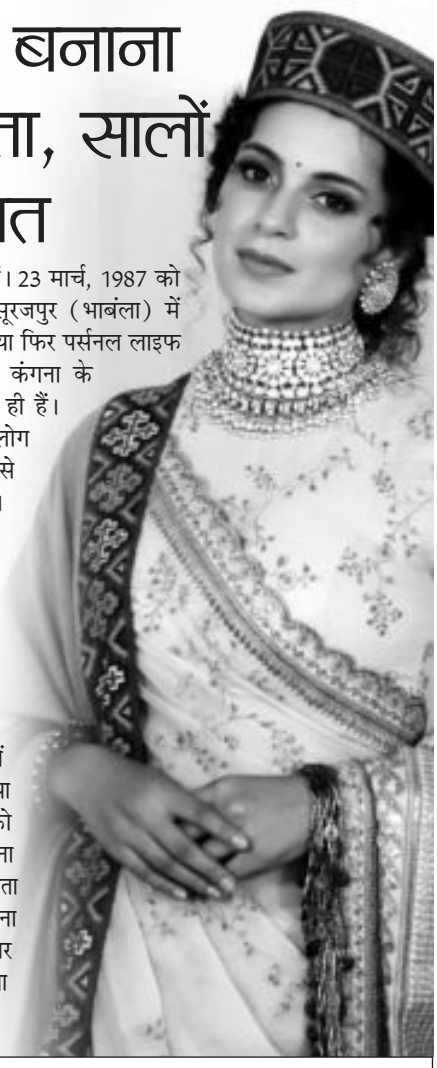

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट 34 साल की हो गई हैं। 23 मार्च, 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पास स्थित सूरजपुर (भाबंला) में जन्मी कंगना अपने बड़बोलेपन, एक्टिंग स्किल्स या फिर पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वैसे तो कंगना के फिल्मी कैरियर से जुड़ी बातें उनके फैन्स जानते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं, जिन्हें शायद ज्यादातर लोग न जानते हों। कंगना के पिता अमरदीप रनोट पेशे से बिजनेसमैन हैं, वो बेटी को डॉक्टर बनाने चाहते थे। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में कराया था। डीएवी स्कूल में कंगना को मेडिकल की किताबों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसे रैंप पर चलना ज्यादा पसंद आता था। स्कूल में फेयरवेल हो या फ्रेशर कंगना के बिना कोई भी फंक्शन अधूरा रहता था। डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश सचदेवा कहती हैं कि कंगना उस वक्त से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी रखती थी। स्कूल में फ्रेशर्स नाइट हो या फेयरवेल, कंगना मॉडलिंग जरूर करती थी। कंगना को मॉडलिंग इतना पसंद आने लगी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और हॉस्टल से पीजी में शिफ्ट हो गईं। पिता अमरदीप को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने कंगना की पिटाई भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के घर से भागने और फिल्मों में काम करने की वजह से कंगना के पिता ने उनसे सालों तक बात नहीं की थी।

दादाजी हुए थे नाराज... कंगना ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने की बात अपने पिता से की थी, तो वे बहुत नाराज हुए थे। यहां तक कि उन्हें घर से निकल जाने को कहा था। वे अभिनय में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी और इसीलिए वे बिनी कोई पैसा लिए घर से निकल गई थीं। जब उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर उनके दादाजी ने देखी, तो बहुत नाराज हुए थे और अपने नाम के साथ लगा सरनेम तक हटाने को कह दिया था। इसकी वजह यह थी कि फिल्म में उन्होंने किसिंग सीन दिया था। खैर कंगना आज बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बना चुकी है और बेहतरीन अभिनय कर रही है।

इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना हर किसी के लिए मुश्किलः सूरज पंचोली

बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। लोग इस मुद्दे पर कहते हैं कि स्टार किड्स को फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा मौके दिए जाते हैं और आउसाइडर्स को किनारा कर दिया जाता है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में सूरज पंचोली ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है। लेकिन, स्टार किड्स के लिए सोशल मीडिया के इस युग में नफरत से निपटने की अतिरिक्त चुनौती भी होती है। सूरज का कहना है कि जब लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें भी नेपोटिज्म का फायदा मिला है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। सूरज पंचोली ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह किसी के लिए आसान है। बेस्ट एक्टर ही इस इंडस्ट्री में टिक पाएगा, बाकी नहीं टिक पाएंगे। यह सबसे बेस्ट फैमिली के सबसे अच्छे लोगों के साथ भी हुआ है। नेपोटिज्म टैग से कभी-कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। सूरज एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। सूरज ने आगे कहा, इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही है। कुछ फिल्म फैमिली के लोगों को नापसंद किया जाता है। इसलिए यह बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर हर कोई अब एक आलोचक है और नफरत एक सेकंड में फैल सकती है। स्टार किड्स के लिए सोशल मीडिया के युग में नफरत से निपटना एक अतिरिक्त चुनौती है।

सेट पर बदसलूकी करने वाले डायरेक्टर का नाम सामने न ला पाने का पछतावा है, मैं बहुत डर गई थीः प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक अवार्ड विनिंग टॉक शो सुपर सोल पर ओपरा विनफ्रे के साथ इंटरव्यू किया। वो अपनी दोस्त मेघन मार्कल के बाद इस टॉक शो पर आई थीं और शो में उन्होंने उन कई घटनाओं के बारे में बताया जहां डायरेक्टर्स ने उनके साथ गंदा व्यवहार किया था। प्रियंका ने एक बड़ी स्टार बनने से पहले इंडिया में काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में उनसे ऐसे डांस प्रफोर्मेंसेज देने को कहा जाता था जिसमें वे काफी अनकम्फर्टेबल फील करती थीं। उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाओं के लिए डायरेक्टर्स के सामने अवाज ना उठा पाने के लिए मैं आज भी पछताती हूं। प्रियंका ने कहा, मैं हमेशा उन बातों के लिए ओपीनियन रखती हूं जिनसे मैं सहमत नहीं होती। मुझे बचपन से ही अवाज उठाने के लिए एनकरेज किया गया है। वह अभी भी पछताती हैं कि वो उन डायरेक्टर्स को सामने नहीं ला पाईं और कहने लगीं, मैं बहुत डर गई थी।

जमीनी कार्यकर्ता का शिकायती पत्र

यह दुनिया की रीति है। हर बड़ा चाहता है कि उससे छोटा कोई भी कदम उठाने से पहले उससे सलाह-मशविरा जरूर कर लिया करे। सरकारी सेवा में तो थ्रू प्रॉपर चैनल के विरुद्ध चलना आचरण नियमावली के प्रतिकूल माना जाता है।

किसी राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता अर्से से अपने आप को उपेक्षित अनुभव कर रहा था। जब पानी नाक तक पहुंच गया और उसका दम घुटने लग गया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पहला काम यह किया कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष को एक पत्र लिख भेजा। नीचे से ऊपर तक खलबली मच गई, क्योंकि जिसे वह पत्र बता रहा था, वह वास्तव में शिकायती पत्र था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एक साथ उस पर झपट पड़े। एक सीनियर नेता, जो आलाकमान की नाक के बाल भी कहे जाते थे, उस कार्यकर्ता को हड़काते हुए बोले, 'तुमने यह पत्र क्यों लिखा? लिखने से पहले मुझसे परामर्श कर लेना चाहिए था। अध्यक्ष जी को बहुत बुरा लगा है। तुम पर अनुशासनहीनता की कारवाई होनी तय समझो।'

यह दुनिया की रीति है। हर बड़ा चाहता है कि उससे छोटा कोई भी कदम उठाने से पहले उससे सलाह-मशविरा जरूर कर लिया करे। सरकारी सेवा में तो थ्रू प्रॉपर चैनल के विरुद्ध चलना आचरण नियमावली के प्रतिकूल माना जाता है। यदि किसी अधीनस्थ कर्मचारी को अपनी बात कहनी होती है तो इसके लिए उचित माध्यम का अनुपालन करना होता है।

एक बार किसी दफ्तर में आग लग गई। चूंकि आग बाहर लगी हुई थी, इसलिए उसे सबसे पहले साहब के कमरे के बाहर बैठने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मी ने देखा। वह बारी-बारी साहब और फिर बड़े साहब को मोबाइल मिलाता रहा, लेकिन दौरे पर निकले साहब लोगों का फोन नहीं उठा। दिक्कत यह थी कि उनके आदेश के बिना किसी भी बाहरी संस्था से न तो सीधे संपर्क किया जा सकता था और न ही उसे बुलाया जा सकता था। इसी उधेड़बुन में आधा दफ्तर जल गया। राजनीति का क्षेत्र भी कुछ-कुछ ऐसी ही नौकरशाही जैसा हो चला है। चाहे पूरी पार्टी का सत्यानाश हो जाए, आग लग जाए, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता को अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए भी कुछ बीच वालों की अनुमति लेनी होती है।

वह साधारण कार्यकर्ता पहले से ही चिढ़ा बैठा था। उसकी पार्टी में सुनी नहीं जा रही थी। लिहाजा उसने वरिष्ठ नेता से ही पलट कर सवाल कर दिया, 'मैं पत्र क्यों नहीं लिख सकता? क्या पत्र व्यवहार के लिए भी आप जैसे लोगों की परमीशन चाहिए!' उस वरिष्ठ नेता ने कार्यकर्ता की शिकायत को घुमाकर सीधा संविधान के हवाले कर दिया कि हां, चाहिए। पार्टी का संविधान तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। कार्यकर्ता ने प्रतिप्रश्न किया, 'कहां है पार्टी का संविधान। मैंने तो कभी देखा नहीं। यहां तो सब कुछ ऊपर-ऊपर तय हो जाता है। आज दशकों बीत गए। अपनी पार्टी में एक चुनाव तक नहीं हुआ। इसीलिए हम हर चुनाव हार जाते हैं।'

इस पर वरिष्ठ नेता ने उसे डपटते हुए कहा, 'ज्यादा न बोलो। अगर पार्टी में बने रहना है तो अपने मुंह पर ताला लगाना सीखो। साधारण कार्यकर्ता हो तो उस जैसा ही आचरण करना भी सीखो। तुम्हारे एक पत्र लिख देने से तुम्हें कोई अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना देगा।'

फिर कार्यकर्ता ने संवेदना भरी चाल चली, 'और मुझे बनना भी नहीं है। मैं ऐसे ऊंचे सपने नहीं देखता। मुझको पार्टी के अतीत और इतिहास से खानदानी लगाव है। मेरी पांच पीढ़ियों ने इस पार्टी की सेवा की है। मैं नहीं चाहता कि इतनी पुरानी पार्टी एक इतिहास बनकर रह जाए।'

वरिष्ठ नेता पर इस दांव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, 'तुम जैसों की यही तो दिक्कत है। अपनी ही गाते रहते हो। तुम्हारी पांच पीढ़ियों ने पार्टी की सेवा की है तो अध्यक्ष जी की छह पीढ़ियों ने। तुम्हें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो कोई और रास्ता देखो।' कार्यकर्ता बोला, 'देख चुका हूं। हर दल की एक ही कहानी है।' नेता ने कहा, 'अब सही रास्ते पर आए हो। यही आज की राजनीति का सच है। इसलिए ज्यादा पत्र-वत्र लिखने के फेर में न पड़ो।'

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

Science House Medicals Pvt.Ltd.
Celebrating
25
YEARS EXPERIENCE
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023 GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5
Email : shbpl@rediffmail.com PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

KARTAR

SINCE 1975

किसान का विश्वास
हमारा असली संकल्प

Devendra Chouksey

आपकी उपज के
एक-एक
दाने का रक्षक

098264-89053
081093-55536

KARTAR 4000

LUDHIANA AGRO SALES

New Bypass Road, Near Meena Chouraha Acharpura Jodh, Bhopal (M.P.)

Email : kartar.bhopal@gmail.com Website : www.kartarharvestar.com

Spl. Kartar & All Combinee Spare Parts Available

Auth. Dealer : Kartar Agro Industries (P) Ltd.

देशभर के किसानों की पहली पसंद करतार 4000 नॉन एसी हार्वेस्टर